R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• शोपीस बनने लगे उज्ज्वला सिलेंडर • गिद्ध और घड़ियाल स्टेट बनेगा मप्र

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

न माया मिली और न राम

वर्ष 19, अंक-9 1 से 15 फरवरी 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

तिरंगे का अपमान

कौन जिम्मेदार...?

हमारे किसान
हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

किसानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास

- कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। अधोसंरचना विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि मिशन का गठन।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ किसान कल्याण योजना में प्रदेश के किसानों को ₹ 4000 प्रति वर्ष देने का निर्णय। प्रदेश के 78 लाख पात्र किसानों को लगभग ₹ 3200 करोड़ की राशि का भुगतान होगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुल ₹ 8646 करोड़ का भुगतान।
- 16 लाख किसानों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन, ₹ 27000 करोड़ से अधिक का भुगतान।
- पिछले 8 माह में 2 करोड़ 10 लाख किसानों को विभिन्न योजनाओं में ₹ 46000 करोड़ से अधिक का भुगतान।
- उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण।
- पिछले 8 माह में लगभग ₹ 8000 करोड़ से अधिक की 7सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति।
- 2002-03 में प्रदेश का कुल सिंचित रकबा मात्र 7 लाख 50 हज़ार हेक्टेयर था, जिसे 15 साल में बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर तक कर दिया।
- 15 वर्षों में सिंचाई बजट ₹ 1005 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10,928 करोड़ किया गया।
- तीन वर्षों में 1000 नये "कृषि उत्पादक संगठन" का होगा गठन।
- शून्य ब्याज दर पर ऋण योजना वर्ष 2020-21 में पुनः प्रारंभ।
- मंडी नियमों में ऐतिहासिक सुधार। मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर 0.5% किया गया।
- सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ₹ 800 करोड़ जारी।

"किसान मेरे लिये भगवान हैं,
हम उनकी सेवा में
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

- शिवराज सिंह चौहान

सशक्त किसान, समृद्ध खेती, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

इस अंक में

सम्मान

9 | मप्र को 6 साल बाद वीरता पदक

मप्र पुलिस की गिनती देश की सबसे कर्तव्यनिष्ठ और जांबाज पुलिस में होती है। चंबल को दस्युमुक्त करने वाली मप्र पुलिस के अधिकारी और जवान समय-समय पर अपने कर्तव्य का जांबाजी से पालन करते हुए...

राजपथ

10-11 | नए चेहरों की युवा टीम

मप्र भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मप्र भाजपा की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी को उम्मीदों की टीम माना जा रहा है। लंबे समय बाद नए चेहरों वाली एक युवा टीम तैयार है।

योजना

12 | नई पोषण नीति

मप्र में नवजात से लेकर 6 महीने तक के करीब 70 हजार बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया है। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है।

महंगाई

14 | इस बार जोर से लगेगा करंट

मप्र में उपचुनाव जीतने के बाद से ही बिजली आम उपभोक्ताओं को झटके पर झटके दे रही है। दो प्रतिशत महंगी हो चुकी बिजली की दरों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की तैयारी है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

26 जनवरी को महापर्व गणतंत्र और तिरंगे का जिस तरह अपमान हुआ, वह बर्दाश्त से बाहर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल उन्मादियों ने जिस तरह का उपद्रव किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गणतंत्र और तिरंगे के अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है? किसान, पुलिस या फिर सरकार? जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इससे देश की साख गिरी है और भारतीय गणतंत्र पर दाग भी लग गया है।

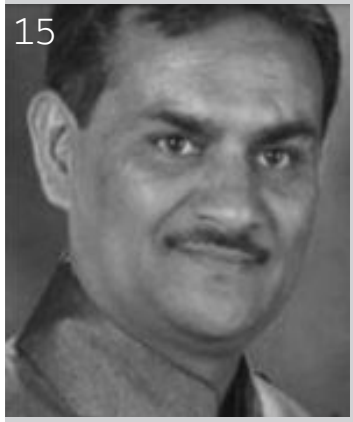

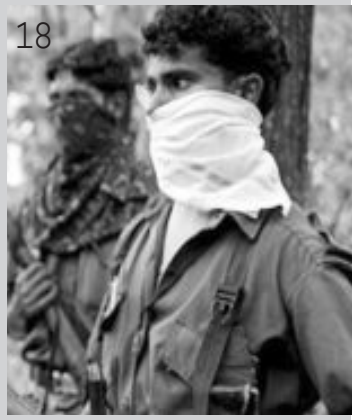

राजनीति

30-31 | उबरने का आखिरी मौका!

देश का सबसे पुराना सियासी दल कांग्रेस यदि पलटकर वर्ष 2020 के घटनाक्रम और पार्टी की गति को देखे तो कुछ खास हासिल नहीं है। विद्रोह की सुगबुगाहट ने गांधी परिवार का सुकून जरूर कम किया होगा। पूरे साल की समीक्षा संकेत मिलेंगे कि नए साल 2021 में उसे नई जागृति के साथ...

राजस्थान

35 | भाजपा में बड़ा चेहरा कौन?

राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राज्य भाजपा में बड़ा चेहरा कौन है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट के घमासान पर चुटकियां लेने वाली भाजपा के लिए अपने घर में चल रहे इस घमासान...

उप्र

37 | 'मोदी मैन' ने बढ़ाई दिग्गजों की बेचैनी

उप्र की राजनीति में हुई एक शख्स की एंट्री के बाद से यहां की सियासत में बेचैनी अचानक से बढ़ गई है। यही नहीं उप्र के भाजपा नेताओं में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई है। इसका कारण है उप्र की राजनीति में 'मोदी मैन या मोदी वाले...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

हर–हर नर्मदे... घर–घर शराब

कवि विनोद बक्सरी की एक कविता की पंक्तियां हैं...

शराब और शराबी से नफरत है मुझे... मैं पीता नहीं हूं, वो पिलाती है मुझे।
मैं तो उसका कोई नहीं... पर, वो अपने जिस्म की चादर बताती है मुझे।।

कुछ ऐसी ही स्थिति मप्र की है। मप्र की सरकार शराब से नफरत करती है। शराब से सरकार की नफरत का आलम यह है कि अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में सरकार ने नर्मदा किनारे शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया था जो अभी भी बरकरार है। सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए यात्रा निकालकर नारा दिया था कि हर-हर नर्मदे, घर-घर नर्मदे। सरकार के इस कदम की सर्वत्र सराहना हुई थी। लेकिन कर्ज और कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही सरकार ने कमाई के लिए घर-घर शराब भेजने की योजना बनाई है। सरकार की इस योजना की खबर जैसे ही फैली, लोगों के मुंह से नारा निकला- अब तो हर-हर नर्मदे, घर-घर शराब। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब उस सरकार में हो रहा है जो सरकार एक दशक से कसम खा रही है कि प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं बढ़ने देगी। दरअसल, शराब की बिक्री प्रदेश सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी है। आर्थिक बदहाली के इस दौर में सरकार इस मुर्गी को मार भी नहीं सकती है। इसलिए सरकार ने योजना बनाई है कि इस मुर्गी से जितना हो सके उतना सोने का अंडा निकाला जाए। इसके लिए नई आबकारी नीति में ऑनलाइन ऑर्डर पर शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान लाने का विचार किया जा रहा है। बीते महीनों में उज्जैन-मुरैना में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत होने से उपजे सियासी बवाल के बीच राज्य सरकार वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव किया गया है यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल भी अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल यह ड्राफ्ट वाणिज्यिक कर व आबकारी मंत्री के पास पहुंच चुका है। यहां से मंजूरी के बाद इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। बता दें कि नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसलिए सरकार अभी से इस तैयारी में लगी हुई है कि शराब की बिक्री से किस तरह अधिक से अधिक कमाई की जा सके। गौरतलब है कि शराब की बिक्री प्रदेश सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। 2019-20 में अप्रैल-दिसंबर में 7845.19 करोड़ रुपए आए थे। इस साल इसी दरमियान की कमाई 6593.48 करोड़ हो गई। विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मार्च तक पिछले साल के बराबर ही 9300 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार पर कर्ज का जो भार आया है उसकी भरपाई के लिए ऐसी नीति बनाई जाए ताकि भार को कम किया जा सके। इसी के तहत सरकार की कोशिश है कि घर-घर शराब की डिलीवरी का प्रावधान लाया जाए। आबकारी नीति में इस प्रावधान को शामिल किया जाता है या नहीं यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सरकार के कदम की अभी से आलोचना होने लगी है। विपक्ष के नेता कहने लगे हैं कि नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली पार्टी की सरकार इस तरह के कदम उठाएगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
लेकिन आगे देखिए यह सरकार और क्या-क्या अनैतिक कदम उठाती है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 9, पृष्ठ-48, 1 से 15 फरवरी, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलंटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

टीम वीडी से सीख

भाजपा की नई कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार नए चेहरों को मौका दिया गया है, उससे अन्य पार्टियों को सीख लेना चाहिए। टीम वीडी में सक्रिय नेताओं को तव्वजों दी गई है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भाजपा युवा नेताओं को ही तवज्जो देगी।

● **अनिल पांडे,** भोपाल (म.प्र.)

रेत खनन पर दें ध्यान

मप्र आज भले ही बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया है, लेकिन अवैध तरीके से रेत खनन की बीमारी ने राज्य को इस तरह ग्रसित कर लिया है कि हर साल सरकार को अरबों रुपए की चपत लगी है। प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

● **अखिलेश चौहान,** सीहोर (म.प्र.)

प्रदेश में ही रहें कमलनाथ

कमलनाथ को मप्र में रहकर ही कांग्रेस का संकटमोचक बने रहना चाहिए। प्रदेश में अभी कांग्रेस कमजोर है, इसलिए उसे मजबूत करने के लिए कमलनाथ को यहीं पर रहकर और अधिक प्रयास करने चाहिए। वे भोपाल में बैठकर भी केंद्रीय नेतृत्व के लिए काम कर सकते हैं।

● **प्रिया सूर्यवंशी,** ग्वालियर (म.प्र.)

पश्चिम बंगाल में भाजपा हो रही मजबूत

भाजपा केंद्र में काबिज होने के साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में सत्तापक्ष में है। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा को अगर भगवा लहराना है तो उसे ममता बनर्जी की पार्टी से सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में यह लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर और असम के बाद चौथे स्थान पर है। राज्य के तीन जिलों में मुसलमान बहुमत में हैं। भाजपा ने ममता की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति को मुद्दा बना लिया है। इस आधार पर भाजपा ने ममता और टीएमसी को हिंदू विरोधी तक करार दे दिया है। टीएमसी इस मुद्दे पर मुखर होने के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में आ रही है।

● **प्रदीप मालवीय,** जबलपुर (म.प्र.)

कमजोर हो रहा विपक्ष

2014 से लगातार हाशिये पर खिसकती जा रही कांग्रेस पार्टी अब अपनी पहचान खोती जा रही है। देखा जाए तो एक सर्वमान्य और सक्षम नेतृत्व का अभाव आज विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है। कांग्रेस राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बनाने की असफल कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली है। अब खुद पार्टी के ही कई नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि या तो परिवारवाद जिंदा रह सकता है या फिर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी परिवार का झंडा उठाने वालों की संख्या ही अधिक है।

● **नीतेश रावत,** राजगढ़ (म.प्र.)

मेट्रो प्रोजेक्ट को गति

प्रदेश में मेट्रो ट्रेन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों ही दल नगरीय निकाय चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में लगे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोनाकाल में करीब 10 महीने से बंद पड़े काम को आनन-फानन में शुरू करा दिया गया है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा बापट चौराहा से विजय नगर के बीच एमआर-10 के बीचों बीच बिजली की हाईटेंशन लाइन है। इंदौर में धीमी पड़ी गति को जल्द रफ्तार मिले।

● **सोनम शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

शह-मात का खेल

राजस्थान में भाजपा के भीतर गुटबाजी और छत्रपों की आपसी कलह स्तर पर है। सत्ता की भूख से व्याकुल नेता कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार से लड़ने के बजाय आपस में ही उलझे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिशें कर रहा है उनका विरोधी गुट। ताजा विवाद गहलोत सरकार के एक मंत्री परसादी लाल मीणा के दौसा में दिए एक बयान से उभरा है। उन्होंने फरमाया कि राजस्थान में वसुंधरा के बिना भाजपा उसी तरह शून्य है जिस तरह अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस। भाजपा वसुंधरा की अनदेखी करेगी तो अपना ही नुकसान करेगी। इससे भाजपा खेमे से प्रतिक्रिया होती ही। हालांकि पहल भाजपा की तरफ से ही हुई थी जिन्होंने 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का मान-सम्मान नहीं करने की बात कही थी। कांग्रेस के मंत्री का पलटवार भाजपाई सह न पाए। भाजपा के भीतर अब मुख्यमंत्री पद की वसुंधरा इकलौती दावेदार नहीं हैं। सूबेदार सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी दलित के नाते मुख्यमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं। यह महत्वाकांक्षा तो तब है जबकि ज्यादातर फैसले दिल्ली से आलाकमान कर रहा है। सतीश पूनिया के समर्थक तो व्हाट्सऐप पर ग्रुप बनाकर उनके पक्ष में मुहिम चला रहे हैं।

कुनबे का असंतोष

17 महीने के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो जरूर कर लिया पर उससे विधायकों में असंतोष घटने के बजाय और बढ़ गया लग रहा है। यतनाल उपनाम से चर्चित बीजापुर शहर के विधायक बीआर पाटिल तो मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं वे पर अब येदियुरप्पा राज्य में भी मंत्री बनाने को तैयार नहीं। पाटिल ने येदियुरप्पा पर प्रधानमंत्री की सराहना के बहाने फिर हमला बोल दिया। फरमाया कि प्रधानमंत्री का सपना है विकास। वंशवाद की राजनीति का खात्मा और भ्रष्टचार मुक्त सरकार। फिर उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से गुहार लगाई कि भाजपा में एक परिवार के एक सदस्य को ही राजनीति में पद मिले। उन्होंने 75 की उम्र पार कर चुके लोगों को पद न देने की नीति को भी सराहा। येदियुरप्पा पर इन दिनों वंशवाद के आरोप भाजपा वाले ही लगा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हैं तो एक बेटा सांसद। दूसरा बेटा प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बना है। भाजपा आलाकमान येदियुरप्पा से मुक्ति तो चाहते हैं पर उनकी पुख्ता सियासी जमीन को देख उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।

भाजपा के हाथों में

उत्तराखंड में सत्ता का ख्वाब देख रहे कांग्रेसी गुटबाजी में मशगूल हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पार्टी के सूबेदार प्रीतम सिंह दोनों को ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फूटी आंखों नहीं सुहाते। पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने भी गुटबाजी छिप न सकी। वे दो दिन के दौरे पर आए थे। इंदिरा हृदयेश के क्षेत्र हल्द्वानी में रावत समर्थकों ने यादव की मौजूदगी में ही जमकर हंगामा किया। देहरादून में पार्टी की सभा हुई तो उसमें भी हरीश रावत गैरहाजिर रहे। किसी भी बैनर-पोस्टर पर अपना नाम और तस्वीर न देख हरीश रावत तमतमाए हुए थे। यादव ने भी उनकी अनदेखी की। यादव के वापस जाते ही हरीश रावत ने आलाकमान से मांग कर डाली कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले ही घोषित करे पार्टी। उनके समर्थकों ने तो इसके लिए उन्हीं का नाम भी सुझा दिया। इससे खफा इंदिरा हृदयेश ने याद दिलाया कि पिछले चुनाव में रावत को ही मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था। सत्ता तो गंवाई ही, दो सीटों से लड़कर भी रावत सदन में नहीं पहुंच पाए। पार्टी 70 में से 11 सीटों पर सिमट गई। विरोधी खेमा रावत पर गुटबाजी कर परोक्ष रूप से भाजपा के हाथों में खेलने का आरोप लगा रहा है।

दीदी नहीं अब पीशी

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वाक युद्ध नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होने के साथ ही अपनी पूर्व नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा शब्दों के बाण चलाने में जुट गए हैं। ममता बनर्जी को सभी दीदी कह कर पुकारते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जनसभाओं में उन्हें 'पीशी' यानी आंटी कहना शुरू कर दिया है। वहीं ममता के भतीजे अभिषेक भी निशाने पर हैं। उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप ममता विरोधी लगाते रहे हैं। पहले भाजपा ने अभिषेक को 'भाईपो' कह पुकारना शुरू किया था। भाईपो का तात्पर्य भाई का बेटा यानी भतीजा से है। अब लेकिन उनका भी दूसरा नामकरण कर दिया गया है। उन्हें 'बाबूसोहना' कहा जाने लगा है। बाबूसोहना से तात्पर्य ममता आंटी के लाडला होने से है। अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लेने की भाजपाई रणनीति के खासे फायदेमंद होने की खबरें आ रही हैं।

गुस्से में कुमारस्वामी

कर्नाटक के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके कुमारस्वामी इन दिनों खासे नाराज और चिड़चिड़े हो चले हैं। जानकारों का दावा है कि कुमारस्वामी नाराज इसलिए है कि तमाम कोशिशें करने के बाद भी वे मुख्यमंत्री की गद्दी बचा नहीं पाए। उनकी नाराजगी अपने पिता से भी है जिन्होंने उन्हें भाजपा के बजाय कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर किया था। पिछले दिनों कुमारस्वामी तब मीडिया पर भड़क उठे जब पत्रकारों ने उनसे एक धोखाधड़ी के मामले में कर्नाटक की क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ के लिए बुलाई गई कन्नड़ अभिनेत्री राधिका की बाबत प्रश्न पूछ डाले। नाराज कुमारस्वामी ने उत्तर में चिड़चिड़ा कर कह डाला कौन राधिका? वे किसी राधिका को नहीं जानते। उनका उत्तर सुन पत्रकार हैरान रह गए। दरअसल राधिका पूर्व मुख्यमंत्री की दूसरी पत्नी हैं जिनसे उन्हें एक संतान भी है। कुमारस्वामी का कौन राधिका कहना, सुनते है उनकी इस दूसरी पत्नी को खासा नागवार गुजरा है।

मंत्रीजी की मायागिरी

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे। लेकिन देश में इन दिनों ऐसी परिपाटी चल पड़ी है कि कोई व्यक्ति जिस बात पर जोर देता है, उसमें गिरी शब्द जोड़ दिया जाता है। मप्र में इन दिनों एक मंत्रीजी का पूरा फोकस माया (पैसा कमाने) पर है। मंत्रीजी का भाग्य भी ऐसा है कि लक्ष्मीजी खुद उन पर कृपा बरसाती दिख रही हैं। लेकिन इससे भी मंत्रीजी की लालसा पूरी नहीं हो रही है और उन्होंने मायागिरी शुरू कर दी है। दरअसल, मंत्रीजी के पास प्रदेश का सबसे कमाऊ विभाग है। उनका भाग्य इतना अच्छा है कि वे जब अपनी पूर्व पार्टी में मंत्री थे तब भी उन्हें यह विभाग मिला था और वर्तमान पार्टी में भी दूसरी बार उन्हें यही विभाग मिला है। यानी मंत्रीजी के चारों तरफ लक्ष्मीजी की कृपा बरस रही है। लेकिन फिर भी मंत्रीजी की प्यास नहीं बुझ रही है। इसका आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्रीजी ने अपने बेड़े में शामिल वाहनों में अपनी खुद की इनोवा लगा ली है। गौरतलब है कि मंत्रीजी जिस विभाग में मंत्री हैं वह विभाग मंत्रियों के यहां वाहन अटैच करता है। इसके लिए ट्रेवल्स एजेंसियों से टेंडर बुलाए जाते हैं। लेकिन मंत्रीजी ने विभाग की ओर से अपने पास खुद की गाड़ी लगवा ली है। मंत्रीजी ऐसा करके खुश हैं कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो।

कोई झेलने को तैयार नहीं

लोकतंत्र में प्रशासन को शासन का चेहरा माना जाता है। इसलिए सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि वह फ्रंट पर ऐसे अफसरों को रखे, जिनकी कार्यप्रणाली बेहतर हो और जो गण और तंत्र के साथ सामंजस्य बैठाकर काम कर सके। अगर मप्र की बात करें तो यहां पुलिस विभाग में कुछ ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें झेलने को कोई तैयार नहीं होता है। इसलिए इन अफसरों को कभी भी ऐसी पोस्टिंग नहीं मिलती है, जिससे जनता का जुड़ाव होता है। ऐसे तीन स्पेशल डीजी लेवल के अफसरों की चर्चा इन दिनों प्रशासनिक वीथिका में खूब हो रही है। इन अफसरों में एक साहब 1986, एक 1987 और एक 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वैसे तो तीन अफसर अपने आपको ईमानदार और तेज तर्रार मानते हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली हमेशा विवादों में रहती है। यानी सरकार की ओर से इन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, वे उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। हाल के वर्षों में ये तीनों अफसर किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में रहे। प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर है कि इन तीनों वरिष्ठ अफसरों की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी रही है कि जरूरत के बाद भी सरकार इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से कतराती है। खासकर उन पदों पर इन्हें नहीं बैठाया जाता है, जिनका जनता से सीधा जुड़ाव रहता है। दरअसल, ये अफसर साहबगिरी के शिकार हैं, इसलिए इन्हें कोई झेलने को तैयार नहीं होता है।

घर का भेदी

प्रदेश की राजनीति में दमदार और वजनदार हैसियत रखने वाले मंत्रीजी की स्थिति इन दिनों पहाड़ के नीचे ऊंट वाली हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर मंत्रीजी के साथ उनके गृहजिले में जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल, गणतंत्र दिवस पर मंत्रीजी अपने गृहजिले में झंडावंदन करने पहुंचे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्रीजी की अगवानी के लिए कलेक्टर और एसपी का होना जरूरी था। लेकिन कार्यक्रम स्थल पर कलेक्टर, एसपी की कौन कहे अदना सा अफसर भी मौजूद नहीं रहा। आलम यह रहा कि अफसरों के इंतजार में मंत्रीजी को एक खानसामा से देर तक बतियाना पड़ा। जब मंत्रीजी की आवभगत करने कोई अफसर नहीं पहुंचा तो मंत्रीजी भी आगबबूला हो उठे। उन्होंने आव देखा न ताव और एसडीओ तथा ईई को निलंबित कर दिया। लेकिन कलेक्टर और एसपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार मंत्रीजी ने कलेक्टर और एसपी पर चुप्पी क्यों साध ली है?

ऐसी जल्दबाजी क्यों?

मप्र की प्रशासनिक वीथिका में इस समय अजब सा माहौल है। आलम यह है कि कर्तव्यनिष्ठ अफसर असमंजस के घेरे में हैं। इसकी वजह यह है कि कब, किसको, कहां भेज दिया जाए किसी को पता नहीं। गत दिनों ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब एक विभाग में प्रमुख के रहते उनकी जगह दूसरे साहब को पदस्थ कर दिया गया। दरअसल, उक्त साहब दिल्ली जाने के मूड में हैं। इसकी वजह यह है कि साहब जिस विभाग में हैं, उस विभाग में उनका मन नहीं लग रहा है। साहब की मंशा को भांपते हुए बड़े साहब ने कहा कि आजकल आपका मन नहीं लग रहा है तो साहब ने साफ-साफ शब्दों में कहा था कि अच्छा होगा कि आप मुझे टीआरआई भेज दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साहब अभी विभाग में काम संभाले हुए हैं कि उनकी जगह एक दूसरे साहब को भेज दिया गया। इस तबादले को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी जल्दबाजी क्यों की गई। इसको लेकर प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इससे बड़े साहब की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है।

समय का फेर

समय बड़ा बलवान होता है। समय कब किसको फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर ला दे यह कोई नहीं जानता। इन दिनों एक माननीय का समय ऐसा बदला है कि अच्छे-अच्छे तुर्रम खां भी उनके आगे बिछे पड़े हैं। ग्वालियर-चंबल अंचल से निकलकर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों छाए इन माननीय का जलवा कुछ इस कदर कायम है कि लोग उन्हें सत्ता का सानिध्य पाने की सीढ़ी समझने लगे हैं। इसलिए आए दिन उनके बंगले पर कारोबारियों और धनाढ्यों की भीड़ देखी जा सकती है। माननीय जब राजधानी में रहते हैं तो उनका जलवा देखने लायक होता है। उनके इंतजार में लोग घंटों कुर्सी तोड़ने को मजबूर होते हैं। गत दिनों तो एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो गया। दरअसल, कुछ साल पहले तक माननीय जिनके पास चंदा के लिए घंटों बैठा करते थे, अब वे चंदा देने वाले कारोबारी माननीय के दरबार में इंतजार करते पाए जाते हैं। बताया जाता है कि उक्त कारोबारी पर सरकार की तिरछी नजर है। कभी प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में सम्माननीय रहे उक्त कारोबारी की दिशा और दशा इन दिनों खराब चल रही है। उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में वे इस उम्मीद के साथ फरियाद लेकर माननीय के पास पहुंचे थे कि वे अपने पुराने दिन याद कर इनकी सहायता करेंगे। माननीय ने उनकी सहायता की या नहीं यह तो पता नहीं लेकिन उनको इंतजार करता देख हर कोई हैरान जरूर हुआ।

राजनीति के भंवर में मैं फंसना नहीं चाहता। एक तो मेरा स्वास्थ्य खराब है, ऊपर से राजनीति का स्तर गिर रहा है। अत: मैं राजनीति में उतरे बिना ही जनता के लिए काम करता रहूंगा। राजनीति से दूर रहकर भी जनसेवा की जा सकती है।

● **रजनीकांत**

आम आदमी पार्टी 6 राज्यों उप्र, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगले 2 वर्षों में चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने यह फैसला इसलिए लिया है कि देशभर में प्रत्येक गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा है। लोग चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंचे। अत: पार्टी ने निर्णय लिया है कि लोगों तक पहुंचने के लिए हम आगामी चुनाव लड़ेंगे।

● **अरविंद केजरीवाल**

विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में फर्क है। कप्तानी के मामले में विराट कोहली रहाणे के मुकाबले ज्यादा एक्प्रेसिव और कम्युनिकेट करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे काफी शांत और सुलझे हुए हैं। दोनों की कप्तानी में खेलने का अनुभव मुझे मिला है। दोनों का लक्ष्य भारतीय टीम को जिताने पर रहता है।

● **आर अश्विन**

नरेंद्र मोदी सरकार के धारा-370 को हटाने और सूबे को दो केंद्र शासित हिस्सों में बांटने के कदम को पलटने एक सियासी संघर्ष होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कानूनी लड़ाई। जम्मू-कश्मीर के लोगों को डराकर खामोश कर दिया गया है। अब सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं।

● **महबूबा मुफ्ती**

मेरे फैंस को इन दिनों मेरी शादी की चिंता है। आज भले ही मैं 35 साल की हो गई हूं, लेकिन अभी मैंने शादी के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। अभी मुझे एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। वैसे तो मैं 4 साल की उम्र से ही फिल्में कर रही हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी वह नहीं कर पाई हूं, जिसके लिए मैं बनी हूं। इसलिए मैं फैंस से कहना चाहती हूं कि अगर आने वाले समय में मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाती हूं, तो जल्द ही शादी कर लूंगी।

● **श्रुति हसन**

वाक्युद्ध

गणतंत्र दिवस पर सरकार ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की है वह घातक होगी। क्योंकि अब गांवों से लेकर शहरों तक आंदोलन फैलने लगा है। कांग्रेस किसानों के साथ है। सरकार को तीनों कृषि कानून हर हाल में वापस लेने ही पड़ेंगे। हम खेती-किसानी को बर्बाद होता नहीं देख सकते।

● **राहुल गांधी**

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान देश नहीं सहेगा। किसानों ने जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, वह अक्षम्य है। कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने किसानों को आक्रामक रैली निकालने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों ने कानून व्यवस्था को तार-तार किया।

● **जेपी नड्डा**

मप्र को 6 साल बाद वीरता पदक

मप्र पुलिस की गिनती देश की सबसे कर्तव्यनिष्ठ और जांबाज पुलिस में होती है। चंबल को दस्युमुक्त करने वाली मप्र पुलिस के अधिकारी और जवान समय-समय पर अपने कर्तव्य का जांबाजी से पालन करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में 2 पुलिस अधिकारियों डीआईजी अरविंद सक्सेना और सतना एसपी धरमवीर सिंह यादव ने वीरता पदक पाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

मप्र को 6 साल बाद वीरता पदक मिला है। यह वह पदक है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रतीक्षारत रहते हैं। गृह मंत्रालय ने इस साल पुलिस अवॉर्ड की जो घोषणा की है, उसमें मप्र के 16 पुलिस अफसरों का नाम हैं। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डीआईजी अरविंद सक्सेना और सतना एसपी धरमवीर सिंह यादव को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। दोनों पुलिस अफसरों को यह अवॉर्ड 4 साल पहले 31 मई 2017 को भोपाल में धर्मस्थल से जुड़े विवाद के चलते हुई घटना के बाद सौहार्द्र बनाने में अहम भूमिका अदा करने के लिए दिया जा रहा है। उस दौरान सक्सेना एसपी नॉर्थ भोपाल और धरमवीर एएसपी जोन-4 थे।

उल्लेखनीय है कि भोपाल के अलावा अरविंद सक्सेना जहां-जहां भी एसपी के तौर पर पदस्थ रहे हैं, वहां उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही माफिया और अपराधियों पर भी नकेल करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। वर्तमान समय में वे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं। उन्हें परिवहन विभाग में यह पदस्थापना एक चैलेंज के रूप में मिली थी। उसी दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला और विभाग के सामने राजस्व संग्रहण का संकट खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में सक्सेना ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीति बनाकर काम किया और आज परिवहन विभाग ने राजस्व के टारगेट को पूरा कर सरकार को बड़ी आर्थिक मदद दी है।

गृह मंत्रालय की सूची में वीरता पदक के लिए 2 पुलिस अफसरों के अलावा एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव समेत 4 अफसरों को विशिष्ट सेवा पदक और रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला समेत 10 अफसरों का सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया है। गृह मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए मप्र के राजेश कुमार राजपूत और हिमानी बीरवाल को अवॉर्ड दिया जाएगा। राजेश राजपूत को जीवन रक्षक और हिमानी बीरवाल को उत्तम जीवन रक्षक अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा पदक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, एडीजी, अजाक, संतोष उपाध्याय, डीएसपी, इंदौर, नरेंद्र कुमार गंडराडे, इंस्पेक्टर, पीएचक्यू, अजय तिर्की, इंस्पेक्टर, पीएचक्यू को दिया जाएगा। जबकि सराहनीय सेवा पदक मोनिका शुक्ला, एसपी, रायसेन, मनोज कुमार सिंह, एसपी, भिंड, राजेंद्र कुमार वर्मा, एसपी लोकायुक्त, रीवा, सभ्याची श्राफ, एसपी लोकायुक्त, इंदौर, जगदीश कुमार पवार, एएसपी, देवास, अमित सक्सेना, एसपी स्पेशल ब्रांच, भोपाल, जितेंद्र सिंह, एसपी साइबर सेल, इंदौर, लक्ष्मी कुशवाहा, डीएसपी ट्रेनिंग पीएचक्यू, भोपाल, सुरेंद्रपाल सिंह राठौर, डीएसपी ट्रेनिंग, उज्जैन, अलका शुक्ला, डीएसपी पीएचक्यू, भोपाल को मिलेगा।

वही पिछले वर्ष (2020) उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए मध्य प्रदेश के 41 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजी सम्मान के लिए चुना गया। डीजी सम्मान की सूची में भोपाल जोन के एडीजी उपेंद्र जैन, पुलिस मुख्यालय में एडीजी विवेक शर्मा, इंदौर जोन के आईजी हरिनारायणचारी मिश्र, भोपाल डीआईजी इरशाद वली, ग्वालियर एसपी अमित सांघी, इंदौर एएसपी प्रशांत चौबे, राजेश रघुवंशी, गुरुप्रसाद पाराशर, भोपाल एएसपी दिनेश कौशल, एएसपी विशेष शाखा भोपाल अमित सक्सेना, एसपी रेडियो नीतू ठाकुर, सीएसपी उज्जैन अश्विनी कुमार नेगी, डीएसपी देवास किरण कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर उज्जैन संजय मंडलोई, इंस्पेक्टर रीवा अनिमेश द्विवेदी, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा, संतोष कुमार शुक्ला, गोपाल सिंह गुरंग, वैशाली रामटेक, सुशील कुमार बारई, श्रीराम मिश्रा, प्रेमकुमार चौहान, लोकेंद्रपाल सिसोदिया, नरेश मालवीय, दिनेश कुमार यादव, योगेंद्र सिंह तोमर, सेवा सिंह तोमर, अजय कुमार वाजपेयी, धनराज सिंह उईके, रमेश चंद्र जाटव, अजमत खान, राकेश कुमार सिरवैया, सतीश कुमार यादव, रविशंकर पटेल, जितेंद्र सिंह राठौर, रविशंकर मुजाल्दे, कृष्णगोपाल शर्मा, हरप्रसाद पटेल, दौलत सिंह यादव, जगदीश नारायण शर्मा और मुकेश कुमार सिंह शामिल हैं।

● **सुनील सिंह**

अरविंद और धरमवीर ने लगा दी थी जान की बाजी

राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए सम्मानित किए जाने के लिए चुने गए डीआईजी अरविंद सक्सेना और सतना एसपी धरमवीर सिंह ने अमन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वाकया 30 मई 2017 का था जब भोपाल के हमीदिया में साम्प्रदायिक विवाद के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को संयम से कंट्रोल करने में तत्कालीन एसपी भोपाल नार्थ अरविंद सक्सेना के साथ धरमवीर सिंह यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त यादव एएसपी नार्थ थे। इन दोनों अफसर ने पीरगेट चौराहे पर हो रहे पथराव को कंट्रोल करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पीरगेट चौराहे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए एक पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी लाठी-डंडे लेकर सड़क पर आ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। डायल-100 समेत अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों को आग लगा दी गई थी। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किए। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। विकट स्थिति में दोनों अफसरों ने जिस तरह भीड़ को नियंत्रित किया, वह सराहनीय है। गौरतलब है कि अरविंद सक्सेना ने होशंगाबाद में अपनी पदस्थापना के दौरान रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध रेत खनन पर रोक लगा दी थी। वहीं सतना एसपी धरमवीर सिंह को 6 साल पहले भी वर्ष 2013 में इंडियन मुजाहिद्दीन और सिमी के आतंकवादियों को गिरफ्तार कर देश में सिमी के माड्यूल को समाप्त करने के कार्य में अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2015 में राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक भी एसपी धरमवीर सिंह हासिल कर चुके हैं।

प्रशिक्षण, खुफिया विभाग और फील्ड में अपना लोहा मनवाया है अमित सक्सेना ने

एएसपी विशेष शाखा भोपाल अमित सक्सेना को उनकी साहसिक और उल्लेखनीय सेवा के लिए सराहनीय सेवा पदक के साथ ही डीजी डिस्क के लिए चयनित किया गया है। सक्सेना ने नक्सल, प्रशिक्षण, खुफिया विभाग के साथ ही फील्ड में भी अपनी सेवा का लोहा मनवाया है। इस कारण उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें प्रदेश का सबसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी माना जाता है।

मप्र भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वह प्रयोगशाला है, जहां वह अपने नए-नए फॉर्मूले का परीक्षण करते हैं। फिर उसकी सफलता के बाद उसे देशभर में लागू किया जाता है। मप्र से परीक्षण के बाद निकले फॉर्मूले को आधार बनाकर भाजपा ने न केवल केंद्र में बल्कि वर्तमान समय में 17 राज्यों में अपनी सरकार स्थापित की है। अब एक बार फिर भाजपा ने मप्र में पीढ़ी परिवर्तन के फॉर्मूले का परीक्षण शुरू किया है और इसके तहत चौथी पीढ़ी (टीम वीडी) के हवाले संगठन को सौंप दिया है। भाजपा का यह प्रयोग मिशन 2023 और 2024 के लिए है।

नए चेहरों की युवा टीम

मप्र भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मप्र भाजपा की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी को उम्मीदों की टीम माना जा रहा है। लंबे समय बाद नए चेहरों वाली एक युवा टीम तैयार है। आने वाले वक्त में 2023 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए, लेकिन इस संतुलित कही जा रही टीम में सिंधिया समर्थकों को तरजीह नहीं दी गई है। इस बात पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए सिंधिया समर्थकों के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया। यहां तक कहा गया कि आगे-आगे देखिए कैसे सिंधिया हाशिए पर डाले जाते हैं। 30 सदस्यों वाली टीम के सामने चुनौतियां हजार हैं लेकिन फिलहाल क्या इस टीम को लेकर पार्टी के भीतर वाकई शांति है, संतुष्टि है ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में वीडी कहते हैं कि कांग्रेस अपने कुनबे की चिंता करे। भाजपा में सबकुछ सुनियोजित रणनीति के तहत होता है।

शर्मा की नवगठित टीम में पुराने जमे हुए लोगों में से सिर्फ चार को ही जगह मिली है। साफ है कि प्रदेश भाजपा की टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। टीम वीडी में सिंधिया समर्थकों में से केवल मदनलाल कुशवाह को जगह मिली, मंत्रिमंडल में भी इस वक्त सिंधिया समर्थक 9 विधायक मंत्री हैं। सिंधिया समर्थक 3 विधायक चुनाव हारने के बाद मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं और फिर से जगह बनाने की जुगत में हैं। संगठन में सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिलने से कांग्रेस को लगे हाथ एक मुद्दा मिल गया है। पिछले साल मार्च महीने में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन संभाला था, तो उनके साथ कई समर्थकों ने भी पाला बदला। मंत्रिमंडल विस्तार में तो सिंधिया को उनकी पूरी हिस्सेदारी मिली, लेकिन संगठन में उनकी भागीदारी नहीं दिखाई दी। आने वाले दिनों में अभी निगम-मंडल, प्राधिकरणों में नियुक्ति के अलावा नगरीय निकायों चुनावों में फिर से सिंधिया समर्थकों को मौका मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भाजपा अध्यक्ष खुद साफ कर चुके हैं कि पार्टी में अब कोई किसी का समर्थक नहीं है। जरूरत के मुताबिक सबका इस्तेमाल होगा।

गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले संघ और भाजपा ने चौथी पीढ़ी को संगठन की कसौटी पर कसने का फॉर्मूला बनाया था। जिसका परीक्षण करने के लिए 15 फरवरी 2020 को चौथी पीढ़ी के सबसे सक्रिय नेता वीडी शर्मा को मप्र भाजपा की कमान सौंपी गई। वीडी पार्टी के लिए भाग्यशाली साबित हुए और करीब सवा माह बाद ही भाजपा की पुनः सत्ता में वापसी हो गई। उसके बाद वीडी ने सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य का जो प्रदर्शन किया है, उससे प्रभावित होकर संघ और भाजपा ने पीढ़ी परिवर्तन का निर्णय लिया और चौथी पीढ़ी के हवाले मप्र को कर दिया। यानी मप्र भाजपा में चौथी पीढ़ी के नेताओं को प्रतिनिधित्व सौंपा गया।

गौरतलब है कि 15 साल के बाद दिसंबर 2018 में भाजपा के हाथ से सत्ता निकली तो संघ और भाजपा में

सक्रिय नेताओं को जगह

मप्र भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल सदस्यों को देखें तो ये वे नाम हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही है। इन्होंने मप्र की राजनीति में अपना मुकाम स्वयं बनाया और पाया है। यानी बिना गॉडफादर के उन्हें यह मुकाम मिला है। वर्तमान दौर में माना जाता है कि प्रभावशाली पिता या गॉडफादर के बिना राजनीति में जगह बनाना मुश्किल है। कई प्रतिभाशाली युवा राजनीति से जुड़ नहीं पा रहे हैं और जगह नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रभावशाली पिता या गॉडफादर नहीं हैं। हमारा देश 65 फीसदी युवाओं का देश है। देश के तमाम क्षेत्रों से आवाज उठ रही है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब अगर बात राजनीति की हो तब यह आवाज और भी मुखर हो जाती है। वर्तमान लोकसभा में युवा सांसदों की ठीक-ठाक संख्या को देखकर स्थिति निराशाजनक नहीं लगती। देश में युवा नेतृत्व पैदा हो रहा है। मगर ध्यान देने वाली बात है कि वह कहां से पैदा हो रहा है।

चिंता की लहर दौड़ पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाने के बाद भी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद संघ और भाजपा ने महसूस किया कि अकेला चना (शिवराज सिंह चौहान) भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए चौथी पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम शुरू हुआ और वीडी को मप्र भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से ही वीडी पर संगठन के गठन का दबाव पड़ने लगा लेकिन काफी सोच-विचार के बाद संघ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चौथी पीढ़ी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हरी झंडी दी। दरअसल, इसके पीछे संघ और भाजपा का फोकस विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 पर है।

13 जनवरी को वीडी ने मप्र भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा की, तो उससे 30 साल बाद पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की झलक दिखाई दी। इससे पहले स्व. सुंदरलाल पटवा भाजपा में नई पीढ़ी को लाए थे, जो अब तक सत्ता-संगठन में शीर्ष पदों पर हैं या थे। अब कार्यकारिणी में ज्यादातर नए चेहरों को जगह दी गई है। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले संघ ने अपने स्वयंसेवकों से मिले फीडबैक के बाद भाजपा को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके आधार पर ही मप्र भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी को आकार दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि स्वयंसेवकों द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अधिकतर युवाओं को टिकट दिया था। इस कारण कांग्रेस ने भाजपा से अधिक सीटें जीती थीं। इस रिपोर्ट के बाद से ही संघ और भाजपा में इस बात पर मंथन शुरू हो गया था कि पार्टी में अब चौथी पीढ़ी को आगे लाया जाए। भविष्य को देखते हुए सोची-समझी रणनीति के तहत भाजपा संगठन ने चौथी पीढ़ी के नेताओं को मुख्यधारा में लाने का कदम उठाया है। वीडी शर्मा ने लगभग 11 महीने बाद अपनी टीम बनाई है। जिसमें भौगोलिक, जातिगत, गुटीय संतुलन पर भी खास ध्यान दिया गया है। संगठन के पुराने पदाधिकारियों में सिर्फ जीतू जिराती और पंकज जोशी की ही वापसी हुई

है। महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष रहीं सीमा सिंह की दस साल बाद संगठन में वापसी हुई है। अब तक पदाधिकारी रहे रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी को पदोन्नत कर प्रदेश मंत्री बनाया है। वहीं, लोकेंद्र पाराशर को एक बार फिर प्रदेश मीडिया प्रभारी की बागडोर सौंपी गई है। पाराशर ऐसे पहले मीडिया प्रभारी हैं जिन पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और राकेश सिंह के बाद तीसरे प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी भरोसा जताया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र भाजपा की टीम का स्वरूप देखकर इस कदर प्रफुल्लित हैं कि पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह डाला कि भाजपा की टीम जोश और उमंग से भरी है लेकिन कमलनाथ-दिग्विजय की टीम घिसी-पीटी है। गौरतलब है कि वीडी शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी में कई ऐसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो इससे पूर्व कभी अधिक चर्चा में नहीं थे। बैतूल के वैभव पंवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा किसान मोर्चा-दर्शन सिंह चौधरी, महिला मोर्चा-माया नारोलिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा-भगत सिंह कुशवाह, अनुसूचित जाति मोर्चा- डॉ. कैलाश जाटव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा-कल सिंह भाबर और अल्पसंख्यक मोर्चा-रफत वारसी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष में अनुभवी चेहरों को महत्व दिया गया है। संध्या राय (सांसद) भिंड, मुकेश चौधरी भिंड, कांतदेव सिंह सिंगरौली, योगेश ताम्रकार सतना, सुमित्रा वाल्मिक जबलपुर, आलोक शर्मा भोपाल, सीमा सिंह भोपाल, जीतू जिराती इंदौर, गजेंद्र पटेल (सांसद) बड़वानी, बहादुर सिंह सोंधिया (विधायक) उज्जैन, चिंतामणि मालवीय उज्जैन, पंकज जोशी शाजापुर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उधर, जिन नेताओं को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, उनमें मदन कुशवाहा ग्वालियर, ललिता यादव छतरपुर, रजनीश अग्रवाल सागर, लता वानखेड़े सागर, प्रभुदयाल कुशवाह सागर, राजेश पाण्डेय रीवा, मनीषा सिंह (विधायक) शहडोल, आशीष दुबे जबलपुर, नंदिनी मरावी (विधायक) जबलपुर ग्रामीण, राहुल कोठारी भोपाल, संगीता सोनी झाबुआ और जयदीप पटेल धार का नाम शामिल है। इनके अलावा जबलपुर के अखिलेश जैन को प्रदेश कोषाध्यक्ष, उज्जैन के अनिल जैन कालूखेड़ा को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, भोपाल के राघवेंद्र शर्मा को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है।

● **कुमार राजेन्द्र**

मंडल से लेकर जिलों में युवा नेतृत्व

प्रदेश भाजपा के एक नेता का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक मप्र भाजपा पूरी तरह युवा हो जाएगी। इसकी तैयारी संगठन के गठन से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी युवा फैक्टर को प्राथमिकता दी है। पार्टी संगठन को सक्रिय करने के लिए युवा चेहरों को मौका दिया गया है। निष्क्रिय जिला व शहर अध्यक्षों को हटाकर उनके स्थान पर नई तैनाती की गई है। इसी फॉर्मूले पर मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। दरअसल, पार्टी की कोशिश यह है कि 2023 में होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वैसे तो मप्र विधानसभा चुनाव होने में अभी बहुत वक्त है लेकिन भाजपा अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। मिशन 2023 के लिए भाजपा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीहोर में भाजपा ने 2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी इसके संकेत दिए थे कि भाजपा में अब नया दौर शुरू होने वाला है। पार्टी अपने हर एक युवा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी से लैस करेगी। मुरलीधर राव का कहना है कि पार्टी अब कमजोर बूथ के लिए हर बूथ मजबूत अभियान चलाएगी।

नई पोषण नीति

मप्र में नवजात से लेकर 6 महीने तक के करीब 70 हजार बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया है। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1495 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। अब सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए नई नीति पर काम करेगी। विभाग ने राज्य पोषण नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया, इस तरह के सर्वे आमतौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सर्वे किया है। इसके अध्ययन के अनुसार करीब 10 लाख बच्चों पर किए गए सर्वे में सामने आया है, अधिकांश क्षेत्रों में गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चे पाए गए हैं। मध्यम कुपोषण वाले बच्चों की संख्या करीब 3 लाख 50 हजार हैं। वहीं, 70 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों में से 6 हजार को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक तिहाई से अधिक बच्चे त्वचा और हड्डी रोग से भी पीड़ित हैं।

केंद्र सरकार ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 12 दिसंबर 2020 को इसकी पांचवी रिपोर्ट का पहला भाग जारी कर दिया है, जिसमें 17 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ष 2019-20 के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इसमें मप्र शामिल नहीं था। हालांकि बाकी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वे से जुड़ा फील्ड वर्क अब दोबारा शुरू हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अगले 6 माह में आने की उम्मीद है। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 की रिपोर्ट के मुताबिक मप्र में 48 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। वहीं, 9 लाख अतिकुपोषण की श्रेणी में हैं। वर्ष 2018 में आई इस रिपोर्ट के बाद भी प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसके तहत नीति का क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 मंत्रियों का राज्य पोषण मिशन बनाया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर संचालन समूह का गठन होगा। इसमें स्थानीय संस्थाओं नगरीय विकास एवं पंचायती राज समेत विभिन्न समितियों ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, संयुक्त वन प्रबंधन समिति आदि को शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने देश के कुपोषण प्रभावित 100 जिलों को चिन्हित किया है। इसमें मप्र के 12 जिले बड़वानी, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, खरगोन, मुरैना, शाहजहांपुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी व टीकमगढ़ हैं। वर्ष 2006 से 2016 के बीच 57 हजार बच्चों की मौत हुई है। कुपोषण से मृत्यु दर 42.8 प्रतिशत है। इस हिसाब से बिहार व झारखंड के बाद मप्र का देश में तीसरा नंबर आता है।

65 लाख बच्चों को बटे सूखे राशन में अनियमितता

प्रदेश में मिड-डे मिल में स्कूली बच्चों को बांटे गए 285 करोड़ रुपए के सूखा राशन में काफी अनियमितता सामने आई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों से शिकायतें मिली हैं कि बच्चों को घटिया क्वालिटी का राशन दिया गया। आधी-अधूरी सामग्री बांटी गई। इसके चलते मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की नोटशीट के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों से राशन बंटने और बच्चों तक पैकेट पहुंचने की सत्यापन रिपोर्ट तलब की है। कलेक्टरों से रिपोर्ट मिलने के बाद शासन इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप सकता हैं। सूखा राशन के लिए प्रदेश को 285 करोड़ रुपए का बजट मिला था। राज्य शासन के पास शिकायतें मिली हैं कि सामग्री वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। ये राशन बच्चों तक बराबर नहीं पहुंचा है। इसका वितरण जिला पंचायत सीईओ की निगरानी में होना था, जिसमें गड़बड़ी हुई है। इसके बाद मुख्य सचिव बैस ने 75 विकासखंड की सभी शालाओं में बंटे दाल, तेल और चिक्की का वितरण होने की सत्यापन रिपोर्ट 25 जनवरी तक बुलाई थी। स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव ने विकासखंड स्तर और स्कूलों तक वितरण होने के सत्यापन की जानकारी के लिए सभी जिलों के कलेक्टर और जिला मिशन संचालक को प्रपत्र भेजा है। इस प्रपत्र में सभी बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है ताकि प्रत्येक बच्चे तक सही राशन पहुंचने की स्थिति साफ हो जाए।

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में बीते आधे दशक में पांच वर्ष से कम आयु-वर्ग के बच्चों की मौत के मामलों में कमी आई है। सर्वेक्षण के पहले चरण में शामिल 22 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, गोवा और असम में नवजात (28 दिन से कम आयु के बच्चे), शिशु (365 दिन से कम उम्र के बच्चे) एवं बाल (5 वर्ष से कम वय के बच्चे) मृत्यु दरों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि स्पष्ट गिरावट के बावजूद असम में शिशु मृत्यु दर 30 से अधिक है। मिजोरम में शिशु तथा बाल मृत्यु दरों में कमी अवश्य हुई है लेकिन नवजात मृत्यु दर जस की तस है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के प्रथम चरण में चयनित राज्यों में, बीते पांच सालों में नवजात मृत्यु दर (34), शिशु मृत्यु दर (47) एवं बाल मृत्यु दर (56) अधिकतम बिहार में जबकि न्यूनतम (7 से कम) केरल में दर्ज की गई।

एनएफएचएस-4 (2015-16) और एनएफएचएस-5 (2019-20) की तुलना करने से पता चलता है कि 22 में से 15 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में नवजात मृत्यु दर स्पष्ट तौर पर घटी है। बीते पांच सालों में सर्वाधिक कमी सिक्किम, जम्मू-कश्मीर और असम में दर्ज की गई। नवजात मृत्यु दर केरल, सिक्किम और गोवा में सबसे कम तो बिहार, त्रिपुरा, असम और गुजरात में सर्वाधिक आंकी गई। नवाजत मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से 28 दिन के भीतर होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

न माया मिली और न राम

दिग्गी राजा यानी मप्र के वरिष्ठतम नेता दिग्विजय सिंह। निजी और राजनीतिक जीवन में उनके नाम कई ऐसे कीर्तिमान दर्ज हैं जिनके बारे में अधिकतर नेता सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति में दिग्गी राजा को कई अच्छी-बुरी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी उम्र काफी हो चली है, पर अब भी हर दिन भरपूर सक्रिय रहते हैं और अपनी अलग शैली में कुछ न कुछ नया किया करते हैं। उनका सबसे ताजा कारनामा है, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग धनराशि का चेक श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पते पर भेजना।

दिग्गी राजा मप्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में कई अहम भूमिकाओं में रह चुके हैं। उनके लिए यह समझना कतई कठिन नहीं है कि राम मंदिर निर्माण की सहयोग राशि प्रधानमंत्री को भेजना कितना बेतुका एवं हास्यास्पद है। श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट गठित है। देशभर से प्राप्त हो रही सहयोग राशि इसी ट्रस्ट के खाते में जमा हो रही है। आम श्रद्धालुओं की तरह लाखों कांग्रेसी भी इसी ट्रस्ट के खाते में सहयोग राशि जमा कर रहे हैं, पर दिग्गी राजा तो दिग्गी राजा ठहरे। वह भला आम आदमी की तरह क्यों सोचें?

वह आम आदमी की तरह सोचने लगेंगे तो कांग्रेस की मौजूदा हालत और खुद उनकी उम्र-आधारित परिस्थितियों के बीच उनकी क्या प्रासंगिकता रह जाएगी? इसलिए राजा साहब ने अपना चेक प्रधानमंत्री को भेज दिया। इसके पीछे उनके अपने तर्क होंगे, पर उनके इस कृत्य पर आम आदमी के अपने सवाल हैं। यक्ष प्रश्न यह है कि राम को काल्पनिक पात्र बताने वाली पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। प्रियंका गांधी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने अयोध्या गई थीं, पर रामलला का दर्शन करने नहीं गईं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जो भाजपा पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप जड़ते रहे हैं। वह राम मंदिर आंदोलन को भी राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।

मप्र के कांग्रेस कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं कि दिग्गी राजा द्वारा मंदिर निर्माण की सहयोग राशि का चेक प्रधानमंत्री को भेजना क्या राजनीति नहीं है? वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर आम आदमी उनकी स्वीकारोक्ति का इंतजार नहीं करता। सबको दिख रहा है कि राजा साहब राम मंदिर निर्माण में भी नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जब उनके कद का नेता ऐसी हरकत करता है तो उसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पहले ही बहुत कुछ भुगत रही है। दिग्गी राजा जाने-अनजाने उसके भविष्य को भी अभिशप्त करवा रहे हैं। मप्र के तटस्थ लोग इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसा जुमला इसी प्रदेश के कांग्रेसी नेता ने गढ़ा। सनातन धर्म के संतों और धर्माचार्यों के बारे में सर्वाधिक अपमानजनक टिप्पणियां यहां के कांग्रेस नेताओं ने ही कीं। पार्टी इसका खामियाजा भी भुगत रही है, पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब भी इन सबसे सबक सीखने को तैयार नहीं।

राम मंदिर निर्माण के लिए मप्र समेत पूरे विश्व में उल्लास हिलोरे ले रहा है। अमीर-गरीब अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक योगदान करके धन्य महसूस कर रहे, पर दिग्विजय सिंह अब भी इसे लेकर राजनीति में उलझे हैं। उनके मन में राम मंदिर के प्रति रंचमात्र आस्था होती तो वे ऐसी हल्की हरकत न करते, पर वह अपनी सोच और आदत से लाचार हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मप्र राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़-चढ़कर सहयोग करने वाला प्रदेश है। यहां के मुसलमान भी दिल खोलकर धनराशि समर्पित कर रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह को भ्रम हो रहा कि राम मंदिर निर्माण के प्रति सच्ची आस्था दर्शाने से उनका वोटबैंक लुट जाएगा। मप्र में उनके पास कहां वोटबैंक बचा है? उनकी दुविधा से कांग्रेस को न माया मिली और न राम।

वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्जमाफी का झूठा वादा करके कांग्रेस अपना रहा-बचा आधार भी गंवा चुकी। राम मंदिर निर्माण में सच्चे मन से सहयोग करके पार्टी अपना प्रायश्चित शुरू कर सकती थी, पर राजा साहब ने अपनी स्मार्टनेस से यह अवसर भी छीन लिया। हर स्तर के देशवासियों के सहयोग से अयोध्या में कुछ ही वर्षों में दुनिया का भव्यतम धर्मस्थल बनकर तैयार हो जाएगा, पर इसके निर्माण के इतिहास में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की निम्नस्तरीय हरकतों के अलावा अपना कोई योगदान नहीं दिखेगा।

● **रजनीकांत पारे**

वासनिक ने संभाली कमान

नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के सामने आदिवासी वोट बैंक को साधे रखने की चुनौती है। यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों की इसकी कमान प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने अपने हाथों ले ली है। पिछले दशक तक आदिवासी भाजपा का वोट बैंक था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल हुआ और कांग्रेस ने प्रदेश की आदिवासी 47 में से 31 सीटें जीत कर चौका दिया था। इससे पहले लगभग इतनी ही सीटें भाजपा को मिलती आ रही थीं। यही वजह है कि वासनिक ने दो दिनों तक मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया व शहडोल के दौर किए। इस दौरान उन्होंने इन जिलों में उम्मीदवारों का चयन करने से पहले क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ आगामी विधानसभा की तैयारी के मद्देनजर आदिवासी जिलों के लिए प्लान तैयार किया गया है। यही वजह है कि पिछले माह प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिवासी जिलों के विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक ली थी।

इस बार जोर से लगेगा करंट

मप्र में उपचुनाव जीतने के बाद से ही बिजली आम उपभोक्ताओं को झटके पर झटके दे रही है। दो प्रतिशत महंगी हो चुकी बिजली की दरों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की तैयारी है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। कंपनी ने कुल जरूरत 44 हजार 814 करोड़ रुपए बताई है। मौजूदा बिजली दर पर उसे कुल 42 हजार 185 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 2629 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की अनुमति मांगी है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले दिसंबर में ही बिजली की दरों में 1.98 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। उपभोक्ताओं की जेब पर प्रति यूनिट 8 से 15 पैसे का भार डाला गया है। अब नए टैरिफ याचिका में 6 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। नियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर तीन गुना अधिक भार बढ़ जाएगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के पास कंपनी के इस प्रस्ताव का विरोध करने और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए लोगों को बड़ी संख्या में राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करानी होगी।

सूत्रों की मानें तो टैरिफ याचिका में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने की तैयारी है। औद्योगिक इकाइयों को महंगी बिजली बेचकर कंपनियां पहले ही नुकसान उठा चुकी है। इसी तरह रेलवे को बेची जा रही बिजली की दर भी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में कंपनियों के सामने घरेलू और कृषि उपभोक्ता ही हैं। प्रदेश में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.59 करोड़ है। इसमें एक करोड़ उपभोक्ता घरेलू हैं जो गृह ज्योति योजना का लाभ पा रहे हैं। 28 लाख के लगभग कृषि पंप उपभोक्ता हैं, जो सरकार की सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। गृह ज्योति योजना और कृषि पंप वाले उपभोक्ताओं की बिजली ही महंगी करने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली की दर बढ़ाने वाले इस याचिका पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों के स्तर पर आपत्तियों की सुनवाई करेगी। इसके लिए मार्च में कोई तारीख निश्चित हो सकती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम रेवन्यू फिरोज कुमार मेश्राम के अनुसार तीनों विद्युत कंपनियों के आय-व्यय के अनुसार टैरिफ याचिका लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल जरूरत 44 हजार 814 करोड़ रुपए की अनुमानित है। मौजूदा बिजली दर पर कुल अनुमानित आय 42 हजार 185 करोड़ रुपए ही हो रही है। ऐसे में इस गैप को भरने के लिए 6 प्रतिशत दर बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है।

आमजन की जेब ढीली करने की पूरी तैयारी

कांग्रेस सरकार की नीति में परिवर्तन कर आमजन की जेब ढीली करने की तैयारी पूरी हो गई है। नियामक आयोग की मंजूरी मिलते ही आम उपभोक्ताओं पर तीन गुना ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करना होगा। कंपनियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 100 रुपए ही बिल चुकाने की योजना लागू की थी। फिलहाल मौजूदा सरकार ने भी इसे यथावत रखा है। 150 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि इसके चलते सरकार पर प्रतिमाह 400 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है। एक परिवार को सस्ती बिजली देने पर 517 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। अब इसकी भी समीक्षा सरकारी स्तर पर की जा रही है। पहले चरण में आयकर देने वालों से पूरी बिजली की दर वसूलने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 6 लाख उपभोक्ता हैं। यहां यह भी बता दें कि दिसंबर में ही बिजली दरों में 1.98 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। उपभोक्ताओं की जेब पर प्रति यूनिट 8 से 15 पैसे का भार डाला गया था। सूत्रों के मुताबिक अब नए टैरिफ याचिका में 6 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। नियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर 3 गुना अधिक भार बढ़ जाएगा।

उधर, बिजली कंपनी के नए टैरिफ में ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ अधिक डाला जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो प्रस्ताव बनाया गया है इसमें जिस बिजली वितरण कंपनी का लाइन लॉस सबसे कम है वहां के उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली बेची जाएगी। वहीं जहां ज्यादा बिजली नुकसान है उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को औसत सस्ती बिजली मिलेगी। हालांकि अभी ये प्रस्ताव मप्र नियामक आयोग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। यदि कंपनी की याचिका मंजूर हुई तो करीब 8 फीसदी बिजली के दाम बढ़ेंगे।

प्रदेश में फिलहाल सबसे कम बिजली की पारेषण एवं वितरण हानियां (लाइन लॉस) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में है। यहां करीब 16.65 फीसदी नुकसान हो रहा है जबकि विद्युत नियामक आयोग से 15 फीसदी का लाइन लॉस मानक तय हुआ है। इसके अलावा पूर्व क्षेत्र कंपनी में 30.87 और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में लाइन लॉस 36.67 फीसदी हो रहा है। जबकि उक्त कंपनी में क्रमशः 16 तथा 17 फीसदी मानक आयोग ने तय किया हुआ है। ऐसे में मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रस्ताव बनाया इसमें पश्चिम क्षेत्र के उपभोक्ता को औसत दाम 7.10 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं पूर्व क्षेत्र कंपनी के उपभोक्ता को 6.99 रुपए प्रति यूनिट और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता को 6.93 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी मिलेगी। तीनों वितरण कंपनी के लिहाज से कुल औसत खपत प्रति यूनिट करीब 7 रुपए की दर से पड़ेगी। मौजूदा दर के हिसाब से औसत बिजली का दाम 6.51 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ता खरीद रहा है। इसमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता 6.99 रुपए प्रति यूनिट, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता को 6.95 तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6.93 रुपए प्रति यूनिट पड़ रही है। अब एक बार फिर से बिजली की दरों में वृद्धि उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकती है।

● **अरविंद नारद**

गरीबों के राशन पर डाका

कोरोनाकाल कई लोगों के लिए आपदा में कमाई का अवसर साबित हुआ। हद तो यह रही कि रसूखदारों ने गरीबों के राशन पर डाका डालकर अपना घर भर डाला। ऐसा ही मामला गत दिनों इंदौर में सामने आया। खुद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले की परतें खोलीं। मनीष सिंह ने घोटाले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में 80 लाख का राशन घोटाला हुआ है। राशन माफियाओं ने जिम्मेदारों से सांठ-गांठ कर 51 हजार गरीब परिवारों के हक का ढाई लाख किलो से ज्यादा राशन डकारा है। मामले में माफिया भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद दहिगुडे के खिलाफ रासुका की कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि भरत दवे और प्रमोद दहीगुडे के साथ ही इनके परिचितों के बारे में शिकायत मिली कि इनके द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में या तो सामग्री नहीं दी जा रही या फिर कम वितरण हो रहा है। इस पर 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित किया गया। 12 जनवरी को 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर टीम ने दबिश देकर रिकार्ड एवं पीओएस मशीन जब्त की। उसी दिन टीम ने इन दुकानों में संग्रहित राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया। जांच में अप्रैल 2020 से ही खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दाल और केरोसिन की मात्रा कम या ज्यादा मिली। साथ ही कई अनियमितताएं भी पाई गईं। इस पूरे मामले में मास्टर माइंड भरत दवे पर्दे के पीछे रहकर अपने कई रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से राशन दुकानें संचालित कर पूरा हेर-फेर कर रहा था।

टीम ने जब दुकानों का रिकार्ड देखा तो इसमें गेहूं 185625 किलो, चावल 69855 किलो, नमक 3169 किलो, शक्कर 423 किलो, चना दाल 2201 किलो, साबुत चना 1025 किलो, तुवर दाल 472 किलो, केरोसीन 4050.5 लीटर में बड़बड़ी मिली। माफियाओं ने 185625 किलो गेंहू और 69855 किलो चावल कुल मिलाकर 255480 किलो खाद्यान्न जिसकी कीमत 7904479 है, का गबन किया। प्रति व्यक्ति 5 किलो के मान से माफियाओं ने 51096 हितग्राहियों को राशन से वंचित किया। इसके अतिरिक्त मिटटी का तेल (केरोसिन) नमक, शक्कर, चना दाल, साबुत चना, तुवर दाल में भी गबन किया। इन्होंने गरीबों को उचित जानकारी नहीं होने पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन वितरित ही नहीं किया। ये सिर्फ मात्र हर महीने मिलने वाला राशन ही उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन पीओएस मशीन में कर दे रहे थे। ये यहां से राशन बचाकर बाजार में बेच रहे थे।

इंदौर के प्रभारी फूड कंट्रोलर आरसी मीणा की भी राशन माफियाओं से मिलीभगत पाई गई थी। राशन को लेकर मीणा की जिम्मेदारी निरीक्षण और पर्यवेक्षण की थी। लेकिन वे खुद अधिकारियों को जांच करने से रोक कर रहे थे। जांच खाद्य निरीक्षकों को भविष्य खराब करने की धमकी भी दी जा रही थी। अधिकारियों ने शिकायत पर उन्हें निलंबित करने के आदेश कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा ने 13 जनवरी को देते हुए अलीराजपुर अटैच कर दिया था।

इंदौर में सालों से राशन माफिया ने कई कंट्रोल दुकानों पर कब्जा कर रखा था और खाद्य विभाग भी उसके इशारों पर चलता रहा। पहली बार कलेक्टर मनीष सिंह ने राशन माफिया पर ना सिर्फ नकेल डाली, बल्कि दवे बंधुओं पर रासुका भी लगाई। खाद्य महकमे और कंट्रोल दुकानों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले 20-25 सालों से दवे बंधुओं का दबदबा रहा है, जिसके चलते पूरे खाद्य विभाग में उसकी तूती बोलती रही। अभी कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ **दवे बंधुओं** की नजदीकियां उजागर हुई है और सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने से लेकर अन्य फोटो भी सामने आए। इधर कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के भी जितने खाद्य मंत्री पिछले 15 सालों में रहे उन सभी से इन राशन माफियाओं की नजदीकियां रही है। हालांकि निलंबित किए गए खाद्य नियंत्रक आरसी मीणा, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गए, वे भी दिग्गज कांग्रेस नेताओं से जुड़े रहे हैं। यही कारण है कि कई बार शिकायत होने के बाद भी राशन माफिया के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अगर स्थानीय स्तर पर खाद्य विभाग के निरीक्षक थोड़ी-बहुत भी जांच करते थे, तो सीधा ऊपर से फोन आ जाता था। भाजपा के ही कई पूर्व खाद्य मंत्री दवे बंधुओं के मददगार रहे, जिसके चलते पिछले 20-25 सालों से इनका नेटवर्क कायम हो गया और 150 से अधिक कंट्रोल दुकानें इनके नियंत्रण में आ गई। अब कलेक्टर मनीष सिंह ने पहली बार सख्त कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ की है।

● **विकास दुबे**

अवैध कमाई धूल में

कोरोनाकाल में गरीबों के हक का राशन डकारने वाले दवे बंधुओं के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने निगम के साथ मिलकर गत दिनों बुलडोजर चला दिया। राशन में हेराफेरी कर भरत दवे, श्याम दवे ने परिवार के साथ मिलकर शहर में मकान बनाने के साथ ही मल्टी भी खड़ी कर ली थी। सुबह रिमूवल की कार्रवाई जोन-18 में पवन नगर से हुई। इसके बाद मोती तबेला में भी मकानों को जमींदोज किया गया। पवनपुरी में श्याम दवे के तीन मंजिला मकान को निगम की टीम ने जमींदोज किया। शुरुआती जांच में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आ चुकी है। संपत्तियों की जांच में कलेक्टोरेट के आसपास ही इनकी पांच मल्टियां और एक प्लॉट सामने आ चुका है, जिसकी कीमत पांच करोड़ के करीब बताई जा रही है। यह मल्टियां श्याम दवे की हैं। यहां किराए से दुकानें संचालित हैं। इसके अलावा किराएदार भी रह रहे हैं। इसी परिवार के एक सदस्य धर्मेंद्र पुरोहित की पीर गली के पास तीन मल्टियां होना बताया जा रहा है। भरत दवे के एक रिश्तेदार अशोक और उसकी पत्नी अंजू द्वारा बिसनावदा में ईंट-भट्टे का भी लंबा-चौड़ा कारोबार होना बताया जा रहा है। हालांकि भरत दवे के अभी केवल सुदामा नगर में एक मकान का ही पता चला है। राशन माफिया भरत और श्याम दवे समेत चार आरोपियों को पुलिस की एसआईटी ने 23 जनवरी को राजीव गांधी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कुल 31 राशन माफियाओं को चिन्हित किया है। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि आरोपी भरत (55) पिता विजय दवे निवासी ई सेक्टर सुदामा नगर, श्याम (57) पिता बालकृष्ण दवे निवासी मोती तबेला, धीतेश (32) पिता श्याम दवे और कमलेश (27) पिता सुखराम कनाड़े निवासी बाईग्राम शनि मंदिर के पास को गिरफ्तार किया है।

करीब 10 माह बाद यह उम्मीद जगी है कि मप्र विधानसभा में कामकाज सुचारु रुप से हो पाएगा। इसके लिए 22 फरवरी से बजट सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी, वहीं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राजनीतिक घमासान के बीच यह बजट सत्र उम्मीदों भरा है। देखना यह है कि यह सत्र उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं।

उम्मीदों का बजट सत्र

मप्र विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 33 दिनों तक चलने वाले सत्र को हरी झंडी दे दी है, जिसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी भी कर दी है। ऐसे में मप्र में कोरोना संकट के चलते पिछले सात महीने से प्रोटेम स्पीकर ही सदन की कार्यवाही और कामकाज देख रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बजट सत्र में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ऐसे में देखना है कि मप्र विधानसभा का स्थायी स्पीकर कौन बनता है?

दरअसल, मप्र में मार्च में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने और भाजपा का दामन थाम लेने के बाद कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई हो गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। ऐसे में कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रजापति के इस्तीफे के बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा प्रोटेम स्पीकर बने थे, लेकिन जुलाई में कैबिनेट में शामिल होने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

जगदीश देवड़ा के इस्तीफे के बाद 3 जुलाई को भाजपा नेता व विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, तब से लेकर अभी तक वे ही विधानसभा का कामकाज देख रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रहते उन्होंने कांग्रेस के कई विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए। रामेश्वर शर्मा के नाम के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया है। किसी भी विधानसभा में सबसे लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर बने रहने का रिकॉर्ड अब शर्मा के नाम पर हो गया है। हालांकि, अब सात महीने के बाद परमानेंट विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की संभावना तेज हो गई है, क्योंकि उपचुनाव हो चुके हैं और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी दो बार हो चुका है।

मप्र में अब भाजपा 126 विधायकों के साथ सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। 22 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले ही दिन अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसीलिए भाजपा ने स्थायी विधानसभा अध्यक्ष के चयन करने पर मंथन शुरू कर दिया है। फरवरी के पहले सप्ताह में भाजपा स्पीकर के लिए नाम तय कर उसका ऐलान कर सकती है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बैठक हुई है, जिसमें भाजपा स्पीकर के साथ उपाध्यक्ष के पद पर भी दावेदारी कर सकती है।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उपचुनाव जीतने के बाद कहा था कि विंध्य से ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं, जबलपुर के दिग्गज नेता और पार्टी विधायक अजय विश्नोई ने कहा था कि मैं तो काफी पहले से विंध्य इलाके से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग करता रहा हूं। ऐसे में माना जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र से आने वाले किसी नेता को भाजपा स्पीकर की कुर्सी पर बैठा सकती है। ऐसा होता है तो 17 साल के बाद विंध्य क्षेत्र से कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। विंध्य से श्रीनिवास तिवारी 24 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक एमपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे थे।

अधिसूचना के मुताबिक इस सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों

15 मिनट में समाप्त हो गया था पिछला बजट सत्र

पिछले साल बजट सत्र 16 मार्च से 31 मार्च तक था, लेकिन कमलनाथ सरकार के अल्पमत में आने से राजनीतिक संकट खड़ा होने के कारण गतिरोध पैदा हो गया था। मप्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर राज्यपाल और सरकार आमने-सामने आ गए थे। इसके बाद कमलनाथ को बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले बजट सत्र से अब तक पांच बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया, जिसमें 17 बैठकें होनी थीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते केवल 4 बैठकें हो पाईं। दिसंबर में तीन दिन सत्र बुलाया गया था, लेकिन विधानसभा के 36 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2020 में 21 से 23 तारीख तक तीन दिन का सत्र आहूत किया गया, लेकिन एक दिन में समाप्त कर दिया गया।

की सूचनाएं 24 फरवरी तक और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम-267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में 16 फरवरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएगी। कमलनाथ सरकार का कार्यकाल केवल 15 माह का रहा, लेकिन इस दौरान एक इतिहास विधानसभा में बना था। वर्ष 2019 में मानूसन सत्र 8 जुलाई से 26 जुलाई तक बैठकें प्रस्तावित हुईं, लेकिन 15 और 16 जुलाई (क्रमशः सोमवार और मंगलवार) को अवकाश होने के कारण विधानसभा की बैठक शनिवार और रविवार को भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। मप्र विधानसभा की कार्यवाही शनिवार को देर रात लगभग 10:45 बजे स्थगित होने के बाद रविवार सुबह 11 बजे फिर शुरू हो गई थी। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब विधानसभा की कार्यवाही रविवार को भी हुई।

इस बजट सत्र के पहले ही दिन अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। ऐसे में इस पद को लेकर नाम सामने आने लगे हैं। विधानसभा सचिवालय ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम और केदारनाथ शुक्ला में से किसी एक का नाम तय होगा। अध्यक्ष पद के साथ ही उपाध्यक्ष पद भी भाजपा अपने पास रखने जा रही है। खास बात यह है कि विंध्य अंचल लगातार 4 से 5 बार के विधायकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह है कि इन विधायकों में से किसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। ताकि राजनीतिक, क्षेत्रीय के साथ-साथ जातिगत समीकरणों को भी साधा जा सके। विंध्य अंचल से आने वाले 5 विधायकों के नाम विधानसभा अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। इन विधायकों में राजेंद्र शुक्ल, नागेंद्र सिंह नागौद, गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह गुढ़, केदारनाथ शुक्ला और अजय विश्नोई का नाम शामिल है। हालांकि अजय विश्नोई महाकौशल से आते हैं। लेकिन वे लगातार यह मांग कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य या महाकौशल अंचल में से किसी एक को मिलना चाहिए।

खास बात यह है कि कमलनाथ सरकार की तर्ज पर इस बार भाजपा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अपने पास रखने की तैयारी में हैं। सूत्रों का दावा है कि इस बार भाजपा में ऐसे विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो लगातार तीन बार से विधायक बनते आ रहे हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य की झोली में जाता है। तो ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मध्य भारत या बुंदेलखंड के किसी विधायक को दिया जा सकता है। इतना ही नहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के जरिए भाजपा जातिगत समीकरणों को भी साधने की तैयारी में है।

मप्र विधानसभा में फिर टूटेगी परंपरा

मप्र विधानसभा के बजट सत्र में क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा एक बार फिर टूट जाएगी? भाजपा नेताओं की ओर से आ रहे बयानों को देखते हुए कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा को कमलनाथ और दिग्विजय के घमंड ने तोड़ा था और अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके सीधे मायने यह निकाले जा रहे हैं कि भाजपा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस या विपक्ष को देने के मूड में नहीं है। 2018 से पहले तक मप्र विधानसभा में यह परंपरा रही थी कि विधानसभा में अध्यक्ष का पद सत्तापक्ष के और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के खाते में रहता था। लेकिन 2018 में बनी कमलनाथ सरकार के दौरान यह परंपरा टूट गई। तब अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के सीनियर विधायक एनपी प्रजापति चुने गए और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष में रही भाजपा को देने के बजाय, कांग्रेस के ही खाते में गया। तब कांग्रेस की विधायक हिना कांवरे उपाध्यक्ष चुनी गई थीं। अब एक बार फिर विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। इस बार सत्ता में भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस। संख्या बल के लिहाज से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर अगर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी तो वह दोनों जीत दर्ज करेंगे। अध्यक्ष के तौर पर तो भाजपा का उम्मीदवार खड़ा होना स्वाभाविक है लेकिन उपाध्यक्ष के लिए भी भाजपा की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान से इस बात के संकेत साफ मिल गए हैं। ऐसे में संख्या बल के लिहाज से उपाध्यक्ष का पद भी भाजपा के ही खाते में रहेगा।

प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। वे देश के एकलोते ऐसे विधायक बन गए हैं जिन्होंने लगातार सात महीने तक प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कई विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए है। रामेश्वर शर्मा वर्तमान में भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। बहुमत के आधार पर स्पीकर का पद भाजपा की झोली में जाएगा। यह तय माना जा रहा है, लेकिन एक नाम तय करना आसान नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का कहना है कि जो भी फैसला होगा सर्वसम्मति से होगा। फैसला सब को राहत देने वाला होगा।

भाजपा पर विंध्य क्षेत्र के नेताओं को एडजस्ट करने का दबाव है। केदारनाथ शुक्ल सीधी सीट से और गिरीश गौतम रीवा के देवतालाब सीट से भाजपा विधायक हैं। विंध्य से आने वाले इन दोनों विधायकों में से कोई एक अध्यक्ष पद पर विराजमान हो सकता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद विंध्य के खाते में जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए मप्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीताशरण शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा नाराज चल रहे अपने से विधायकों को संतुष्ट करने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अपने पास रख सकती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य नेताओं के पदभार सौंपने के लिए भाजपा में विचार-विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं को शिवराज सरकार के कैबिनेट और निगम मंडलों में जगह मिल सकती है।

● **प्रवीण कुमार**

अमरकंटक में नक्सली घुसपैठ

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से घुसपैठ कर मप्र के बालाघाट में डेरा डाले नक्सली अमरकंटक में अपनी गतिविधियों को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्सली गतिविधियों को लेकर अपनी आशंकाओं, चिंताओं और मिलीं सूचनाओं से देश के गृहमंत्री अमित शाह को भी अवगत कराया है। उन्होंने इस मामले में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का आग्रह शाह से किया है। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न मसलों पर चर्चा के अलावा प्रमुख रूप से राज्य में सक्रिय हो रहे नक्सलियों के बारे में मिल रही सूचनाओं से अवगत कराया था। बता दें कि मप्र में बालाघाट और मंडला नक्सल प्रभावित जिले हैं, जहां पर नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलती रहती हैं। यहां मप्र पुलिस की हॉक फोर्स की एक बटालियन के अलावा दो आईआर बटालियन और एक रिजर्व पुलिस बल की बटालियन तैनात की गई है। नक्सलियों की हरकतों पर नजर रखने और सूचना जुटाने के लिए एक विशेष शाखा भी बनाई गई है। इसके अलावा मप्र, छत्तीसगढ़ के त्रिकोणीय क्षेत्र में एक संयुक्त कैम्प भी नक्सली गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इतने बड़े पैमाने पर पहरेदारी के बावजूद राज्य के अमरकंटक जिले में नक्सलियों की गतिविधियों के विस्तार की योजना की भनक ने सरकार को चौकन्ना कर दिया है।

खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से 100 से भी ज्यादा नक्सलियों ने मप्र की सीमा में प्रवेश किया है। दोनों राज्यों की सीमा बालाघाट से मिलती है। डराने वाली खबर यह है कि ये नक्सली बालाघाट, मंडला से निकलकर राज्य के दीगर जिलों में अपनी धमक दर्ज कराने की साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नक्सली राज्य में कोई बड़ी घटना अंजाम देने वाले हैं? खुफिया सूत्र बताते हैं कि बालाघाट और मंडला में करीब 6 नक्सली समूह सक्रिय हैं, इनमें से खटिया मोचा दलम पिछले साल मंडला आया था। बालाघाट और मंडला की सीमाएं एक-दूसरे से लगी हुई हैं, जिसका दायरा काफी लंबा है। जहां तक बालाघाट जिले का सवाल है तो बता दें कि यहां बीते नवंबर और दिसंबर 2020 में तीन मुठभेड़ों में तीन महिला माओवादी मारी गई थीं। इनमें से दो छत्तीसगढ़ और एक महाराष्ट्र की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की युवा नक्सली 25 वर्षीय शारदा को 6 नवंबर को बालाघाट पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था, उस पर छत्तीसगढ़ और मप्र पुलिस ने कुल 8 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके अलावा बस्तर छत्तीसगढ़ के गंगलूर से आई 24 वर्षीय नक्सली सावित्री भी 11-12 दिसंबर 2020 की रात को बालाघाट पुलिस से मुठभेड़ में मारी गई थी, उस पर भी दोनों राज्यों की पुलिस ने 14-14 लाख रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था।

राज्य में मारे या पकड़े जा रहे नक्सलियों और उनकी गतिविधियों से यही साबित होता है कि मप्र के बालाघाट, मंडला ही नहीं अनूपपुर, सिंगरौली जैसे जिले भी उनके लिए आरामगाह जैसे हैं। खुफिया महकमे के सूत्र बताते हैं कि पड़ोसी राज्यों में वारदातों को अंजाम देने के बाद या पुलिस की निगाहों से बचने नक्सली इन जिलों में आराम करने आ जाते हैं। जंगलों में आदिवासियों के साथ भी रह लेते हैं और मामले शांत हो जाने के बाद अपने राज्यों में वापस लौट जाते हैं।

90 के दशक से बालाघाट जिले के जंगलों में आउट सोर्स की कमी का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रहे नक्सलियों से निपटने के लिए अब तीन राज्यों की सीमा पर षट्कोणीय सुरक्षा का घेरा नजर आएगा। इसके लिए पुलिस खास सुरक्षा इंतजाम करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा पर मप्र के बालाघाट जिले में छह चौकियों में सुरक्षा का मजबूत घेरा दिखेगा। नक्सलियों से निपटने जंगलों में कसावट की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों से निपटने का अब तक का यह अनूठा एक्शन प्लान है। तीन राज्यों की सीमा पर षट्कोणीय घेरा जिले का ही नहीं कान्हा नेशनल पार्क का भी सुरक्षा कवच बनेगा।

● **राकेश ग्रोवर**

नक्सलियों की राह में मौत का जाल

लगातार सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे नक्सलियों का रास्ता रोकने के लिए सुरक्षा का खास घेरा बनाने के साथ ही पुलिस ने कुछ नए रास्तों में एंबुश प्लान किया है। महाराष्ट्र- छत्तीसगढ़ की सीमा मप्र की बालाघाट व मंडला जिले में फोर्स बढ़ाने कवायद की जा रही है। जिले के सायर-संदूका, टेमनी, कोरका-बोंदारी, मलकुआ, चिलकोना, राशिमेटा, कोदापार, पितकोना, चौरिया, चिलौरा, कोसुम्बहरा, धीरी, मुरुम, मलायदा, सीतापाला, कटेमा, कट्टीपार ये दूरस्थ इलाके 90 के दशक से नक्सली गिरफ्त में रहे हैं। वहीं नए स्थान के लिए दमोह, सालेटेकरी, मछुरदा व छत्तीसगढ़ से लगे मंडई, चिल्पी में विस्तार दलम के साथ नक्सलियों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। दक्षिण बैहर और लांजी के इलाके में सुरक्षा में कसावट लाने के साथ ही छत्तीसगढ़ में विस्तार दलम का विस्तार रोकने प्रयास किए जा रहे हैं। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी कहते हैं कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा पर मप्र के बालाघाट-मंडला जिलों में 6 चौकियों में षट्कोणीय सुरक्षा का घेरा नजर आएगा। पुलिस ने अपने एक्शन प्लान में खास व्यूह की रचना की है। जिसे तोड़ पाना नक्सलियों के लिए आसान नहीं होगा। मप्र का यह अब तक अनूठा एक्शन प्लान है, जिसमें करीब 600 जवान सीमा पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा से अब नक्सली सीधे जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

शोपीस बनने लगे उज्ज्वला सिलेंडर

जिस समय ग्रामीणों को केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर वितरित किए गए, तब गांवों के अधिकतर घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनने लगा था। इससे न सिर्फ कच्चे ईंधन से फैलने वाले धुएं में कमी देखने को मिली थी। जब नए-नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुए थे, तब अधिकतर घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनने लगा था, लेकिन अब अधिकतर घरों में फिर से कच्चे ईंधन (लकड़ी, कंडे आदि) से चूल्हे पर ही खाना बनता दिखने लगा है। अब हाल यह है कि गांवों के अधिकतर घरों से सुबह-शाम फिर वही धुआं उठता है। बल्कि सर्दियों में अगर देखें, तो और अधिक धुआं उठता दिखाई देता है। क्योंकि अनेक लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव भी तापते हैं। हालांकि खेत में पराली और ऊख की पताई जैसे दूसरे अवशेष जलाने पर पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता है, तो उस पर मोटा जुर्माना लगता है और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन गांव तो गांव है, गांवों की कच्चे ईंधन पर विकट निर्भरता है। इस बात को सरकारों को भी समझना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष और स्थायी व्यवस्थाएं बनानी होंगी।

सवाल यह है कि सरकार की वातावरण को शुद्ध करने की कोई भी योजना आखिर परवान क्यों नहीं चढ़ पाती? अब से करीब तीन दशक पहले भी तत्कालीन सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए घर-घर गोबर-गैस की योजना चलाई थी। शुरू में गांवों के अनेक घरों में गोबर-गैस के प्लांट भी लगे, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे गोबर-गैस के वो प्लांट समूल रूप से नष्ट हो गए। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिले गैस सिलेंडर भी आज गांवों के अधिकतर घरों में हैं। लेकिन शुरू से ही लोगों को अपने पैसे से सिलेंडर भराने पड़ रहे हैं। केवल लॉकडाउन के समय तीन महीने मुफ्त में सिलेंडर भरे गए थे। इस बारे में कुछ ग्रामीणों से बात करने पर कई ऐसी बातें और परेशानियां निकलकर सामने आईं, जिन पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। उज्ज्वला सिलेंडर भराने, न भराने के बारे में पूछने पर मीरगंज क्षेत्र के गांव रसूलपुर के श्याम सिंह कहते हैं कि गांवों में हर आदमी के पास इन दिनों परेशानी है। बाहर रोजी-रोटी कमा रहे बहुत-से लोग इस समय खाली बैठे हैं। मजदूरों की इतनी आमदनी नहीं होती कि वे हर महीने करीब साढ़े सात सौ की गैस भरा सकें। किसानों पर वैसे ही आफत आई हुई है। पहले सिलेंडर सस्ता था, कुछ लोग बाहर रहकर पैसा भी कमा रहे थे, तब ज्यादातर घरों में सिलेंडर भरा लिए जाते थे। अब सिलेंडर भी बहुत महंगा है और कमाई भी नहीं है, तो सिलेंडर कहां से भराएं। अंगनलाल ने इस बारे में कहा कि भैया! सरकार ने सिलेंडर तो दे दिए और गैस महंगी कर दी। हम तो मजदूर आदमी ठहरे। अकेले कमाते हैं, तो पांच लोग रोटी खाते हैं। ऐसे में सिलेंडर-बिलेंडर कौन भराए?

हमारे बस की बात तो है नहीं। गांवों में पंडिताई का पेशा करने वाले कस्बा निवासी रामअवतार आर्य कहते हैं कि जो परिवार संपन्न हैं, केवल वे ही दोनों टाइम गैस की रोटी खाते हैं। हम जैसे मध्यम परिवारों में एक सिलेंडर भराने के बाद उसे बहुत खास मौके पर ही उपयोग में लाया जाता है, जैसे मेहमान आ जाएं तो। लेकिन गरीबों के लिए तो सिलेंडर भराना मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के जैसा है। सरकार हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है। उसे सोचना चाहिए कि गांव के लोग अभी उतने संपन्न नहीं है कि वे शहरी लोगों की तरह अच्छा जीवन जी सकें। अब तो सब्सिडी भी नहीं आती। पहले की अपेक्षा अब दो से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो गया। बिजली पहले ही महंगी हो रखी है। पेट्रोल, डीजल सब तो महंगा है। गांवों में अधिकतर लोग या तो किसान हैं या मजदूर। यहां नौकरीपेशा 10 फीसदी भी नहीं हैं। ऐसे में किसके बस की बात है कि वह सिलेंडर भराए? किसान खेत में पानी के देने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करने और इंजन से पानी देने में ही हाफ जाता है। अब तो डीजल इतना महंगा है कि अपने ही ट्रैक्टर से जुताई बहुत महंगी पड़ती है, अपने ही पम्पसेट से पानी लगाना बहुत महंगा पड़ता है। सोचिए, जो लोग सबकुछ किराए पर लाकर खेती करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? ऐसे में सिलेंडर भराने की हिम्मत किसकी होगी? जबसे कोरोना आया है, तबसे तो वैसे भी लोगों की रोजी-रोटी पर संकट मंडराने लगा है। अब सरकार कह रही है कि नया कोरोना आ गया है। समझ में नहीं आता कि नया कोरोना ही आया है या लोगों की खाल उतारने की तैयारी की जा रही है। कभी-कभी सियासी लोगों पर विकट गुस्सा आता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम गांव वालों की न तो कोई सुनने वाला है और न ही हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

किसी-किसी परिवार में कई कनेक्शन

बता दें कि जब उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए थे, तब किताब के नाम पर सभी से 100-100 रुपए लिए गए थे। हर परिवार को एक सिलेंडर, एक रेगुलेटर, एक पाइप और एक चूल्हा दिया गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि इस गैस कनेक्शन में कुछ जगहों पर अपने-पराए का भेदभाव देखने को मिला था। यह बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को जो कनेक्शन सरकार ने हर परिवार मतलब हर दम्पति को दिए थे, उनमें भी बंदरबांट जैसी स्थिति के बारे में कुछ लोगों ने बताया। गांव के एक पढ़े-लिखे और गांव की गतिविधियों पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि देखिए, गांवों में हर सरकारी योजना में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। उज्ज्वला योजना में भी खूब धांधली हुई। इस योजना के तहत हुए गैस कनेक्शनों में देखने को मिला कि जिसके संबंध प्रधान या दूसरे पहुंच वाले लोगों से थे, उन्हें ज्यादा लाभ मिला और जिनके संबंध नहीं थे, उन्हें या कम लाभ मिला या मिला ही नहीं। ऐसे में कई परिवार तो ऐसे हैं, जिनके संयुक्त परिवार में जितने दंपति जोड़े हैं, उतने ही सिलेंडर मतलब कनेक्शन उन्हें मिल गए।

कब तक जान लेती रहेगी जहरीली शराब

पिछले दिनों मप्र के मुरैना जिले में जहरीली शराब का कहर बरपा तो करीब 30 लोगों की जानें लेकर ही माना। इससे पहले उज्जैन में 16 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। इन कांडों से पहले वैध या अवैध शराब के कारोबारी न सिर्फ प्रदेश के इन दो जिलों बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी, ऐसी कितनी घटनाओं में कितनी जिंदगियों से खेल चुके हैं, उनका जिक्र करने लगें तो जगह कम पड़ जाएगी। मुरैना कांड के बाद गठित एसआईटी ने अपनी जांच में बताया कि लॉकडाउन के कारण की गई शराबबंदी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाने का काम शुरू हुआ। अब वह बड़े स्तर पर फैल गया है।

दरअसल, सरकार साल दर साल जिस तरह शराब के दामों में वृद्धि कर रही है, उससे वह आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। न तो सरकार को समझ में आ रहा है और न ही कोई सरकार को अब तक यह समझा पाया है कि इस नीलामी की दरें शराब के उपभोग के अंधाधुंध बढ़े बिना ज्यादा नहीं बढ़ सकती और इनके लिए शराब का उपभोग बढ़ाना ही है तो मद्यनिषेध अभियान का ढोंग क्यों? सरकारी ठेकों के समानांतर शराब का जो अवैध कारोबार कल्पनातीत पैमाने पर चलता रहता है, उसके उत्पादों के सबसे बड़े कहें या ज्यादातर ग्राहक वे 'गरीब' होते हैं जो सरकारी ठेकों की 'महंगी' शराब नहीं खरीद सकते। शायद इसीलिए इस अवैध कारोबार का हाल देश में गरीबों की होकर रह गई दूसरी चीजों जितना ही बुरा है। वहां मौतें बांटने वाले **धंधेबाज** किसी भी हद से क्यों न गुजरते रहें, आबकारी विभाग और पुलिस को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनकी जेबें भरी जाती रहें और शांति व्यवस्था के लिए कोई बड़ी समस्या न खड़ी हो।

यही कारण है कि कई बार प्रदेशों की राजधानियों तक में, जहां प्रदेश सरकारें बसती हैं, उनकी नाक के नीचे डंके की चोट पर कायम अवैध शराब का साम्राज्य अपने गुल खिलाता रहता है। प्रायः हर ऐसे गुल के खिलने के वक्त सोती पकड़ी जाने वाली सरकारें इनके खिलने के बाद हड़बड़ाकर नींद से जागती हैं तो दिखावे की तेजी दिखाकर पीड़ितों के लिए मुआवजे व मजिस्ट्रेटी जांच के ऐलान के साथ धंधेबाजों की गिरफ्तारियां करातीं और 'जिम्मेदार' ठहराए गए अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाइयों के कागजी कोड़े बरसाने लग जाती हैं।

लेकिन होता यह है कि जल्दी ही सरकारें फिर झपकी लेने लग जाती हैं और उनका अमला मौका ताड़कर सारी कागजी कार्रवाई को चुपके से खत्म कर देता है। फिर अगली त्रासदी होने से पहले किसी को यह भी देखने की फुरसत नहीं होती कि व्यवस्था पर भारी पड़ रहे शराब-कारोबारी उन 18 वर्ष से कम उम्र वालों यानी अवयस्कों को भी शराब बेच व पिला रहे हैं, जिन्हें तम्बाकू के उत्पाद बेचने तक की कानूनी मनाही है। यह प्रशासनिक काहिली सरकारें बदलने के बाद भी खत्म नहीं होती। इसीलिए आमतौर पर किसी को मालूम नहीं हो पाता कि किसी वैध-अवैध शराब कांड में हुई मौतों के किसी मामले में किस स्तर पर क्या जांच हुई, कौन-कौन दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हालात के दूसरे पहलू पर जाएं तो इस मामले में सरकारें या राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, उनका स्वरूप निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाली राजनीतिक पार्टियां भी इतनी स्वार्थांध हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है, उसके दौरान शराब बांटने की घटनाओं को रोकना चुनाव आयोग के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। आम लोगों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ गुस्सा उभरता है तो उसको भी राजनीतिक रंग देकर भटका दिया जाता है।

देश में उदारीकरण व्यापने के बाद तो लगता है कि ऐसी त्रासदियों का एक खास वर्ग चरित्र भी है। विदेशी निवेश के लिए लालायित सरकारें निवेशकों की 'मांग' पर देशभर में अमीरों के लिए बेहतर शराब की खरीद-बिक्री और पीने-पिलाने के एक से बढ़कर एक सुभीतों के सुव्यवस्थित इंतजाम करके प्रफुल्लित हो रही हैं, जबकि गरीबों को 'अवैध' व 'कच्ची' के हवाले करके उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

काश, ये सरकारें समझतीं कि पूर्ण शराबबंदी के विरोध में उनके द्वारा जिन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का प्रायः हवाला दिया जाता रहता है, शराब को जहरीली करने में उनकी कतई कोई भूमिका नहीं है। होती तो सबसे पहले वे आदिवासी मारे जाते, जिनके यहां तमाम उत्सवों का वह अनिवार्य हिस्सा है। दरअसल, वह किसी भी कीमत पर मुनाफा कमाने की बढ़ती जा रही भूमंडलीकरण पोषित प्रवृत्ति है, जो न दवा को दवा रहने दे रही है, न दारू को दारू। यहां तक कि दूध को भी दूध नहीं। दरअसल, सरकार की नीति में खोट होने के कारण अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालांकि इस बार सरकार सख्त नजर आ रही है, लेकिन यह सख्ती कितनी कामयाब होती है, देखना होगा।

● **नवीन रघुवंशी**

सरकार को राजस्व की चिंता

शराब की बिक्री मप्र सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए सरकार चाहकर भी शराबबंदी जैसा कदम नहीं उठा पा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराब की नई दुकानें खोलने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का मानना है कि शराब की अधिक दुकानें खोलने से जहरीली शराब पीने को लोग मजबूर नहीं होंगे। मुरैना शराब कांड के बाद गृहमंत्री के बयान को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने का खाका तैयार कर लिया था। आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत और 5 हजार की आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में एक-एक शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव मांगा था। लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं हुए तो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। दरअसल, शराब की बिक्री सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। वह न तो इसे बंद करा सकती है और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक दुकानें खुलवा सकती है। दरअसल, सरकार के सामने समस्या यह है कि वह पहले से 2 लाख करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है। उस पर हर माह लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार शराबबंदी के बारे में सोच भी नहीं सकती है।

भारत में उगेगा रंगीन कपास

अगर आप ये सोचते हैं कि प्राकृतिक कपास केवल सफेद रंग का होता है, तो ये खबर आपको आश्चर्य में डाल सकती है। भारत रंगीन कपास की व्यावसायिक खेती के लिए इसके बीजों की प्रजाति जारी करने से कुछ ही महीने दूर है। शोधकर्ता 16301डीबी और डीडीसीसी1 का फार्म ट्रायल कर रहे हैं। इन प्रजातियों से भूरे रंग के कपास का उत्पादन होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के कपास पर ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट (एआईसीआरपी-कॉटन), कोयम्बटूर का नेतृत्व कर रहे एएच प्रकाश कहते हैं, इस साल 21 अप्रैल को आईसीएआर की कमेटी की वार्षिक बैठक होगी, जिसमें इस कपास की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद इसकी प्रजातियों को व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया जाएगा। दूसरे संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ये एजेंसी सुनिश्चित कर रही है कि इस कपास के उत्पादन में निरंतरता बनी रहे।

कपास की 16301डीबी प्रजाति को आईसीएआर की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर), नागपुर ने विकसित किया है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा उगाए जा रहे गोसोपियम हरसटम की पांच रंगीन कपास की प्रजातियों के मूल्यांकन के बाद इस कपास की प्रजाति विकसित की गई है। वहीं, डीडीसीसी-1 प्रजाति को एग्रीकल्चरल साइंस यूनिवर्सिटी, धारवाड़ (कर्नाटक) ने विकसित किया है। भारत और अन्य उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाने वाली जी-अरबोरियम प्रजाति के 6 रंगीन कपास के मूल्यांकन के बाद ये प्रजाति विकसित की गई है। प्रकाश ने कहा कि 15 अन्य रंगीन कपास की प्रजातियों को लेकर परीक्षण चल रहा है और इनके परिणाम अलग-अलग चरणों में हैं।

रंगीन कपास को दोबारा पुनर्जीवित करने में कामयाबी एआईसीआरपी की तीन दशकों की मेहनत का परिणाम है। विज्ञानियों का कहना है कि रंगीन कपास के अस्तित्व को बचाने का एक ही उपाय है कि इसकी प्रजातियों के जीन समूहों को सुधार कर इतना मजबूत और लंबा किया जाए कि आधुनिक टेक्सटाइल मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नई अनुवांशिक प्रजाति तैयार करने में काफी वक्त लगता है और इसकी प्रक्रिया थकाऊ है। एआईसीआरपी के अधीन खंडवा के बीएम कृषि कॉलेज के पौधा प्रजनक देवेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं, पहले चरण में इच्छुक विशेषताओं वाले कपास की रंगीन और सफेद प्रजातियों का चुनाव किया जाता है। इसके बाद छोटे गमलों में इनका संकरण कराया जाता है। इससे नई प्रजातियां तैयार होती है, जिनमें अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं वांछित होती हैं और कुछ नहीं।

उद्योग के लिए तैयार

आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग में वैसा कपास पसंद किया जा रहा है जिसके फाइबर की लंबाई 25-29 एमएम हो। फिलहाल दो प्रजाति 16301डीबी व डीडीसीसी1 को व्यावसायिक तौर पर जारी करने के योग्य माना जा रहा है। इनके धागे की लंबाई 23-24 एमएम है, जो मीडियम कैटेगरी में आती है और हथकरघा उद्योग द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इन धागों की मजबूती 20-23 जी/टीईएक्स (प्रति 1000 मीटर में ग्राम के हिसाब से) है, जो टेक्सटाइल उद्योग के मानक के अधीन है। इसका उत्पादन भी अधिक होता है। एक हैक्टेयर में इस प्रजाति से 1200-1800 किलोग्राम कपास का उत्पादन होता है जबकि सफेद कपास का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 466 किलोग्राम है। हालांकि, इन प्रजातियों का सबसे अधिक फायदा ये है कि इससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और इसके उत्पादन में खर्च भी कम होता है। भारत में कुल कृषि उत्पादन में जितने कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, उसका आधा हिस्सा केवल सामान्य सफेद कपास के उत्पादन में इस्तेमाल हो जाता है। इसकी तुलना में रंगीन कपास की प्रजातियां इस तरीके से तैयार की गई हैं कि वो कीड़े के हमले से बच जाती है और कम कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इन्हें रंगने की जरूरत या तो एकदम कम पड़ती है या बिल्कुल भी नहीं। रंगने में ज्यादा पानी और जहरीले रसायन की जरूरत पड़ती है। सबसे अहम बात कि प्राकृतिक तौर पर रंगीन कपास किसानों की अनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कॉटन पर निर्भरता कम करती है, जो (बीटी कपास) किसानों के लिए काफी खर्चीला साबित हुआ है और बड़े पैमाने पर कपास की खेती करने वाले देश पर इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है।

पहला संतोषजनक रंगीन कपास केएस 94-2 था, जिसे साल 1996 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय खंडवा कैम्पस ने जारी किया था। बादामी भूरे रंग के कपास की प्रजाति कम उत्पादन के कारण फेल हो गई। साल 2000 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कपास पर टेक्नोलॉजी मिशन के तहत कई तरह के रंगीन कपास की प्रजातियां तैयार की गईं। लेकिन किसी भी प्रजाति में वो मजबूती या लंबाई नहीं थी, जैसी कपड़ा उद्योग को चाहिए। साल 2013 में सीआईसीआर ने गहरे भूरे रंग के कपास की संकर प्रजाति एमएसएच 53 तैयार की। इसे जी-हरसटम और जी-बरबाडेंस के साथ दो जंगली प्रजातियों जी-रैमोंडी और जी-थर्बर प्रजातियों में क्रॉस ब्रीडिंग कराकर तैयार किया गया था। ऐसा संभवत: पहली बार हुआ था कि जंगली प्रजातियों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराकर कपास की नई प्रजाति विकसित की गई थी। ये प्रजाति अभी तक प्रयोग के स्तर पर नहीं पहुंची है। अब तक रंगीन कपास को जैविक होने के बावजूद बढ़िया कीमत नहीं मिलती है। कपड़ा उद्योग में भी इसके इस्तेमाल को लेकर दिलचस्पी नजर नहीं आती है। इस प्रजाति के कपास के धागे की लंबाई और मजबूती तो मसला है ही, मार्केट यार्ड में रंगीन कपास को स्टॉक कर रखने या अलग से बेचने के लिए विशेष सुविधा भी नहीं मिलती है। लेकिन, उपभोक्ताओं में पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता को देखते हुए इसकी मांग बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में यूरोप के कुछ देशों में प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास की मांग बढ़ी है और अनुमान है कि हर साल 5-6 लाख गांठ की सप्लाई हो रही है। बाजार में रंगीन कपास की बढ़ती मांग से लगता है कि इसका कारोबार वापस पटरी पर लौटेगा।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अब गिद्ध और घड़ियाल स्टेट बनेगा मप्र

मप्र अब गिद्ध और घड़ियाल स्टेट बनने की राह पर है। सरकार का दावा है कि जल्द ही उसे ये तमगा मिल जाएगा। मप्र टाइगर स्टेट पहले से ही था। हाल ही में वो लेपर्ड स्टेट भी बन गया है। मप्र के वन मंत्री विजय शाह ने दावा किया है कि मप्र टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट होने के बाद अब गिद्ध और घड़ियाल की संख्या के मामले में भी देश में नंबर वन होने जा रहा है। इस मामले की रिपोर्ट आने के बाद मप्र गिद्ध स्टेट और घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी हासिल कर लेगा। राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए पहले ही तीन पुरस्कार हासिल कर चुकी है। प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व एरिया वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं और अब सरकार नए वन क्षेत्र विकसित कर वन्य जीवों का पुनर्वास करने की योजना बना रही है।

मप्र सरकार के मंत्री का दावा है कि प्रदेश को जल्द ही घड़ियाल और गिद्ध स्टेट का खिताब मिल जाएगा। वन मंत्री विजय शाह कहते हैं कि टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट होने के बाद अब घड़ियाल और गिद्ध की संख्या के मामले में भी मप्र देश में नंबर वन की स्थिति में पहुंच गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही मप्र को यह दो खिताब और मिल जाएंगे। घड़ियालों के लिए संरक्षित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में एक बार फिर घड़ियाल सहित जलीय जीवों की गणना के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार फरवरी के पहले हफ्ते में सर्वे शुरू होगा। एक पखवाड़े तक चलने वाली जलीय जीवों की गणना में पार्वती नदी के 60 किमी के हिस्से सहित कुल चंबल के 495 किलोमीटर तक के हिस्से में होगी। इसमें जलीय जीवों और पक्षियों की गणना की जाएगी। बताया गया है कि घड़ियाल व अन्य जलीय जीवों का वार्षिक सर्वेक्षण जिले की सीमा में पार्वती नदी के बड़ौदिया बिंदी से प्रारंभ होगा। जिसके बाद अमला 60 किलोमीटर पार्वती नदी में सर्वे करने के उपरांत चंबल नदी में प्रवेश करेगा और फिर जिले की सीमा में चंबल नदी के पाली घाट होते हुए भिंड तक पहुंचेगा। पूरे एक पखवाड़े तक चलने वाले इस सर्वे के लिए चंबल अभयारण्य प्रबंधन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस सर्वे में विभागीय टीम के साथ ही वन्यजीव संस्थान देहरादून के रिसर्च स्कॉलर, अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे।

मप्र में 2019 में पक्षी गणना के मुताबिक 8397 गिद्ध थे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं। इनकी संख्या बढ़ने का कारण यह भी है कि भोपाल के केरवा इलाके में 2013 में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया था और इसे बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और मप्र सरकार की ओर से संयुक्त तौर पर संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है। यहां के आंकड़ों से अन्य राज्यों की तुलना की गई तो यह सर्वाधिक निकले। अकेले चंबल नदी में ही 1255 घड़ियाल मिले थे। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था। चार दशक पहले घड़ियालों की संख्या खत्म होने की स्थिति में थी। तब दुनियाभर में केवल 200 घड़ियाल ही बचे थे। इनमें से पूरे भारत में 96 और चंबल नदी में 46 घड़ियाल ही थे। वर्ष 1978 में संरक्षित किए गए राष्ट्रीय घड़ियाल चंबल अभयारण्य के 435 किलोमीटर के इलाके में वर्ष 1984 में वार्षिक गणना शुरू की गई। हालांकि वर्ष 2016 तक केवल चंबल के 435 किलोमीटर दायरे में ही गणना होती थी, लेकिन वर्ष 2017 में इस गणना में श्योपुर जिले की सीमा में पार्वती नदी का 60 किलोमीटर का हिस्सा भी शामिल किया गया। वर्ष 2020 में घड़ियाल अभयारण्य में हुई वार्षिक जलीय जीव गणनों में 1859 घड़ियाल पाए गए थे। वहीं 710 मगरमच्छ मिले। विशेष बात यह है कि श्योपुर से भिंड तक फैले इस चंबल अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

2014 की गणना के अनुसार मप्र तेंदुआ स्टेट है। गणना के समय कर्नाटक दूसरे नंबर पर था। मप्र में 1817 तेंदुए पाए गए थे तो कर्नाटक में इनकी संख्या 1129 थी। वन विभाग कहता है कि मप्र में तेंदुए बढ़कर 2200 से अधिक हो सकते हैं। 2006 में सर्वाधिक 300 बाघों के साथ यह टॉप पर था, लेकिन 2010 व 2014 की गणना में कर्नाटक और उत्तराखंड से पिछड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया था। मप्र को पिछले साल फिर 526 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इस बीच दो-चार बाघों के कम होने की भी खबरें आई हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

पन्ना मॉडल बनेगा आधार

मप्र में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन विभाग अभयारण्यों में पन्ना मॉडल अपनाएगा। गौरतलब है कि एक समय पन्ना बाघविहीन हो गया था, लेकिन आज वहां 55 बाघ हैं। वर्ष 2008 में मप्र के जिस पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ खत्म हो गए थे। वर्ष 2018 में देशभर में हुई बाघों की गिनती में पन्ना पार्क में 55 बाघ पाए गए हैं। हालांकि इससे अधिक बाघ प्रदेश के कई अन्य टाइगर रिजर्व में भी हैं, लेकिन पन्ना ने यह संख्या शून्य के बाद पाई है। इसके बाद करीब एक दर्जन शावकों ने भी जन्म लेकर पार्क को गुलजार किया है और पार्क में बाघों की संख्या 55 से आगे निकल गई है। यही कारण है कि यूनेस्को ने पन्ना को विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसका असर भी पन्ना के पर्यटन पर दिखाई देने लगा है। उपलब्धि को कायम रखने के लिए यहां बाघों के प्रबंधन और पर्यटन को लेकर नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। पार्क में उन स्थानों को भी पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, जहां अब तक पर्यटकों को जाने की मनाही थी। गौरतलब है कि शिकार की घटनाओं के चलते वर्ष 2008 में पन्ना से बाघ खत्म हो गए थे। वर्ष 2009 में कान्हा व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दो बाघिन और पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघ को पन्ना पार्क में लाया गया। तीनों की कॉलर आईडी लगाकर निगरानी की गई और दो साल में खुशखबरी आई। थोड़ी सुरक्षा और देखभाल मिली, तो बाघों का कुनबा लगातार बढ़ने लगा। वर्ष 2014 के बाघ आंकलन में पार्क में सिर्फ 10 बाघ गिने गए थे, जो चार साल में ही बढ़कर 55 हो गए। वर्ष 2018 में भी मार्च से पहले गिनती हुई थी। इसके बाद पार्क में 12 नवजात शावक देखे गए। इनमें से कुछ अब दो साल के होने वाले हैं। इसी करामात ने पन्ना पार्क को विश्व विरासत संस्था की नजर में ला दिया और संस्था ने 2020 में पन्ना पार्क और शहर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया।

गैंगरीन का दंश

प्यासा और पिछड़ा बुंदेलखंड हमेशा से राजनीतिक रूप से हरा-भरा रहता है। लेकिन इसकी बदहाली पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज यह क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिना जा रहा है। इस क्षेत्र के लोग आर्थिक बदहाली के साथ ही विभिन्न तरह की बीमारियों की चपेट में हैं। मप्र के 7 और उप्र के 7 जिलों वाले इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारों द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास तो हुआ नहीं, लेकिन बीमारियां फैलती गईं। इन 14 जिलों के निवासियों के लिए इस समय गैंगरीन सबसे बड़ा दंश बना हुआ है। हर गांव में लोग इस बीमारी से ग्रसित मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक न ही उप्र और न ही मप्र की सरकार का ध्यान इस ओर गया है।

गैंग्रीन या गैंगरीन एक भयानक और जानलेवा रोग है। शरीर में ब्लड सकुंलेशन ठीक तरह से नहीं होने या फिर किसी खास स्थान के टिश्यू खून के कम प्रवाह और दबाव की वजह से सड़ने-गलने या सूखने लगते हैं तो भयानक और जानलेवा रोग गैंगरीन हो जाता है। यह खास तरह की बीमारी है, जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों में टिश्यूज यानी ऊतक नष्ट होने लगते हैं। इस कारण वहां घाव बन जाता है, जो लगातार फैलता जाता है। समय रहते यदि समस्या का इलाज न किया जाए तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती है। बुंदेलखंड में इस बीमारी के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर महीने लगभग 50 नए मरीज बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अरविंद कनकने के अनुसार बिगड़ी जीवनशैली, खून को ले जाने वाली नसों की बीमारी, बीपी, मधुमेह व हृदय रोगियों को गैंगरीन होने की संभावना ज्यादा रहती है। सर्दियों में यह बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि नसें सिकुड़ने से खून का संचार सही से नहीं हो पाता। बिगड़ा खानपान व धूम्रपान से इस बीमारी के रोगी बढ़ रहे हैं।

मप्र के छतरपुर, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। आलम यह है कि यहां के हर गांव में इसके रोगी मिल रहे हैं। झांसी निवासी 40 वर्षीय युवक को कुछ समय से पैर में सुन्नपन और दर्द की शिकायत बनी हुई थी। इसी दौरान पैर के निचले हिस्से में हल्का घाव हो गया। कुछ ही दिन में दर्द असहनीय हो गया। पैरों में कालापन आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने गैंगरीन बताते हुए पैर काटने की सलाह दी। मरीज एक से दूसरे डॉक्टर को दिखाता रहा। इसी बीच दूसरे पैर के पंजे भी काले पड़ने लगे। बाद में मरीज के दोनों पैर काटने पड़े। सीपरी बाजार निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 8 साल पहले गैंगरीन हो गई थी, तो उनके पैर की दो अंगुलियों को काट दिया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी। कुछ सालों के बाद उन्होंने धूम्रपान करना फिर शुरू कर दिया। इसके बाद यह बीमारी फिर से पनप गई। पंजों में कालापन आने पर डॉक्टर को दिखाया तो गैंगरीन बता दिया। इसके बाद अस्पताल में भर्ती करके व्यक्ति के पैर का पंजा काटना पड़ गया।

गैंगरीन के शुरूआती लक्षणों में हाथ-पैरों में सुन्नपन और नाखून में पीलापन आना है। इसके साथ ही शरीर के उस अंग में तेज दर्द शुरू हो जाता है। बाद में वह अंग काला पड़ने लगता है। जो कि तेजी से बढ़ता जाता है। मधुमेह के अधिकतर रोगियों को अपने खानपान का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में गैंगरीन की मुख्य वजह शुगर की बीमारी ही कारण बनती है। शरीर में यदि खून का प्रवाह किसी कारण से बाधित या कम होता है तो कई तरह की **समस्याएं पैदा** हो जाती हैं। खून के साथ ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है। मगर जब शरीर में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो धमनियों में प्रवाहित होने वाले खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इससे रक्त का प्रवाह भी प्रभावित होता है और टिश्यूज इसका पूरा लाभ भी नहीं ले पाते हैं। इस स्थिति में धीरे-धीरे ये टिश्यू मरने लगते हैं, जो बाद में गैंगरीन का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान करना और हृदय रोगियों को भी यह बीमारी होने की संभावना रहती है। सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर हर महीने 50 नए रोगी इस बीमारी के मिल रहे हैं। दस साल में डेढ़ गुने तक मरीज बढ़ गए हैं।

गैंगरीन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। इनमें सूखा गैंगरीन, नम गैंगरीन और गैस गैंगरीन शामिल हैं। सूखा गैंगरीन शरीर के बाहरी हिस्सों में विकसित होता है। जबकि, नम गैंगरीन शरीर के उन हिस्सों में विकसित होता है, जहां के टिश्यूज नम होते हैं। जैसे हमारे मुंह या फेफड़ों में। गैस गैंग्रीन वह होता है, जिसमें त्वचा के टिश्यूज में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो दूषित गैस का उत्सर्जन करते हैं। इससे आसपास की त्वचा में तेजी से संक्रमण फैलता है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

डायबिटीज के कारण होती है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज

डायबिटीज केवल शरीर के किसी एक हिस्से पर अपना असर नहीं दिखाती, बल्कि यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती है। ब्लड फ्लो कम होने से शरीर में लगी किसी चोट या घाव को भरने में बहुत समय लगता है। हाथ व पैर में ब्लड का फ्लो कम होना पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहलाती है। जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनमें अल्सर और गैंगरीन जैसी समस्या होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। न्यूरो सर्जन डॉ. दिनेश राजपूत कहते हैं कि धूम्रपान करने वालों, मधुमेह और हृदय रोगियों को गैंगरीन होने की संभावना अधिक रहती है। यह बीमारी तीन प्रकार की होती है। बुंदेलखंड में ड्राई गैंगरीन के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। औसतन हर महीने बुंदेलखंड के 35-40 नए रोगी दिखाने के लिए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं।

तिरंगे का अपमान कौन जिम्मेदार...?

26 जनवरी को महापर्व गणतंत्र और तिरंगे का जिस तरह अपमान हुआ, वह बर्दाश्त से बाहर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल उन्मादियों ने जिस तरह का उपद्रव किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गणतंत्र और तिरंगे के अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है? किसान, पुलिस या फिर सरकार? जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इससे देश की साख गिरी है और भारतीय गणतंत्र पर दाग भी लग गया है।

● राजेंद्र आगाल

देश है तो राजनीति है, किसानी है, व्यापार है, संगठन है। देश नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह की कसमें हम हर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर खाते हैं। लेकिन 72वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान सबक दे गया है। देश के धैर्य को चुनौती देने वालों पर परम सख्त होने का समय आ गया है। देश का किसान भोला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन इतना भी भोला नहीं कि वह अपना अच्छा और बुरा न समझे। आंदोलनकारी भी जानते हैं कि देश का 95 प्रतिशत किसान अपने खेतों और घरों में हैं। कुछ मुट्ठीभर बड़े किसान, आढ़तिए और उन्हें समर्थन दे रहे राजनीतिक दल इस आंदोलन को खाद-पानी दे रहे थे। जिन्होंने किसानों का कभी लाभ नहीं किया, वे भी उनकी रहनुमाई में पीछे नहीं रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान आंदोलन में ऐसे लोग भी समा गए, जिनके कारण न केवल गणतंत्र का मानमर्दन किया गया, बल्कि तिरंगे का भी अपमान किया गया।

गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी में जो हिंसा और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हुईं, उनसे सारा देश उद्वेलित है। हिंसात्मक घटनाएं तो कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में भी होती रहती हैं, परंतु दिल्ली में इस तरह का उपद्रव और वह भी 26 जनवरी को, केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रैक्टर रैली से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय से उसे ऐसे निर्देश मिले थे कि स्थिति बिगड़ने पर भी किसी हालत में गोली नहीं चलानी है। अगर ऐसा आदेश था तो वह सही था, परंतु यह भी सही है कि इस आदेश के अनुपालन में दिल्ली पुलिस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस घटना में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक

26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है, परंतु इससे हमें कुछ सबक लेने होंगे। सबसे पहला और जरूरी सबक यह है कि असंतोष की चिंगारी को ज्यादा दिनों तक सुलगने नहीं देनी चाहिए। सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, उनके विरुद्ध किसानों के एक तबके की आवाज धीरे-धीरे मुखर होती जा रही थी और उनके बीच एक उकसाने वाला संदेश जा रहा था। चूंकि समस्या इतने दिनों तक खिंचती रही इसीलिए थोड़ा सा मौका मिलने पर अराजक तत्वों ने दिल्ली में माहौल खराब कर दिया। दूसरा सबक यह है कि आज की तारीख में कई प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्व सक्रिय हैं। ये तत्व मौके की तलाश में रहते हैं। सरकार विरोधी कोई भी मुद्दा हो, वे उसमें घुस जाते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। प्रथमदृष्टया जो रिपोर्ट आई हैं, उनके अनुसार खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था ने आंदोलन में अच्छी-खासी घुसपैठ कर ली थी। इस संगठन ने करीब दो हफ्ते पहले घोषणा की थी कि जो भी गणतंत्र दिवस के दिन लालकिले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे ढाई लाख डॉलर दिए जाएंगे। इसी संस्था के सरगना ने पंजाब के किसानों का आव्हान किया था कि वे 25-26 जनवरी को दिल्ली की बिजली काट दें, ताकि राजधानी अंधेरे में डूबी रहे। ऐसे तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

देश के स्वाभिमान को झटका

कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच भारी संघर्ष देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर जमकर तोड़फोड़ की और लाल किले में भी दाखिल होकर अपना झंडा (निशान साहिब या निशान साहेब) फहरा दिया। हालांकि, पुलिस ने पहुंचकर झंडा उतारा और प्रदर्शनकारियों को लाल किले से हटा दिया, लेकिन 26 जनवरी को दुनिया ने जो देखा है उससे देश के स्वाभिमान को गहरा झटका लगा है। किसान संगठन और पुलिस एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं तो सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसान संगठनों की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार कहते हैं कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली के लिए समय और मार्गों को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन किसान उन निर्धारित मार्गों से हटाकर दिल्ली में प्रवेश कर गए। उनकी ओर से बर्बरता की गई, जिसमें 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वह कहते हैं कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।

दिल्ली पुलिस जिम्मेदार

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से जो निर्धारित रूट दिया गया था, ट्रैक्टर मार्च उसी रूट पर शुरू हुआ, लेकिन चिन्हित जगहों पर बैरिकेड्स ना लगाकर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसी का नतीजा यह हुआ कि ट्रैक्टर सवार भटककर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। परिणाम स्वरूप अवांछनीय तत्वों और कुछ संगठनों को मौका

खेती अगर घाटे का सौदा, तो इसमें रईसों की रुचि क्यों?

भारत कृषि प्रधान देश है। यहां खेती-किसानी में आधी से अधिक आबादी लगी हुई है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान केवल 16 से 17 फीसदी के आसपास ही रहता है। देश में एक किसान की औसत मासिक आय भी 6,000 रुपए से अधिक नहीं हो पा रही है। यह 200 रुपए रोज की औसत दिहाड़ी है, जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है। हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। करीब 70 फीसदी किसान खेती के अतिरिक्त दैनिक कमाई पर निर्भर हैं। ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा करीब 40 फीसदी से भी कम है। सवाल यह है कि अगर खेती-किसानी की स्थिति इतनी बुरी है, तो देश के पूंजीपति (रईस) और उद्योगपति इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? कुछ साल पहले जब फिल्मी महानायक अमिताभ बच्चन ने उप्र के जिले बाराबंकी में उनकी पसंदीदा पार्टी (सपा) की सरकार में जमीन खरीदी, तो बसपा की सरकार बनते ही मायावती ने उन्हें किसान मानने से इंकार करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की। अमिताभ बच्चन किसान बनना चाहते हैं। बाराबंकी में उन्होंने इसके लिए जमीन भी खरीदी। सवाल यह है कि अमिताभ बच्चन, जिनकी हर महीने करोड़ों की कमाई है, किसानी क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब शायद हम सभी को कोरोनाकाल में अच्छी तरह मिल चुका है। कोरोनाकाल में जब दूसरे उद्योगों की तरह फिल्म उद्योग भी ठप पड़ गया, तब एकमात्र कृषि ही एक ऐसा उद्योग या कहें कि व्यवसाय रहा, जिसमें ताला नहीं लगा। दूसरा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हर माह जो करोड़ों की आय होती है, उसको कृषि आय बताकर सरकार के आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंकने का एक आसान रास्ता बन जाता है, क्योंकि कृषि उपज पर आयकर नहीं लगता।

मिला और उन्होंने इस यात्रा में विघ्न डालने का कुत्सित प्रयास किया। भाकियू इस कृत्य में लिप्त लोगों से खुद को अलग करती है। आंदोलन में विघ्न डालने वाले ऐसे तत्वों को भाकियू चिन्हित करने का काम करेगी।

किसान नेता जिम्मेदार

भाजपा प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि किसान संगठनों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, जिन शर्तों पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने इजाजत दी थी। प्रदर्शनकारियों के साथ कोई किसान नेता नेतृत्व करता नहीं दिखा। किसान नेता पूरी तरह से मैदान छोड़कर भाग गए और उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया। पुलिस ने पूरी तरह से संयम बरता कि कोई निर्दोष न मारा जाए। वहीं, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी पुलिस के संयम की तारीफ की। पुलिस ने उपद्रवियों को क्यों नहीं रोका, इस सवाल पर गौरव भाटिया ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से किसान नेता जिम्मेदार थे। इसके जिम्मेदार विपक्ष के नेता भी हैं, जो पूरी घटना को भड़काने वाले हैं।

सरकार है जिम्मेदार

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं कि 6 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो घटना हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। दो महीने से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और गृहमंत्री चुनाव मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। इन्हें किसानों की समस्या से नहीं बल्कि चुनाव की ही फिक्र है। इसी का नतीजा है कि देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हुआ है, उससे देश का सिर झुक गया है।

किसान नेता युद्धवीर कहते हैं कि हम लाल किले पर पहुंचे और यह किसान की जीत है। वहीं, किसान नेता हन्नान मुल्ला ने हिंसक प्रदर्शन से किनारा करते हुए कहा कि इस पूरी घटना की वो निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी दिल्ली में उत्पाद मचा रहे थे और लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे। इससे जाहिर होता है कि पुलिस ने उन्हें यह सब करने की इजाजत दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि पहले इन कानूनों को किसानों को विश्वास में लिए बिना पारित किया गया था। और फिर पूरे भारत में और पिछले 2 महीनों से दिल्ली के पास डेरा डाले हुए किसानों के विरोध के बावजूद वे उनसे निपटने में बेहद लापरवाह हैं। केंद्र को किसानों के साथ जुड़ना चाहिए और बेरहम कानूनों को निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर होने वाली चिंता और दर्दनाक घटनाओं से बुरी तरह परेशान हूं। केंद्र के असंवेदनशील रवैये के कारण इस स्थिति के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी दिल्ली में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इसके लिए किसका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए? सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या जो बाइडन का? राउत कहते हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं किया जा सकता।

किसान आंदोलन का इतिहास

कहते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है। आज से करीब 32 साल पहले 1988 में 25 अक्टूबर से नवंबर की शुरुआत तक लगभग हफ्तेभर दिल्ली में किसानों की ऐसी ही घेरेबंदी देखी गई थी। तब भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के करिश्माई नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में लगभग पांच लाख किसानों ने 35 मांगों की भारी-भरकम फेहरिस्त के साथ बोट क्लब पर लगभग कब्जा जमा लिया था, जिससे कुछ गज की दूरी पर सत्ता-केंद्र नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ संसद भवन है। तब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने ही वाला था। खासकर पश्चिमी उप्र से आए किसानों की बड़ी मांगों में गन्ने की ज्यादा कीमत, बिजली और पानी के शुल्क से मुक्ति जैसे अहम मुद्दे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह गोलबंदी इतनी बड़ी थी कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का पूरा लंबा-चौड़ा इलाका किसानों से पटा पड़ा था। टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन दिवंगत राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अहम ताकत का प्रदर्शन था। तब कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज थी। फिर भी भाकियू तब मोटे तौर पर पश्चिमी उप्र तक सीमित एक क्षेत्रीय ताकत ही थी। उसके विपरीत मौजूदा किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे देश के फलक पर फैला है और उसकी मांगें भी अधिक महत्वाकांक्षी हैं। फिर, भाकियू और मौजूदा किसान आंदोलन की सामाजिक संरचना भी काफी अलग है। भाकियू का आंदोलन मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ और पश्चिमी उप्र के जाट किसानों की गोलबंदी थी, अलबत्ता भाकियू की पैठ दूसरी जातियों के किसानों में भी मजबूत थी। इसके विपरीत मौजूदा आंदोलन देश के विभिन्न राज्यों, विविध जातियों और विभिन्न तबके के किसानों का ढीलाढाला इंद्रधनुषी शमियाने जैसा है, जिसमें कई सांस्कृतिक रंग एकसाथ खिल रहे हैं। इसी बहुवर्गीय या विभिन्न तबके वाली रूपरेखा के कारण मौजूदा किसान आंदोलन में प्रतिकूल विचारधाराओं वाले किसान-समूहों की शिरकत है। कुछ, जैसे हनन मोल्ला माकपा से जुड़े हैं, तो मप्र और मध्य भारत के दूसरे राज्यों से बड़ा जत्था अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) से संबंधित है, जबकि पंजाब के कुछ समूह अतीत में भाकपा-माले से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत सहित भाकियू के लगभग 40 विभिन्न गुटों का बड़ा-सा जमावड़ा भी है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संयोजक बिनोद आनंद ने बताया कि 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भाकियू के पास सिर्फ प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन और बीबीसी ही माध्यम था। आज के किसान आंदोलन के लिए 24 घंटे के न्यूज चैनलों और हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा है।

आखिर कहां फंसा है पेंच?

कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच सबसे प्रमुख मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार से एमएसपी की गारंटी चाहिए। सरकार ने उनसे कह दिया है कि वह एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं हैं, वे एमएसपी की गारंटी को लेकर नए कानून की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों किसान एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं और इससे कम पर पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं हैं? दरअसल, एमएसपी पर सरकार का कहना है कि वह इसकी पहले से चली आ रही व्यवस्था को खत्म नहीं करेगी और इसे पहले की तरह ही जारी रखेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार नए कृषि कानून लागू होने के बाद भी पहले की तरह ही हर साल फसलों के समर्थन मूल्य का ऐलान करती रहेगी। एमएसपी पर अब तक चली आ रही व्यवस्था से किसानों को दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार 23 फसलों की एमएसपी घोषित करती है लेकिन उन सभी को खरीदती नहीं है। यहां तक कि वह जिन मुख्य फसलों जैसे गेंहू और धान को खरीद में तरजीह देती है, उनका भी करीब-करीब आधा हिस्सा ही वह खरीदती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में देश में 1184 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ जिसमें से 511 लाख टन ही सरकार द्वारा खरीदा गया। इसी साल हुए 1076 लाख टन गेहूं में सरकारी खरीद की मात्रा 390 लाख टन थी। इसके अलावा 231 लाख टन दाल में से सिर्फ 28 लाख टन और 454 लाख टन मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा आदि में से चार लाख टन की ही सरकारी खरीद हुई। यानी सरकार ने इन फसलों की कुल पैदावार का करीब 32 फीसदी हिस्सा ही खरीदा। ऐसा भी सिर्फ उन फसलों के मामले में किया गया जिन्हें सरकार खरीदती है। सरकार एमएसपी घोषित करने के बाद भी कुछ फसलें बिलकुल नहीं खरीदती। यही वजह है कि एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था से गिने-चुने किसानों को ही फायदा मिलता है। केंद्र सरकार की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की एमएसपी पर खरीद का फायदा देश के केवल 6 फीसदी किसानों को ही मिलता है।

एमएसपी पर खरीदी घट रही

बीते सालों के आंकड़ों को देखें तो एमएसपी पर फसल की खरीद साल-दर-साल घटती जा रही है। देश में साल 2015-16 में जहां गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए 20,088 खरीद केंद्र थे। वहीं साल 2016-17 में इसकी संख्या घटकर 18,181 रह गई। इसके बाद 2017-18 में खरीद केंद्रों की संख्या और कम होकर 17,596 पर पहुंच गई। 2018-19 में गेहूं के खरीद केंद्रों में बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़ा 19,280 पर पहुंच गया। लेकिन अगले ही साल 2019-20 गेहूं के खरीद केंद्रों में काफी ज्यादा की गिरावट आई और साल 2015-16 की तुलना में 26.13 फीसदी की कमी के साथ ये संख्या घटकर सिर्फ 14,838 ही रह गई है।

2019-20 में पूरे देश में 14,838 खरीद केंद्रों में से करीब 95 फीसदी खरीद केंद्र राज्य एजेंसियों के थे। गेहूं खरीदी के लिए देशभर में केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महज 728 खरीद केंद्र थे, जो कि कुल खरीद केंद्र का सिर्फ पांच फीसदी ही है। इन केंद्रों की घटती संख्या का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। साल 2019-20 के रबी खरीद सीजन में कुल 35.6 लाख किसानों को एमएसपी का लाभ मिला था जो कि 2018-19 में लाभान्वित 39.8 लाख किसानों के मुकाबले करीब चार लाख कम है, जबकि इस दौरान गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ा है। साल 2016-17 में गेहूं का कुल उत्पाद 9.85 करोड़ टन था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 10.36 करोड़ टन हो गया। इसमें से केवल 3.4 करोड़ टन की खरीद ही एमएसपी पर की गई थी, यानी कुल उत्पादन के करीब 33 फीसदी की ही खरीदी एमएसपी पर हुई। बाकी बची 67 फीसदी फसल को किसान प्राइवेट बाजार या घरेलू बजार में बेचता है, इसमें से अधिकांश हिस्सा किसान को एमएसपी से काफी कम दाम पर बेचना पड़ता है। एमएसपी पर काफी कम फसल खरीदे जाने के चलते ही किसान अब चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की पूरी व्यवस्था को ही बदल दे और एक नई व्यवस्था लाकर उनकी परेशानी को दूर करे।

किसानों को किस बात का डर

केंद्र सरकार हर साल अपने फसल खरीद लक्ष्य को संशोधित करती है। वह हर साल यह तय करती है कि उसे किसानों से कितना अनाज खरीदना है। इससे ही यह भी तय होता है कि उसे एमएसपी पर प्रत्येक किसान से अधिकतम कितना अनाज खरीदना है। कुल मिलाकर कहें तो किसान चाहे कितना ही अनाज पैदा करें, लेकिन सरकार उनसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अनाज नहीं खरीदती है। बाकी बची फसल को किसान बाहर बेचता है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के मुताबिक अब

करोड़ों स्वाहा करने वाले किसान गरीब हैं क्या?

एक और किसान नेता हैं योगेंद्र यादव। किसान नेता का रूप उन्होंने अभी हाल में धारण किया है। एक साल पहले वह जेएनयू में फीस वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर थे। उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और अब कृषि कानूनों के खिलाफ। किसान आंदोलन में ऐसे आदतन आंदोलनकारियों की अच्छी-खासी भागीदारी है। दिल्ली की सड़कों पर डेरा डाले और किसान हित के बहाने दिल्ली-एनसीआर वालों की नाक में दम करने वाले ऐसे किसान नेता अपने समर्थकों की हर अराजक गतिविधि पर आंखें मूंदे रहे, वह चाहे पंजाब में डेढ़ हजार मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त करना हो या हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर की सभा में तोड़फोड़ करना। मीडिया का एक हिस्सा भी किसान आंदोलन के नाम पर हो रही अराजकता की अनदेखी करता रहा। वह उस अतिवाद की भी पैरवी करता रहा, जो किसान नेता सरकार और सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद भी दिखा रहे थे। किसान प्रेम में पुलकित मीडिया का यह हिस्सा इसकी भी खुशी-खुशी उपेक्षा करता रहा कि किसान नेता किस तरह किसानों की दीनदशा का हवाला दे रहे और सैकड़ों किलोमीटर दूर से हजारों ट्रैक्टर दिल्ली भी बुला रहे। क्या इन हजारों ट्रैक्टरों को दिल्ली लाने-ले जाने में डीजल खर्च के रूप में करोड़ों रुपए स्वाहा कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र का किसान भी गरीब है? सवाल यह भी है कि भारत का किसान इतना फुरसत वाला कब हो गया कि अपना काम-धंधा छोड़कर दो महीने तक दिल्ली में डेरा डाले रहे?

प्राइवेट कंपनियां किसान से सीधे फसल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगी। नए कृषि कानूनों में कही गई इस बात के चलते किसानों को यह डर है कि अगर भविष्य में सरकार ने एमएसपी पर फसल की खरीद का बहुत कम लक्ष्य निर्धारित किया तो उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में अपनी फसल बाहर बेचनी पड़ेगी। और तब अगर प्राइवेट कंपनियां उनकी फसल ओने-पौने दामों पर खरीदने लगीं तो वे क्या करेंगे?

पंजाब और हरियाणा के किसान इस वजह को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि अभी सरकार एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज इन्हीं दो राज्यों से खरीदती है। नीति आयोग की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 100 फीसदी किसान फसल को एमएसपी पर बेचते हैं। यही वजह है कि इन दो राज्यों के किसान कड़ाके की ठंड में भी नए कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एमएसपी पर किसान चाहते क्या हैं? किसानों का कहना है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि अगर उनकी फसल को कोई व्यापारी या कोई प्राइवेट कंपनी खरीदे तो वह उसे एमएसपी पर या उससे ज्यादा कीमत पर ही खरीदे। यानी एक ऐसा कानून जिसके चलते कोई भी फसल को एमएसपी से नीचे खरीद ही न पाए। लेकिन मोदी सरकार किसानों की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी है।

इस आंदोलन का यह हश्र तय था

26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, अगर कुछ अस्वाभाविक था, तो वह भोलापन है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने यह मान लिया था कि किसानों के रूप में एकत्रित भीड़ अपने नेताओं का अनुशासन मानेगी और उनके वायदे के अनुसार निर्धारित रूट पर ही जुलूस निकालेगी। भीड़ वाले आंदोलनों का अब तक का यही इतिहास रहा है कि भीड़ कभी भी अनुशासित तरीके से अपने नेतृत्व की बातें नहीं मानती। इसीलिए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हुआ, वह काफी हद तक प्रत्याशित था। दरअसल, यह आंदोलन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। किसानों के 40 से अधिक संगठन इस आंदोलन में शरीक हैं। इन सबका अलग-अलग एजेंडा रहा है और किसी एक फैसले पर उनका पहुंचना लगभग असंभव था। 26 जनवरी को टीवी चैनलों पर दिनभर की गतिविधियां देखकर एक बात तो बिना किसी हिचक कही जा सकती है कि अराजकता की घटनाएं किसान नेतृत्व के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के नेतृत्व की अक्षमता का भी बखान कर रही थीं।

इस तरह का दयनीय प्रदर्शन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिखाया था। जहां से हिंसा की शुरुआत हुई और बाद में जहां-जहां अराजकता दिखी, कहीं भी एक पेशेवर पुलिस नेतृत्व के दर्शन नहीं हुए। शायद बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप ने इस बल को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वह कोई पेशेवर फैसला कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने रैली निकालने या न निकालने की बात पुलिस के विवेक पर छोड़ दी थी, ऐसी स्थिति में उसके सामने सांप-छछुंदर जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। यदि वह रैली की इजाजत न देती, तो उसे अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का दोषी ठहराया जाता और इजाजत देते समय उसने जिनकी गारंटी ली, वे किसान नेता किसी भी नैतिक बल से रहित थे।

दोनों पक्ष अड़े

किसानों की मांगें सही हैं या सरकार का रुख ठीक है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच यही है कि दोनों पक्ष अड़ गए हैं और दोनों अपने-अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। न सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार दिख रही है, और न किसान इन कानूनों को रद्द किए बिना वापसी के लिए तैयार हैं। यह ऐसा गतिरोध है, जिसे खत्म करने के लिए बीच का सम्मानजनक रास्ता निकाला जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हो सका, और जो कुछ हुआ, उसने इस आंदोलन को बदनाम और कमजोर कर दिया। दिल्ली की तमाम सीमाओं को पार करते किसानों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे यही बता रही हैं कि शुरू में पुलिस को जिस तरह की सख्ती बरतनी चाहिए थी और उनको नियंत्रित करना चाहिए था, वैसा वह नहीं कर पाई। इसी वजह से बैरिकेड्स तोड़कर ट्रैक्टर शहर के अंदर आ गए। निहंग घोड़ों पर हथियार लेकर खतरनाक ढंग से घूम रहे थे। उनको रोकने का प्रभावी तरीका पुलिस के पास नहीं था। पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो उसका बहुत असर पड़ता नहीं दिखा। संभवत: पुलिस की यह सदिच्छा रही होगी कि कम से कम बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया जाए और नियम भंग करने वाले किसान वापस तय रास्तों पर लौट जाएं।

आंदोलनकारियों ने पुलिस की सारी शर्तों को तोड़ा

लोकतंत्र में विपरीत राय रखने का सबको अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, परंतु 26 जनवरी को दिल्ली में लक्ष्मण रेखा पार हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस की सारी शर्तों को तोड़ा। पुलिस पर हमला किया। लालकिले पर राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन किया। ये सब क्षम्य नहीं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वे चाहे किसी भी पार्टी या संगठन के हों। इनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जानी चाहिए। कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए एक महाशय ने कहा, 'किसी के बाप की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका, उसका इलाज कर देंगे।' कृषि कानूनों से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसका स्थायी समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। अगर कमेटी के सदस्यों से कुछ लोगों को आपत्ति हो और यदि उस आपत्ति में बल हो तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। कानूनों की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। कई विकल्प हैं। सरकार को उन्हीं में से ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा, जो प्रदर्शनकारी किसानों के एक बड़े वर्ग को भी स्वीकार्य हो।

सरकारी तंत्र में सुधार

पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय राज्य की भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श एक गलत परिपाटी पर चला गया है। नेहरूवादी राज्य और समाजवादी नीतियों की विफलता ने सरकार और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। लाइसेंस-कोटा परमिट राज, अक्षम नौकरशाही और बेलगाम भ्रष्टाचार ने सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते सरकार को समस्या के समाधान नहीं, बल्कि समस्या के जनक के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि 1990 के दशक के बाद से सरकार के आकार को कम करने का तर्क व्यापक समर्थन पाने लगा। खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा नौकरियां हैं, जिन्हें कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार-अनुपात दुनिया में सबसे कम है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर रेलवे और डाक विभाग को निकाल दिया जाए तो प्रत्येक 1,00,000 लोगों के लिए केवल 139 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके **विपरीत** संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारवादी और कथित तौर पर न्यूनतम सरकार वाले देश में प्रति 1,00,000 निवासियों पर 668 सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है।

वर्ष 2014 में अकेले केंद्र सरकार के स्तर पर 7,50,000 रिक्तियां थीं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 38 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। राज्यों की नौकरशाही में वर्षों से मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण पूरा सरकारी तंत्र ही विलुप्त होता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकारी नौकरियों में कटौती करने के बजाय भारत को राज्य की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का अभिप्राय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है। आवश्यकता तो उसका पुनर्गठन करने की है। समस्या यह है कि सरकार को जिस क्षेत्र में होना चाहिए, वहां नहीं है और बेवजह के ऐसे सरकारी विभागों का बोलबाला है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि समाजवादी समय की बनाई हुई व्यवस्था आज तक चली आ रही है। जिस तरह पुलिस के तमाम पद रिक्त हैं, उसी तरह स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। यदि सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो अकेले स्कूलों में करीब दस लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ग्रामीण और कृषि मंत्रालय में लगभग 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें अधिकांश का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का है। यहां तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बात न करना ही बेहतर है।

अगर देश में पुलिस, स्कूल, अस्पतालों में लाखों रिक्तियां हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है। आखिर ऐसे में सरकार का आकार कम करने की बात ही कहां आती है? जब सरकार सिर्फ नाममात्र के लिए हो तो उसका आकार कम करना न्यायसंगत कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर अधिक न्यायाधीश होंगे तो हमारी न्यायिक प्रणाली तेजी से न्याय देना सुनिश्चित करेगी। इसी तरह अधिक पुलिसकर्मियों का मतलब बेहतर कानून एवं व्यवस्था से होगा। इसी क्रम में और अधिक डॉक्टरों का मतलब होगा आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल। स्कूलों और कॉलेजों में सही पढ़ाई होने से देश का मानव संसाधन कहीं अधिक सक्षम और बेहतर होगा। ये सभी पद आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केवल कल्पना की दुनिया में ही ये पद आर्थिक विकास पर बोझ माने जा सकते हैं।

सरकारी तंत्र में सुधार का यह मतलब नहीं और न हो सकता है कि सरकारी तंत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को उचित मानदंड देने में असमर्थता या अनिच्छा का मतलब यह नहीं है कि सरकार लोगों को काम पर रखना ही बंद कर दे।

● **राजेश बोरकर**

प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता

स्पष्ट है कि आवश्यकता प्रशासनिक सुधारों की है। इसी तरह जरूरत नियम-कानूनों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की भी है, न कि सरकारी नौकरियों को ही समाप्त कर देने की। यह समस्या कोई हाल में उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। पिछले दो दशकों से अधिक समय से एक के बाद एक सरकारें अपनी नीतिगत अक्षमता या अनिच्छा के कारण रिक्त पदों को भरने में अक्षम रही हैं। इस समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से ही हो सकता है। यह समन्वय कायम होना चाहिए और उन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहिए जिनसे सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो। महामारी कोविड-19 के दौरान हमने नौकरशाही राज को देखा कि उसने किस तरह चार महीने के अंदर लॉकडाउन संबंधी सैकड़ों नियम जारी कर एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में सरकार का आकार ज्यादा बड़ा इसलिए लगता है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अनाप-शनाप शक्तियां हैं। इन शक्तियों के चलते वे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों को परेशान करने में सक्षम हैं।

उबरने का आखिरी मौका!

नए साल में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ये चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस की वापसी के लिए आखिरी मौका हैं। अगर यह मौका कांग्रेस चूक गई तो फिर भगवान ही उसका मालिक है।

देश का सबसे पुराना सियासी दल कांग्रेस यदि पलटकर वर्ष 2020 के घटनाक्रम और पार्टी की गति को देखे तो कुछ खास हासिल नहीं है। विद्रोह की सुगबुगाहट ने गांधी परिवार का सुकून जरूर कम किया होगा। पूरे साल की समीक्षा संकेत मिलेंगे कि नए साल 2021 में उसे नई जागृति के साथ आगे बढ़ना होगा। इसकी शुरुआत कुछ मरम्मत से भी हो सकती है, अन्यथा पार्टी का अस्तित्व भी बच सकेगा, कहा नहीं जा सकता।

2020 में कांग्रेस में उथल-पुथल रही। पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अहमद पटेल और दीर्घकालिक कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा का निधन होने से रिक्तता आई है। इससे पहले संगठनात्मक चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ 23 नेताओं (जी-23) ने विद्रोह तेवर दिखा दिए थे। जिस दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, वहां साल के शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक न खोल सकी। वोट शेयर भी 5 प्रतिशत से नीचे रहा। इस झटके से पार्टी उबर भी न सकी और मार्च में मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ देने से कमलनाथ सरकार चली गई। संकट के बादल राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी छाए, जिससे बड़ी मशक्कत से वह निकल सके। हालांकि युवा नेताओं की कमी से जूझ रही पार्टी को सचिन पायलट से भरोसे का संकट हो गया, वहीं पायलट इस घटनाक्रम के बाद से सक्रिय भी नहीं हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को लेकर काफी सतर्क हो चले हैं।

बिहार में महागठबंधन इस बार सत्ता से दूर रह गई। इसमें भी कांग्रेस को ही दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसे 70 सीटों पर मौका दिया गया, लेकिन वह जीत सकी महज 19, ऐसे में डीएमके जैसे सहयोगी अब तमिलनाडु में कांग्रेस की सीटों की मांग का औचित्य पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उप्र की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन हाल ही में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव में पार्टी चार सीटों पर हार गई। राजस्थान में पंचायत चुनावों में कांग्रेस को भाजपा की तुलना में बहुत कम सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने का अभियान चलाया था। राज्यसभा में भी कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। राज्यों में कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, जिनमें से अधिकतर भाजपा में चले जाते हैं। चुनावी प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं दिखती। 2019 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन पर कभी औपचारिक रूप से बैठक नहीं हुई। हार के कारणों का पता लगाने की न कोशिश हुई, न कारणों को दूर करने के प्रयास।

दरअसल, राहुल गांधी के करीबी यानी उनकी टीम और जी-23 के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। राहुल नई टीम के साथ काम करना चाहते हैं, जबकि पुराने दिग्गज चाहते हैं कि राहुल पहले खुद को बेहतर प्रदर्शन से साबित करें, फिर शीर्ष पद पर दावा करें। तब तक के लिए निर्वाचन के जरिए शीर्ष कमान तय हो। ऐसे में भ्रम बरकरार है कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए। मुश्किल ये भी है कि संकेत मिलते हैं कि कभी राहुल तैयार हैं, तो कभी तैयार नहीं हैं। इन स्थितियों में धारणा मजबूत हो चली है कि सोनिया गांधी पुत्र मोह का शिकार हो गईं हैं, जो हर हाल में राहुल को आगे लाना ही चाहती हैं, जबकि पार्टी में ही एक वर्ग उनकी बेटी प्रियंका को जिम्मेदारी देने का पक्षधर है। जी-23 एक गैर-गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि देश में सियासी वंशवाद, भाई-भतीजावाद के प्रति उपेक्षा बढ़ती जा रही है। गांधी परिवार को आगे बढ़ाते रहने से पार्टी का लंबे समय तक नुकसान होता रहेगा।

पार्टी में मची इन सारी उथल-पुथल के बीच विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस स्वाभाविक रूप से दूसरे नंबर की पार्टी बनने से समझती है कि जब लोग भाजपा से ऊब जाएंगे, तो यह एकमात्र या कहें अंतिम विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही चुनेंगे। यानी कांग्रेस परिवर्तन की अलख जगाने के बजाय जनता द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन का इंतजार कर रही है।

ऐसे अनुमानों से इतर कांग्रेस को समझना होगा कि समस्या कांग्रेस से नहीं, बल्कि पार्टी में संगठन स्तर अधिक है। यहां शीर्ष नेतृत्व को लेकर ही मुश्किल है, तो सुधार की शुरुआत कहां से होगी? ऐसे में पार्टी को विस्तृत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी भी पार्टी गांधी परिवार या गैर गांधी के बीच झूल रही है और पार्टी की असल जरूरतों पर कोई बोलना नहीं चाहता। शायद दूसरे से विद्रोह की उम्मीद रखते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य समितियों को भंग करना होगा, संगठनात्मक पदों के लिए चुनाव होने चाहिए, कांग्रेस कार्य समिति भंग कर मार्गदर्शी मंडल

अध्यक्ष का चुनाव बड़ी चुनौती

पिछले डेढ़ साल से राजनीतिक चुनौती से जूझ रही कांग्रेस ने साल 2020 के आखिर में इस मामले को निपटाने की एक और कोशिश की। करीब दिसंबर 2020 में हुई एक अहम बैठक में फैसला किया गया कि साल 2021 के शुरू में ही पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। यह भी दावा किया गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने को राजी हो गए हैं। पार्टी में दावा किया जाने लगा था कि राहुल जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले विदेश यात्रा पर निकल गए। ये राहुल की तरफ से साफ संकेत था कि फिलहाल पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले ही दिन कांग्रेस के खेमे से खबर आ गई कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर लौटने से हिचक रहे हैं।

कैसे जीतेंगे सहयोगियों का विश्वास?

इस बीच, शिवसेना ने तो खुलेआम सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग करके सोनिया के गठबंधन की अगुवाई करने की क्षमता पर ही सवाल उठा दिया है। शिवसेना ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो भी वे यूपीए अध्यक्ष के तौर पर उसे मंजूर नहीं होंगे। भारतीय राजनीति में लगातार अपना जनाधार और साख खोती जा रही कांग्रेस इन पहाड़ जैसी चुनौतियों से कैसे पार पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बनाए जाए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1990 के दशक की शुरुआत की तरह ही गांधी परिवार को कुछ वर्षों के लिए अलग कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए युवा तुर्कों का चुनाव करने और उनमें से प्रत्येक को देश के एक क्षेत्र का प्रभारी बनाने की आवश्यकता है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे दिन ट्वीट करने के बजाय सड़क पर उतरने और सार्वजनिक मुद्दों को उठाने की जरूरत है। इसे न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी एक 'शेडो कैबिनेट' बनाने की जरूरत है। इसमें जबरदस्त प्रशासनिक अनुभव वाले नेता हैं। इन भूमिकाओं में बहुत सारे वरिष्ठ दिग्गजों को समायोजित किया जा सकता है। यह युवा (45 वर्ष से कम) पुरुषों और महिलाओं के लिए सभी संगठनात्मक पदों का 50 प्रतिशत आरक्षित क्यों नहीं कर सकता है? कुछ आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच की आवश्यकता है।

जाति या वर्ग की राजनीति में विश्वास नहीं करने वालों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति की जरूरत है। वर्तमान में पार्टी के पास कोई भी एंकर वोटिंग सेगमेंट नहीं बचा है। मतदाताओं के बिखराव से कांग्रेस कमजोर होती गई है। इसका नजीता रहा कि हर चुनाव में कांग्रेस सिमटती दिखती है, जिसे समझने के लिए ये आंकड़ा ही पर्याप्त है कि 1989 के लोकसभा चुनाव में 30.9 करोड़ वोट पड़े, जिसमें से 11.9 करोड़ कांग्रेस को मिले, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 लाख वोट बढ़कर 12 करोड़ हो गए, जबकि इस चुनाव में वोट पड़े 61.2 करोड़। यानी मतदान दोगुना हो गया, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा लगभग जस का तस। इन स्थितियों में कांग्रेस को समझना होगा कि नया साल उसके लिए नई जागृति का दौर लेकर आएगा या अंत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई सबसे पुरानी पार्टी इतिहास के पन्नों तक सिमटने को तैयार है।

कांग्रेस के सामने पहले से ही चुनौतियों का पहाड़ है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक कांग्रेस अपने गठन के बाद के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। ये दौर लंबा खिंचता जा रहा है। पहले भी कई बार कांग्रेस ऐसे संकटों से गुजरी है। तब संकट कुछ दिनों या फिर कुछ महीने में ही खत्म हो जाता था। पार्टी में पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं ने बगावत की। कई बार पार्टी टूटी, लड़खड़ाई और फिर आगे बढ़ी। चाहे चौधरी चरण सिंह की इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत हो या फिर वीपी सिंह की राजीव गांधी के खिलाफ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से पार्टी एक ही सवाल पर अटकी हुई है और एक ही जगह खड़ी है। यहां मामला भी अलग है। पहले पार्टी में कई बार गांधी-नेहरू परिवार के वर्चस्व को चुनौती दी गई। इसके चलते कई बार पार्टी टूटी। नई पार्टी बनी। लेकिन यहां पूरी कांग्रेस गांधी-नेहरू परिवार के पीछे खड़ी है। पार्टी को इस परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष मंजूर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस जिद पर अड़े हैं कि उनके परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अभी चुनावी मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही है। एक तरफ तो कांग्रेस भाजपा को कमजोर करके केंद्र की सत्ता से उखाड़ना चाहती है लेकिन पश्चिम बंगाल में वो वामपंथियों के साथ जाकर भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर रही है। कांग्रेस में कुछ नेताओं की राय है कि कांग्रेस को वामपथियों के साथ जाने के बजाय ममता का हाथ थामकर उसे मजबूत करना चाहिए ताकि भाजपा को उप्र और महाराष्ट्र के बाद तीसरे सबसे बड़े राज्य में सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन कांग्रेस में फिलहाल ऐसे अहम मसलों पर चर्चा के लिए कोई आधिकारिक मंच ही नहीं है। असम में पिछली बार भाजपा ने कांग्रेस की 15 साल पुरानी तरुण गोगोई सरकार को धराशायी करके बड़े बहुमत से सत्ता हासिल की थी। इस बार कांग्रेस के सामने असम की सत्ता भाजपा से छीनने की बड़ी चुनौती है।

असम में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस की छवि फिलहाल ऐसी बन गई है कि वो सीधे मुकाबले में भाजपा को हराने की ताकत खो चुकी है। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र में भाजपा से सत्ता छीनकर ये भ्रम तोड़ दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो तीनों राज्यों में ढेर हो गई। असम में अगर जीत मिलती है तो ये कांग्रेस के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हो सकती है। तमिलनाडु में भी इस साल विधानसभा चुनाव हैं। यहां कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में है। तमिलनाडु में भी एक बार डीएमके और एक बार एआईएडीएमके की सरकार बनने की परंपरा रही है। पिछली बार एआईएडीएमके को बहुमत मिला था। इस बार भाजपा एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस के सामने इस बार डीएमके के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने की चुनौती है। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन जिस तरह सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर फिसला है उसने कांग्रेस को सहयोगियों के लिए और अविश्वसनीय बना दिया है। इन हालात में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

● इन्द्र कुमार

वर्ष 2021 में देश की राजनीति की दिशा और दशा पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से तय होगी। इसलिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने बंगाल चुनाव को इज्जत का सवाल बना लिया है। वहीं ममता बनर्जी की कोशिश है कि वे प्रदेश में भगवा न फहराने दें। इसलिए वे लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को चकमा देने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला!

ममता बनर्जी और उनकी टीम पर लगता है अमित शाह की घेरेबंदी का असर होने लगा है, तभी तो पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पूरे विपक्ष से एकजुट होकर ममता बनर्जी के सपोर्ट की अपील की गई है। ममता बनर्जी के साथियों पर लगता है भाजपा नेतृत्व का माइंड गेम हावी होने लगा है। भाजपा नेता अमित शाह के पश्चिम बंगाल चुनाव से काफी पहले ही शुभेंदु अधिकारी सहित दर्जनभर नेताओं के टीएमसी से झटक लेने का तृणमूल कांग्रेस पर साफ-साफ असर दिखने लगा है। ममता बनर्जी कहां अभी पार्टी संभालने में लगी थीं और कहां घर में ही बगावत शुरू होने लगी है। ममता बनर्जी के भाई ने तृणमूल कांग्रेस नेता पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी में बढ़ते दखल को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही तृणमूल नेताओं के निशाने पर हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने की शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के लिए अभिषेक बनर्जी के तौर तरीके ही बड़ा कारण बने हैं।

सीनियर तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा का विरोध करने की अपील की है और ऐसा करने के लिए सबको ममता बनर्जी का साथ देना होगा। सौगत रॉय का सुझाव भी यही है कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर ममता बनर्जी का सपोर्ट करें। तृणमूल कांग्रेस की ये कोशिश 2019 के आम चुनाव जैसी ही लगती है, जब पूरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ममता बनर्जी केंद्र में सत्ताधारी भाजपा को चैलेंज करने की कोशिश कर रही थीं। तब तो ममता बनर्जी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंचने जैसा ही महसूस हो रहा था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपाइरी डेट प्रधानमंत्री कहकर बुलाने लगी थीं।

लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करने के बाद ही ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में एंट्री मिली और अब उसी वाम मोर्चे से मदद की गुहार लगाने को भला कैसे समझा जाना चाहिए? सौगत रॉय लेफ्ट के साथ-साथ कांग्रेस का भी साथ मांग रहे हैं, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे तृणमूल कांग्रेस नेताओं के मन में भी ममता बनर्जी के एक्सपाइरी डेट मुख्यमंत्री जैसा डर घर करने लगा है। लगता है अब ममता बनर्जी की टीम भाजपा की तरफ से दबाव महसूस करने लगी है। अगर भाजपा के माइंड गेस के चलते ऐसा हुआ है, तो इसमें पिछड़ना ममता बनर्जी के लिए घातक हो सकता है। अब जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील हो रही है, आशंका तो ऐसी ही होगी कि नतीजे भी कहीं आम चुनाव जैसे ही न हों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिश केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के हर प्रयास को काउंटर करने की है, जैसे बाउल गायक बासुदेव दास को स्टेज पर बुलाकर अपनी तारीफ करा लेना या अमित शाह के घरों में जाकर लंच करने को काउंटर करने के लिए चलते-चलते लोगों के बीच पहुंचकर खाने पकाने लगना, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की हौसलाअफजाई के लिए प्रदर्शन भर लगता है जो ऊपरी प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं लगता।

सौगत रॉय के बयान में वो झलक दिखाई दे रही है जो अब तक ममता बनर्जी के रुख में कभी नहीं देखने को मिली है। लेफ्ट के साथ अब तक शिद्दत से दुश्मनी निभाती आईं ममता बनर्जी ने हमेशा ही अपनी भावना एक्शन के रूप में प्रदर्शित की है। 2019 के आम चुनाव की तरह विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में भी ममता बनर्जी लेफ्ट की दुश्मनी नहीं भुला पाईं थीं। याद कीजिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में भी ममता बनर्जी ने लेफ्ट के

शिवसेना से चुनाव रोमांचक

बंगाल के राजनीतिक दंगल में मुकाबला कांटे का होता दिखाई दे रहा है। कभी लेफ्ट और टीएमसी के बीच होने वाला ये सियासी युद्ध अब तब्दील हो गया है भाजपा और टीएमसी के बीच महायुद्ध में, कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका आंकलन सियासी पंडित भी कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बंगाल की सियासत कभी यूं भी करवट ले बैठेगी इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट की चर्चा होना स्वाभाविक है क्योंकि ये सारे राजनीतिक दल बंगाल की राजनीति में पहले से ही रहे हैं। वह कमजोर रहे हों या फिर मजबूत पर ये राजनीतिक दल बंगाल की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। ये चुनाव महायुद्ध में इसलिए तब्दील हो गया क्योंकि इस चुनाव में अन्य राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी दस्तक दे डाली है। सबसे पहले इस चुनाव में उतरे हैं असदउद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में लड़ने का ऐलान पहले से ही कर रखा है और अब महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी इस चुनाव में कूदने का ऐलान कर दिया है। जिससे चुनाव रोमांचक हो गया है।

नेताओं को न्यौता नहीं दिया था। जब तमिलनाडु से जम्मू-कश्मीर तक के नेताओं को जुटाया था, लेकिन वाम मोर्चे से दूरी बनाए रखी। ये ममता बनर्जी ही हैं जो चाहती थीं कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर ले, लेकिन वो खुद कभी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का साथ लेने को राजी नहीं हुईं। ममता बनर्जी का ये गुस्सा आम चुनाव के नतीजे आने तक हाई हो चला था। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों की मीटिंग में ममता बनर्जी भी शामिल हों, लेकिन ममता तैयार नहीं हुईं।

अब वही तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ दें, लेकिन ममता बनर्जी के साथियों को ऐसा लगता क्यों है कि पार्टी को ऐसा सपोर्ट मिल भी पाएगा। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी पंचायत और निकायों के चुनाव हुए हैं, हर बार भारी हिंसा हुई है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की शिकायत रही है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता उनके उम्मीदवारों को धमकाते हैं और मारते पीटते भी रहते हैं। हत्याओं तक के इल्जाम लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ हैं तो उनको भगवा दल की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए।' सौगत रॉय का दावा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं।

लेफ्ट और कांग्रेस ही नहीं भाजपा की तरफ से भी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा, हमला और हत्या जैसे संगीन आरोप लगाने के बावजूद क्या कभी कहीं कोई सुनवाई हुई है। ये तो अब मानकर चला जाने लगा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होनी ही है, लेकिन क्या ममता बनर्जी ने कभी किसी की ऐसी कोई अपील सुनी है? ममता बनर्जी तो हिंसा के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार बताने लगती हैं, जिस राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर हो, वही कहे कि ये सब बाहरी तत्व हैं तो कितना अजीब लगेगा। सौगत रॉय से पहले सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या ने भी सभी वाम दलों को सलाह दी थी कि वे मिलकर भाजपा का विरोध करें और इसके लिए ममता बनर्जी का साथ दें, लेकिन वो सलाह सिरे से खारिज कर दी गई।

दरअसल, पश्चिम बंगाल का विपक्ष भाजपा के पश्चिम बंगाल में दिनों दिन मजबूत होते जाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले काफी दिनों तक ऐसा लग रहा था जैसे ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करना चाहती हैं। असल में, 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर ही चार दशक पुरानी वाम मोर्चे की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के करीब सालभर बाद ही ममता ने मौका देखकर केंद्र की यूपीए सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया, प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी वैसा ही किया। केंद्र में तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कई विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी।

बाद में ममता बनर्जी की कोशिश रही कि भले ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में चुनावी गठबंधन न हो लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में लेफ्ट के साथ तो न ही जाए, लेकिन बिलकुल वैसा ही हुआ और इस बार भी वही हो रहा है। कांग्रेस ने आम चुनाव के बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को नेता बनाने के बावजूद पश्चिम बंगाल कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बना कर कोलकाता भेज दिया है। अधीर रंजन चौधरी के हाथ में कमान रहते हुए तो ममता बनर्जी को पार्टी का सपोर्ट मिलने से रहा और लेफ्ट नेता जब दीपांकर भट्टाचार्या की नहीं सुने तो सौगत रॉय की अपील क्या मायने रखती है। लिहाजा सौगत रॉय की अपील का फायदा तो होने से रहा, नुकसान होने ज्यादा आशंका लग रही है, क्योंकि सौगत रॉय की इस बात का मैसेज काफी गलत जाएगा। जो कोई भी ममता बनर्जी की भाजपा के मुकाबले हैसियत तौल रहा होगा उसके लिए तो ये भरोसा करना मुश्किल हो सकता है कि ममता बनर्जी कमजोर नहीं पड़ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा। ममता बनर्जी को शुरू से ही हर कोई दीदी कहकर संबोधित करता आ रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक कटाक्ष करते वक्त भी दीदी कहकर ही संबोधित करते रहे हैं, लेकिन तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी में बढ़ती नाराजगी के बीच ममता बनर्जी के संबोधन के लिए एक और नाम दिया जा चुका है पीशी। पीशी का मतलब आंटी होता है। विपक्ष इस नाम को और ज्यादा हवा दे रहा है ताकि अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा सके।

● दिल्ली से रेणु आगाल

परिवारवाद के घेरे में ममता बनर्जी

अभी-अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो अभिषेक बनर्जी को राजकुमार कह कर संबोधित किया। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को युवराज कहकर तंज कसते रहे हैं या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज कहकर संबोधित किया था। हाल ही में ममता बनर्जी के एक भाई कार्तिक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वंशवाद की राजनीति पर चिंता जताकर ममता बनर्जी को ही टारगेट किया था। अभी कार्तिक बनर्जी ने भाजपा ज्वाइन करने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन उनका बयान तो जेपी नड्डा की लाइन ही पकड़ रहा है। कार्तिक बनर्जी का कहना है कि ऐसे राजनेताओं से तंग आ चुके हैं, जो आम लोगों की जिंदगी बेहतर करने का वादा करते हैं लेकिन अंत में सिर्फ अपने परिवार वालों की जिंदगी ही बेहतर बना पाते हैं। ममता बनर्जी पर वंशवाद के आरोप को लेकर भी सौगत रॉय ने बचाव किया है। सौगत रॉय कहते हैं, डायमंड हार्बर के सांसद और टीएमसी की युवा शाखा के प्रमुख अभिषेक बनर्जी को घोष की तुलना में ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। वो 2015 से ही राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने कभी तृणमूल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का दावा पेश नहीं किया।

धान की रिकार्ड खरीदी

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस समय किसान खुशहाल हैं। इसकी वजह है कि प्रदेश में खेती-किसानी लाभदायक होने लगी है। सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर किसान खेती कर रहे हैं। इस कारण प्रदेश में अनाज का बंपर उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब तक सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन में 21 जनवरी तक 84 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो बीते वर्ष राज्य में क्रय किए गए कुल धान 83.94 लाख मीट्रिक टन से 50 हजार मीट्रिक टन अधिक है, जबकि धान खरीदी के लिए 10 दिन अभी बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में बीते 2 वर्षों में धान खरीदी की मात्रा और खेती-किसानी और किसानों की संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ के लिए एक शुभ संकेत है।

राज्य सरकार की किसान हितैषी नीति के चलते छत्तीसगढ़ राज्य को खेती-किसानी के मामले में देश का मॉडल राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। अब तक राज्य के 19 लाख 54 हजार 332 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को 27 लाख 70 हजार 693 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके चलते अब तक 25 लाख 45 हजार 512 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में जहां 56.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में 80.83 लाख मीट्रिक तथा वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया। पंजीकृत किसानों की संख्या में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 15.77 लाख थी, वह वर्ष 2018-19 में बढ़कर 16.96 लाख और वर्ष 2019-20 में बढ़कर 19.55 लाख हो गई थी। इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो 21.52 लाख है।

खरीफ वर्ष 2020-21 में 21 जनवरी 2021 तक राज्य के बस्तर जिले में 1 लाख 20 हजार 471 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 55 हजार 401 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 13 हजार 401 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 2 लाख 65 हजार 350 मीट्रिक टन, कोंडागांव जिले में 1 लाख 25 हजार 945 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 17 हजार 252 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 33 हजार 711 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 4 लाख 30 हजार 664 मीट्रिक टन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 64 हजार 991 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 7 लाख 71 हजार 608 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 1 लाख 15 हजार 821 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में 3 लाख 44 हजार 629 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 4 लाख 98 हजार 428 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 4 लाख 96 हजार 276 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 5 लाख 70 हजार 736 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 3 लाख 81 हजार 633 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 3 लाख 86 हजार 87 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 7 लाख 3 हजार 423 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 6 लाख 4 हजार 191 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 4 लाख 7 हजार 864 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में 2 लाख 94 हजार 996 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 6 लाख 38 हजार 190 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 4 लाख 68 हजार 276 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 1 लाख 34 हजार 643 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 1 लाख 273 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 1 लाख 3 हजार 960 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 1 लाख 35 हजार 683 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 1 लाख 59 हजार 690 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीद रहा केंद्र

प्रदेश सरकार और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय खाद्य निगम की छत्तीसगढ़ इकाई चावल के स्टॉक नहीं उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि खरीफ मौसम के लिए केंद्रीय पूल के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद के बारे में पूर्व जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। वल्लभ के बयान के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि नीति के तहत उसने इस साल छत्तीसगढ़ के लिए पिछले वर्ष के 24 लाख टन के स्तर पर खरीद की मात्रा सीमित कर दी है क्योंकि राज्य सरकार धान उत्पादकों का वित्तीय प्रोत्साहन देती हुई पाई गई। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र ने 2020-21 खरीफ विपणन सीजन के दौरान केंद्रीय पूल के तहत एफसीआई को 24 लाख टन चावल पहुंचाए जाने की अनुमति देने का फैसला किया जो पिछले सालों के दौरान इजाजत दी गई मात्रा के बराबर है। उसने कहा कि यह विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत खरीद प्रणाली पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नोडल एजेंसी एफसीआई के बीच हुए सहमति ज्ञापन के अनुरूप है।

भाजपा में बड़ा चेहरा कौन?

राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राज्य भाजपा में बड़ा चेहरा कौन है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट के घमासान पर चुटकियां लेने वाली भाजपा के लिए अपने घर में चल रहे इस घमासान से पार पाना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि राज्य की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के समर्थकों ने अपनी नेता के पक्ष में जोरदार लॉबिंग की हुई है।

वसुंधरा बीते कुछ महीनों से राजस्थान भाजपा में उनके विरोधियों को अहम पद दिए जाने से नाराज हैं। इनमें जयपुर के राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी और विधायक मदन दिलावर को प्रदेश महामंत्री बनाया जाना उन्हें खासा अखरा है। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने इन दिनों 'वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान' का गठन किया है, जिस पर राज्य भाजपा के दूसरे नेताओं ने ऐतराज जताया है। राजे के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी इस बात का प्रचार किया हुआ है कि वह राज्य भाजपा में सबसे बड़ी नेता हैं। राजे के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में भी सोशल मीडिया पर उनके समर्थक प्रचार कर रहे हैं और उन्हें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है।

वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान के जवाब में सतीश पूनिया समर्थक मोर्चा भी राज्य में बन चुका है। हालांकि पूनिया ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा था कि यह किसी की शरारत है और वह ऐसे किसी मोर्चे का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा था कि ऐसा मोर्चा बनाने वालों के बारे में जांच की जा रही है। लेकिन वसुंधरा ने उन्हें लेकर बने मंच के बारे में इस तरह की कोई सफाई नहीं दी। पूनिया ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और वसुंधरा के समर्थन में सोशल मीडिया पर चल रहे इन ग्रुप्स के बारे में उन्हें बताया था। जब सतीश पूनिया को राजस्थान भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया था तो वसुंधरा राजे उनके स्वागत कार्यक्रमों से दूर रही थीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की पसंद माने जाने वाले पूनिया को राजे का धुर विरोधी माना जाता है। भाजपा के भीतर चल रही इस लड़ाई में कांग्रेस को भी आनंद आने लगा है। राजस्थान की सरकार में मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में वसुंधरा के बिना भाजपा शून्य है। अगर भाजपा वसुंधरा को नजरअंदाज करती है तो उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। मीणा के इस बयान पर सतीश पूनिया ने कहा, 'कांग्रेस पहले कहती थी कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है लेकिन अब वह कह रही है कि कई चेहरे हैं। यह हमारे लिए अच्छी बात है।' पूनिया कहते हैं कि पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बारे में फैसला लेगा कि राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा।

बीते कुछ समय में राजस्थान भाजपा के पोस्टर्स से वसुंधरा राजे का चेहरा गायब होने को लेकर भी घमासान हो चुका है। पिछले महीने भाजपा ने अपने बागी नेता घनश्याम तिवाड़ी को फिर से पार्टी में शामिल किया है। तिवाड़ी का राजे से छत्तीस का आंकड़ा था। राजस्थान में छह बार के भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी कहते हैं कि राज्य में वसुंधरा से ज्यादा समर्थक किसी के नहीं हैं।

राजस्थान में भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है। यहां गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पूनिया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ के भी अपने-अपने समर्थक हैं। लेकिन इन सब पर भी वसुंधरा राजे भारी पड़ती दिखाई देती हैं। भाजपा आलाकमान वसुंधरा को राज्य की राजनीति से हटाने की पूरी कोशिश कर चुका है। वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया लेकिन वह राज्य की राजनीति से बाहर नहीं निकलीं। भाजपा हाईकमान वसुंधरा की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि राजस्थान में अधिकांश विधायक और सांसद वसुंधरा के खेमे के हैं। राजस्थान में भाजपा के 72 में से 47 विधायक वसुंधरा खेमे के बताए जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मोदी-शाह की जोड़ी ने नेता विपक्ष के पद पर वसुंधरा की दावेदारी को नकारते हुए गुलाब चंद कटारिया को इस पद पर बिठाया था और राजे के विरोधी माने जाने वाले राजेंद्र राठौड़ को उप नेता बनाया था। लेकिन इस सबके बाद भी राज्य में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता में कमी नहीं दिखाई देती। ताजा राजनीतिक हालात में 25 जिलों में वसुंधरा राजे समर्थक मंच की टीम का गठन किया जा चुका है। इस मंच के नेताओं का दावा है कि उनके साथ भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद-विधायकों तक का भी समर्थन है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

खुद के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता

राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधने के साथ प्रदेश भाजपा की अंतर्कलह पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की सरकार बनती है। राजस्थान में पूनिया और कटारिया नहीं बल्कि भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के कहने से या खुद के सोचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे यहां पार्टी आलाकमान निर्णय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गौरतलब है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। मोदी समर्थक नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रूख को देखते हुए कई नेता दौड़ में हैं। इस दौरान कटारिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़ा कोई काम नहीं हुआ। जिन वादों पर सरकार चुनकर आई उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की बस एक यही उपलब्धि है कि उन्होंने भ्रष्टाचार उद्योग पैदा कर दिया। इसमें जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी सब लिप्त हैं।

ग्रामीण इलाकों पर नजर

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी खुलकर आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चले हजारों किसान मुंबई पहुंचे। गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की बड़ी रैली बुलाई गई थी, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित किया। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए राज्य के तीनों सत्ताधारी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आ रहे हैं।

ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धवले कहते हैं कि महाराष्ट्र का यह सम्मेलन कृषि कानूनों को खत्म कराने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए था। आजाद मैदान में किसान सभा हुई, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भाग लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सहित वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई में जुटे किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गत दिनों राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपा।

दरअसल, महाराष्ट्र की सियासत में किसान काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति किसानों और ग्रामीण इलाके की इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। एनसीपी की सियासत ग्रामीण इलाके पर टिकी है, जिसके चलते वो किसानों के समर्थन में खुलकर है। वहीं, शिवसेना की छवि एक मजबूत शहरी पार्टी की रही है, लेकिन राज्य के सत्ता में आने के बाद से ग्रामीण इलाकों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में पार्टी ने राज्य और देशभर में हुए तकरीबन हर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसी के चलते महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर आ गई हैं।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार किसान राजनीति से निकले हैं, जिसके चलते उनका सियासी आधार भी ग्रामीण इलाकों में ही है। 2009 तक, ग्रामीण महाराष्ट्र का अधिकतर हिस्सा, कांग्रेस और एनसीपी के प्रभाव में था। साल 1999 से 2014 के बीच अपने 15 सालों के कार्यकाल के आखिर तक आते-आते कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखा और कांग्रेस और एनसीपी सत्ता से बाहर हो गई थी।

साल 2014 में भाजपा ने राज्य की सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में हिंदू वोट बैंक के साथ-साथ अपनी राजनीति मजबूत की। इसके लिए भाजपा महाराष्ट्र में आक्रामक ढंग से अपना विस्तार करने लगी, जिसकी नजर कांग्रेस और एनसीपी के कमजोर पड़ने से खाली हुए स्थान पर थी। इसकी वजह से शिवसेना ने भी शहरी छवि को पीछे करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस शुरू कर दिया था। हालांकि, शिवसेना भी पिछले 15 सालों में ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने के प्रयास में है। मुंबई, ठाणे और कोंकण के अपने गढ़ से बाहर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र इलाके में 2019 में जीत दर्ज की थी।

शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों से जिन नेता को अपने पाले में लिया, वो वही थे जो ग्रामीण महाराष्ट्र के इलाके में अपना आधार रखते थे। इनमें बीद से जयदत्त क्षीरसागर, अहमदनगर जिले के अकोले से वैभव पिचाड़, ठाणे जिले के शाहपुर से पांडुरंग बरोड़ा और औरंगाबाद जिले के सिलोड़ से अब्दुल सत्तार शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे ने पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र इलाके का दौरा किया, जिसमें उन्होंने मंदिरों में जाने से लेकर किसानों और युवाओं पर फोकस किया था। इस दौरे का उद्देश्य उन्हें एक ऐसे जन नेता के तौर पर लोकप्रिय बनाना था, जो ग्रामीण इलाकों की अगुवाई करने में भी सक्षम था।

मौजूदा समय में शिवसेना के 56 विधायकों में से 20 मुंबई क्षेत्र से हैं। 8 कोंकण से, 12 मराठवाड़ा से, 6-6 उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र से और चार विदर्भ से हैं। वहीं, अभी शिवसेना ने जिस तरह से महाराष्ट्र में हुए पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है, उससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी का आधार ग्रामीण इलाके में बढ़ा है। यही वजह है कि आदित्य ठाकरे ने गत दिनों आजाद मैदान में किसानों की रैली को संबोधित किया, इसके जरिए वो अपनी और अपनी पार्टी दोनों की छवि को मजबूत करना चाहते थे।

● **बिन्दु माथुर**

शिवसेना कई क्षेत्रों में कमजोर

पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे अन्य क्षेत्रों में शिवसेना उतनी तेजी से चुनावी फायदे नहीं उठा पाई, जिसके चलते इस इलाके में अभी भी एनसीपी और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन काफी मजबूत मानी जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को जो सीटें मिली हैं, उनमें इन्हीं इलाकों की ज्यादातर सीटें रही हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव के नतीजों में ही यही दिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी को जो सीटें मिली हैं, उनमें विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र इलाके की सीटें हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोरोना संकट का खतरा कम होते ही महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके का लगातार दौरा कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी वो लगातार मुखर हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खुलकर शुरू से खड़ी है। ऐसे में मुंबई के आजाद मैदान में किसानों से मंच पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी नेताओं ने साथ आकर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाकर किसानों और ग्रामीण इलाके के राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद की।

'मोदी मैन' ने बढ़ाई दिग्गजों की बेचैनी

उप्र की राजनीति में हुई एक शख्स की एंट्री के बाद से यहां की सियासत में बेचैनी अचानक से बढ़ गई है। यही नहीं उप्र के भाजपा नेताओं में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई है। इसका कारण है उप्र की राजनीति में 'मोदी मैन या मोदी वाले शर्मा जी' की धमाकेदार एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएमओ से पीएमओ तक के सफर में 18 साल से साथ चल रहे वरिष्ठ आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा की उप्र भाजपा में एंट्री हो गई है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन यानी 14 जनवरी को लखनऊ के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन कर अरविंद कुमार शर्मा को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। यहीं नहीं मोदी मैन कहे जाने वाले एके शर्मा ने उप्र विधान परिषद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है।

इसी बीच मोदी मैन शर्मा जी की जिम्मेदारी और कद को लेकर भाजपाइयों में कयासों का दौर जो शुरू हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखपुर से लौटने के बाद 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मौजूद वहां पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री से पूछा कि मोदी मैन शर्मा जी को उप्र में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उस पर योगी भी खुलकर नहीं बोल पाए, हां इशारों में जरूर उन्होंने संकेत दिए उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी ही मिलेगी। इसके बाद लखनऊ के सियासी गलियारों में कई प्रकार की चर्चाओं को बल मिलना शुरू हो जाता है, कोई कह रहा है कि दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री के पद से हटाकर एके शर्मा को जिम्मेदारी दी जाएगी, वहीं कुछ कयास लगाते हैं कि गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय भी दिया जा सकता है। यही नहीं यह भी अटकलें हैं कि अगले वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शर्मा जी को महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

आपको बता दें कि उप्र विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को मतदान होना है। भाजपा के 10 प्रत्याशियों ने गत दिनों अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और एके भी शामिल हैं। 'एके शर्मा सुबह नामांकन से पहले काफी उत्साहित भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए।' नामांकन से पहले सभी उम्मीदवार भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी निकलकर भाजपा विधान मंडल दल कार्यालय पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

गौरतलब है कि भाजपा के बाकी प्रत्याशियों जिन्होंने नामांकन दाखिल किए उनमें लक्ष्मण आचार्य, अश्वनी त्यागी, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह, सलिल विश्नोई, डॉ. धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। सियासत में आए हुए अरविंद कुमार शर्मा को 5 दिन भी नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के करीब होने के नाते उप्र के भाजपाई उनसे मिलने और संपर्क तलाशने में जुटे हैं। पार्टी कार्यालय से लेकर कई चौराहों पर एके शर्मा के भाजपा में स्वागत के होर्डिंग्स टंग गए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेताओं ने भी ट्वीट कर पार्टी में स्वागत किया। कुछ भाजपा नेताओं का मानना है कि एके शर्मा के आने से राज्य में चल रही योजनाओं की रफ्तार बढ़ सकती है, क्योंकि सीधे पीएमओ का व्यक्ति यहां पर होगा।

ऐसे ही कई सवाल अरविंद कुमार शर्मा के अचानक वीआरएस लेकर सीधे राजनीतिक पार्टी से जुड़ने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिज्ञों का मानना है कि उप्र मिशन 2022 में जुटी भाजपा को सही समय पर एक नया साथी मिला है। भाजपा में शामिल होने के बाद एके शर्मा ने कहा था कि उन्हें काफी खुशी है, देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा काम कर रही है वो शानदार है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के दरबार से सीधे उप्र आना कोई आसान नहीं है, यही कारण है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि एके शर्मा को उप्र कैबिनेट का कोई अहम पद या फिर सीधे उपमुख्यमंत्री पद मिल सकता है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सबसे अधिक तनाव में हैं, क्योंकि सबसे अधिक चर्चाएं उन्हीं के स्थान पर एके शर्मा को रिप्लेस किए जाने की है? आपको बता दें, इस्तीफे से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। वरिष्ठ आईएएस एके शर्मा ने पहले रिटायरमेंट लिया, फिर 96 घंटे के भीतर ही भाजपा में शामिल हो गए।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

शर्मा 18 साल मोदी की टीम का हिस्सा रहे

यहां आपको बता दें कि एके शर्मा को मोदी मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिछले करीब 18 साल से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में अब जब उन्हें भाजपा में लाया गया है, तो इसके सियासी मायने भी हैं। उप्र के मऊ जिले में पैदा हुए एके शर्मा की कर्मभूमि गुजरात ही रही है। तब से अब तक का प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा ही है कि उन्हें उप्र में भेजा गया है ताकि भाजपा के मिशन 2022 को रफ्तार दी जा सके। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर 1988 बैच के आईएएस रहे हैं। 1995 में उन्होंने मेहसाणा की कमान संभाली, जिसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए। हालांकि, 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान मिली तब उनकी नजर में एके शर्मा आए। पहले उन्हें सरदार सरोवर के प्रोजेक्ट से जोड़ा गया, फिर वो सीएमओ आ गए। कच्छ में आए भूकंप के बाद उसे संवारने का जिम्मा भी एके शर्मा को मिला। इसके अलावा गुजरात के आर्थिक मामले जैसे वाइब्रेंट गुजरात के जरिए इन्वेस्ट लाने पर भी एके शर्मा ने जोर दिया। यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एके शर्मा का भरोसा बढ़ता चला गया। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से राजधानी दिल्ली आए, तो एके शर्मा को भी यहां बुला लिया।

अरुणाचल फॉर्मूले का भय

बिहार में भाजपा के निरंतर बढ़ते वर्चस्व के बीच अगले कुछ महीनों में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि नीतीश अपने इस कार्यकाल में अपने खोए हुए वजूद को फिर हासिल करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं? भाजपा और जद-यू के बीच बढ़ती खाई को देखकर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2021 में ही मध्यावधि चुनाव के लिए कमर कसने का आव्हान कर दिया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता नीतीश के महागठबंधन में वापसी पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते मुख्यमंत्री भाजपा का साथ छोड़ने को तैयार हों। उनका कहना है कि भाजपा के सामने नीतीश की नहीं चलती। राज्य कांग्रेस के नेताओं ने भी कुछ इसी तरह के सुर अलापे हैं। मतलब साफ है, विधानसभा चुनाव के दो महीने के भीतर विपक्ष में आम राय बन गई कि भाजपा-जदयू की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रही है।

विपक्ष का दावा है कि देर-सवेर, बिहार में भी भाजपा 'अरुणाचल फॉर्मूला' लागू कर सकती है और जद-यू के विधायकों को अपने दल में शामिल कर सरकार पर पूर्ण नियंत्रण कर सकती है। और तो और, वरिष्ठ राजद नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने यह कहकर खलबली मचा दी कि जद-यू के 43 में से 17 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। ये ऐसी परिस्थितियां थीं जिसके लिए नीतीश तैयार नहीं थे। फिर भी, उन्होंने अपनी पार्टी टूटने के तमाम कयासों को बेबुनियाद बताया। वे कहते हैं, कोई भी, किसी प्रकार का जो भी दावा कर कर रहा है, सब बेबुनियाद है। उसमें कोई दम नहीं है। जद-यू के कई नेताओं ने तो इसके बाद यह दावा किया कि राजद के ही तीन दर्जन से ज्यादा विधायक 'खरमास' की समाप्ति यानी मकर संक्रांति के बाद उनके दल में शामिल होने को तैयार हैं। आखिर, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसके बाद ही तय है।

आरोप-प्रत्यारोपों के बावजूद, इसमें दो मत नहीं कि अरुणाचल प्रदेश की राजनीति ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से बिहार में जद-यू और भाजपा के संबंधों पर असर डाला है। हालांकि प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल की घटना का बिहार की गठबंधन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साल के बीतने के पहले ही पटना में आयोजित जद-यू की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी में भाजपा के रवैए के प्रति काफी तल्खी है। इस दौरान, जद-यू के प्रमुख महासचिव केसी त्यागी ने स्वीकार किया कि पार्टी अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों के भाजपा में जाने से बहुत आहत है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों किया?

जद-यू भले ही इसका मतलब तुरंत नहीं निकाल पाई हो, विपक्ष को यह कहने में देर नहीं लगी कि भाजपा का बिहार में अब नीतीश के राजनीतिक वजूद को खत्म करना ही एकमात्र मतलब और मकसद है और ये सारी कवायद इसी रणनीति के तहत हो रही है। दरअसल, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद, जबसे जद-यू एनडीए गठबंधन में पहली बार छोटे भाई की भूमिका में सिमट गई है, नीतीश विपक्ष, खासकर राजद के निशाने पर हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं का कहना है कि नीतीश अब भाजपा के भारी दवाब में हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के उप-मुख्यमंत्री नहीं बनने से लेकर नए साल में नीतीश के करीबी समझे जाने वाले गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी से अल्पसंख्यक विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए जाने तक के प्रशासनिक फैसले को विपक्ष नीतीश की सरकार पर लगातार कमजोर होती पकड़ के रूप में देख रही है। इसलिए, विपक्षी नेता नीतीश को अपनी और बेइज्जती नहीं करवाने और मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर भाजपा विरोध में अपने साथ आने की सलाह दे रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का कहना है कि अगर नीतीश तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो पार्टी उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने को तैयार है।

नीतीश ऐसे आरोपों का जवाब यह कहकर देते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वे यहां तक कहते हैं कि इस बार चुनाव परिणाम के बाद वे तो मुख्यमंत्री बनने को तैयार न थे और यह पद उन्होंने अंततः दबाव में स्वीकारा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने कहा, मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था। एनडीए की बैठक में ही यह कह दिया था। लेकिन सबका बहुत दबाव रहा। बाद में, सुशील मोदी ने नीतीश की इस बात पर मुहर लगाई। वे कहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया था कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, पर हमारे दबाव पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार में बढ़ रही भाजपा की महत्वाकांक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़ी संख्याबल के कारण भाजपा की महत्वाकांक्षा बिहार में बढ़ गई है। इस बार, जद-यू की 43 सीटों के मुकाबले भाजपा को 74 सीटें मिली हैं। इसी कारण नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद उन्हें भाजपा के प्रदेश नेताओं की आलोचनाओं को सुनना पड़ रहा है। हाल में राज्य में अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि होने के बाद भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने नीतीश को गृह विभाग का दायित्व किसी और को सौंपने की नसीहत दे डाली। जाहिर है, भाजपा नीतीश को अब खुली छूट देने का इरादा रखने वाली पार्टी प्रतीत नहीं होती। हाल ही में, भाजपा ने दो नवनियुक्त उप-मुख्यमंत्रियों, तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात के बाद यह खबर आई कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि बिहार के विकास में भाजपा की सहभागिता दिखे।

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

अलग सिंधुदेश!

पाकिस्तान में अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर हालिया हुई रैली में प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने सिंध प्रांत को अलग देश बनाने की मांग के मामले में विश्व के नेताओं से दखल देने की अपील की है। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापक जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर इस रैली का आयोजन हुआ था। पाकिस्तान बनने के समय से ही एक अस्थिर देश रहा है। बांग्लादेश का विभाजन इसका सबसे मुफीद उदाहरण है। आइए एक नजर डालते हैं, सिंध प्रांत में हुई हालिया रैली और पाकिस्तान में आंतरिक तौर पर बढ़ते असंतोष पर।

भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के लिए समस्याएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। दुनियाभर के कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अगर आपको आने वाले कुछ वर्षों में गृह युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे, तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी भाषा बनाने की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान में अलगाववाद के बीज पनपने लगे थे। लोगों पर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपी गई। बांग्लाभाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान इसी फैसले के चलते अब अलग देश बनकर बांग्लादेश के रूप में आपके सामने है। वहीं, पाकिस्तान में अगस्त, 1947 के बाद से अब तक बनीं सभी सरकारों ने मानवाधिकारों को एक अलग खूंटी पर टांग दिया। बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हो या बलूचिस्तान या फिर सिंधु प्रांत की। पाकिस्तानी सरकारों ने इन सभी जगहों से उठने वाली आवाजों का वर्षों से दमन किया है। पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट करीमा बलोच की कनाडा में हुई हत्या इसका एक ताजा उदाहरण है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऐसे ही कई लोगों को पहले भी खामोश कर चुकी है। पाकिस्तान में अपने अधिकारों की मांग को लेकर उठने वाली हर आवाज करीमा बलोच की तरह ही दबा दी जाती है।

पाकिस्तान में अलग सिंधुदेश की मांग 1967 से ही चलती आ रही है। 1967 में जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रशदी के नेतृत्व में सिंधियों के लिए एक अलग सिंधुदेश की मांग शुरू हुई थी। इसमें सिंधी हिंदू और सिंधी मुस्लिम दोनों शामिल हुए। फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। पाकिस्तान की कुल हिंदू आबादी का करीब 95 फीसदी सिंध प्रांत में हैं। पाकिस्तान के उत्पीड़न से त्रस्त इन लोगों ने अब वैश्विक नेताओं से गुहार लगाई है। वहीं, प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने के पीछे एक बड़ी वजह है। कश्मीर की स्थिति को लेकर हुई एक सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा था कि समय आ गया है, अब पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। मोदी के इस बयान के चलते बलोच आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में काफी तवज्जो मिली थी। इसके बाद 2016 में भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान, गिलगित और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का आभार व्यक्त किया था। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में जुल्मो-सितम झेल रहे इन हिस्सों के लोगों ने उनकी आवाज उठाने के लिए मोदी को सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया था।

17 जनवरी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमसोरो जिले में जीएम सैयद के गृहनगर सान कस्बे में हुई रैली में लोगों ने आजादी के लिए नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सीधे तौर पर कहा- सिंध, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया था। अलग सिंधुदेश की मांग को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर उठाया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ने सिंध प्रांत पर जबरन कब्जा कर रखा है। साथ ही पाकिस्तान संसाधनों का दोहन और मानवाधिकारों के जमकर उल्लंघन करता है। जिए सिंध मुत्ताहिदा महाज के चेयरमैन मोहम्मद बरफात ने कहा कि हमारी संस्कृति और इतिहास पर हुए दशकों से जारी हमलों के बावजूद हमने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बचाकर रखा है। हम आज भी बहुलतावादी, सहिष्णु और सौहार्दपूर्ण समाज हैं, जो मानव सभ्यता को बचाकर रखे हुए हैं। बरफात का कहना है कि सिंधी समाज के कई लोगों को पंजाबी वर्चस्व वाली पाकिस्तानी फौज ने जेलों में डाल दिया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ने लगा असंतोष

पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही बलूचिस्तान, गिलगित और पाक अधिकृत कश्मीर में असंतोष बढ़ने लगा था। पाकिस्तानी हुकूमत पर पंजाबी वर्ग के वर्चस्व से लेकर मानवाधिकारों के उल्लंघन तक पाक के नापाक इरादों की एक लंबी दास्तान है। इन सबके बीच अब चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के चलते भी पाक में भारी अंसतोष फैल रहा है। सीपीईसी निर्माण के कारण पाकिस्तानी फौज का स्थानीय लोगों पर अत्याचार काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के इन हिस्सों की आवाम अब खुलकर अपना विरोध दर्शा रही है। बीते कुछ वर्षों में भारत की वर्तमान मोदी सरकार पर इन लोगों का भरोसा बढ़ा है। ऐसे में अलगाववादी रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आने से पाकिस्तान की पेशानी पर फिर से बल पड़ सकते हैं।

चुनौतियों भरा ताज

अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने इसलिए कांटों का ताज पहना है, क्योंकि उनके सामने जितनी गंभीर चुनौतियां घरेलू मोर्चे पर हैं, उतनी ही अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी। उन्हें एक ओर जहां बुरी तरह विभाजित अमेरिकी समाज को एकजुट करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय साख को फिर से बहाल भी करना है। ये दोनों ही काम आसान नहीं। भले ही ट्रंप पराजित हो गए हों, लेकिन उनकी सोच को सही मानने वालों की कमी नहीं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की पराजय का यह मतलब नहीं कि वह जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका भी पराभव हो गया है। जिस तरह इस पर निगाहें रहेंगी कि बाइडेन अमेरिकी समाज की बीच की खाई को पाटने क्या कदम उठाते हैं, उसी तरह इस पर भी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में उनकी पहल से विश्व व्यवस्था क्या आकार लेती है? यह तो तय है कि वह जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप से भिन्न रवैया अपनाएंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अन्य वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका के अलगाव को खत्म करेंगे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह संयुक्त राष्ट्र में सुधार कर उसे प्रभावी बनाने की कोई ठोस पहल कर सकेंगे या नहीं? इस सवाल के जवाब में यह भी देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का वह किस हद तक समर्थन करते हैं?

नि:संदेह इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि बाइडेन के दौर में अमेरिका से भारत के संबंध और सुधरेंगे। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि आज भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है, उतनी ही अमेरिका को भारत की भी है। इसके बाद भी यह स्पष्ट नहीं कि रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद जैसे मसलों पर बाइडेन प्रशासन क्या रवैया अपनाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में भी अमेरिका के नए प्रशासन की नीति पर भारत की पैनी निगाहें रहेंगी। ऐसी ही निगाहें पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी रहेंगी। भारत के साथ-साथ दुनिया की निगाहें इस पर खास तौर पर रहेंगी कि बाइडेन बेलगाम चीन पर लगाम लगाने के लिए क्या करते हैं? चीन न केवल विश्व व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, बल्कि वह अमेरिका को तगड़ी चुनौती भी दे रहा है। यदि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका महामारी कोविड-19 पर गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से आपराधिक रवैया अपनाने वाले बिगड़ैल चीन की लगाम कसने के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं करते तो अमेरिका के लिए अपना प्रभुत्व कायम रखना कठिन होगा। एक बेहतर दुनिया के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका लोकतांत्रिक शक्तियों को संबल प्रदान करता रहे।

हाल की घटनाओं ने दुनिया में अमेरिका की छवि धूमिल की है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी समाज जिस तरह से बंटा है और नस्लवाद की खाई चौड़ी हुई है, अमेरिका के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। जो देश दुनिया को लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार जैसे उपदेश देता है, उसी देश में अश्वेतों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, यह दुनिया देख रही है। ऐसे में बाइडेन के समक्ष घरेलू मोर्चे पर बड़ी चुनौती अश्वेत समुदाय के प्रति पनप रही घृणा को खत्म करना है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के निर्माण में अश्वेतों की भूमिका श्वेतों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी रही है। पिछले एक साल में कोरोना महामारी ने अमेरिका को हर तरह से तोड़कर रख दिया है। कोरोना से निपटने में ट्रंप ने जिस तरह का लापरवाही भरा रवैया दिखाया, उसका खमियाजा अमेरिकी आज भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हाल में है, बेरोजगारी चरम पर है और अमेरिकी उद्योग-धंधे संरक्षण मांग रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को जिस तरह बर्बाद किया है, उससे पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। वैश्विक मोर्चे पर चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे संकट भी बाइडेन को विरासत में मिले हैं। अगर अमेरिका ने इन दोनों देशों के प्रति विवेकपूर्ण और तार्किक नीति नहीं अपनाई तो संकट और ज्यादा बढ़ेगा।

भारत को लेकर बाइडेन ने हालांकि सकारात्मक रुख ही दिखाया है। ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई थी, खासतौर से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र कारोबारी समझौते हुए। तीन बड़े रक्षा करार भी हो चुके हैं और अरबों डॉलर के हथियार सौदे प्रक्रिया में हैं। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार को लेकर समय-समय पर ट्रंप भारत को आंखें दिखाने से बाज नहीं आए और तरजीह व्यापार व्यवस्था से भारत को बाहर कर दिया। इसलिए अब कारोबार और रणनीतिक समझौतों में बाइडेन प्रशासन का क्या रुख रहेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।

● **कुमार विनोद**

भारत-अमेरिकी सहयोग बढ़ाने का प्रयास

अमेरिका में जो बाइडेन के पद संभालने के साथ ही देश को पहले नंबर पर लाने की कोशिश होगी। अपनी प्राथमिकताओं में बाइडेन ने कोरोना-19 की महामारी से निपटने की पुरजोर कोशिश करने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने डेढ़ महीने पहले ही विशेषज्ञों का दस्ता भी नियुक्त कर दिया था। उन्होंने यह भी साफ किया कि पिछली सरकार के विभिन्न फैसलों को गुण-दोष के आधार पर परखा जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि नई डेमोक्रेटिक सरकार भारत के साथ हुए विभिन्न समझौतों पर कोई आंच नहीं आने देगी। इसकी वजह है कि भारत-अमेरिकी संबंधों का दायरा वैश्विक रणनीति का रहा है। भारत के साथ हुए अमेरिकी समझौते न केवल रक्षा, बल्कि तकनीक, व्यापार, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों से भी संबंधित हैं। भावी समय के साथ अमेरिकी नीतियों के तहत हुए ये समझौते दोनों देशों और उनके नागरिकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच सामरिक, वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर भी राय-मशविरा हुआ है। भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाने का विरोध उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहले ही कर चुकी हैं। जाहिर है, कश्मीर को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंध सहज नहीं होंगे। बाइडेन को अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन चीन और रूस के साथ वे कैसे शक्ति संतुलन बना पाते हैं, यही उनके कौशल की परीक्षा भी होगी।

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5

Email : shbpl@rediffmail.com Fax : +91-0755-4257687

PH. : +91-0755-4241102, 4257687

शराब अच्छी या बुरी?

चतुरमल को वर्षों बाद संतान सुख प्राप्त हुआ, वो भी जुड़वां बेटों के रूप में। उन्होंने एक शानदार कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया। मांस, मदिरा से दस फीट दूर रहने वाले आलोक को भी मजबूरीवश शामिल होना पड़ा, चतुरमल से घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों के चलते। पार्टी में पहुंचकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक परिचित पहलवान के सामने की खाली कुर्सी देखकर वहां जा बैठा। वेटर के आने पर एक थम्स अप, भुनी मूंगफली और दो सिंधी मसाला पापड़ का ऑर्डर दिया। पहलवान ने अचरज भरी नजरों से आलोक को देखकर कहा, मेरी तरह मुफ्त की व्हिस्की पीने और मांसाहार खाने के बदले ये क्या घास-फूस और मीठे पानी का ऑर्डर दिया है।

हमारा परिवार शाकाहारी है। हमारी पीढ़ियों में वर्षों से किसी ने शराब को छुआ तक नहीं है। आलोक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद जब पहलवान को शराब चढ़ गई तो आलोक से फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, शराब पीना अच्छी बात है या बुरी? पहलवान द्वारा अचानक दागा गया सवाल सुनकर आलोक सकपका गया। खुद को कोसने लगा कि इस पहलवान के सामने बैठने की बेवकूफी क्यों की? खैर, जवाब तो देना ही था। मेरे जवाब से

पहलवान असंतुष्ट हुए और मुझे यहीं चारों खाने चित्त कर दिया तो? यही सोचकर वो कांप उठा। मन ही मन में सारे देवी-देवताओं का स्मरण करने लगा। प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि ऐसी सद्बुद्धि दे, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आखिरकार थोड़ा सोचकर, हिम्मत जुटाते हुए कहा, जो पिए उसके लिए अच्छी, जो न पिए उसके लिए बुरी बात है। आलोक का जवाब सुनकर पहलवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैलने लगी। आलोक ने संतोष की सांस ली। उसे वो कहावत याद आई, जान बची तो लाखों पाए।

– **अनाम**

एक अकेला

सेवानिवृत्त अध्यापक आलोकराम हर मौसम में अपने साथ छाता लिए बिना घर से बाहर के लिए नहीं निकलते। छाता और आलोकराम मानो एक-दूसरे के पूरक बन चुके थे। पीठ पीछे कुछ लोग उन्हें छाताराम, छतरीवाला, अम्ब्रेला मैन आदि कहकर कटाक्ष करते थे। इसके बारे में उनके घनिष्ठ मित्र चतुरमल ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कहने लगे, 'देखो भाई, लोगों द्वारा पीठ पीछे खिल्ली उड़ाने के कारण मैं अपने सेहत से समझौता नहीं कर सकता। धूप में बिना छाते के घूमने पर लू लगने का खतरा होता है। बारिश के मौसम में सर्दी-जुकाम होने की संभावना बनी रहती है। लोगों की परवाह किए बिना अपनी पसंद की वेशभूषा पहनना, घूमना-फिरना और रहना चाहिए।' आलोकराम के तर्क के आगे चतुरमल ने हार मान ली। आलोकराम ने एक शादी में शामिल होने के लिए नए कपड़े पहने। छाता लेकर घर से निकलते समय उनकी पत्नी शांति ने उन्हें टोकते-रोकते हुए कहा, नए परिधान के साथ पुराना छाता टाट में पैबंद समान लगता है। अब तो बरसात का मौसम भी नहीं है। आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। नवंबर-दिसंबर और मार्च अप्रैल में भी पानी गिरते देखा है। आलोकराम ने पत्नी को जवाब दिया और प्रतिक्रिया जाने बिना घर से निकल पड़े।

आलोकराम को विवाह समारोह में पीठ पीछे यूं छाता लटकाए देखकर कुछ लोग मुस्कुराए। कईयों ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। आलोकराम आमंत्रित से मिले। वर-वधू को आशीर्वाद दिया। भोजन किया। इतने में बरखा रानी बरसने लगी। जो लोग कार में आए थे, वे सब निश्चिंत दिखे। बाकी लोगों के पास बरसात थमने की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्माराम ने अपना छाता खोला और बेफिक्र होकर चल पड़े अपने घर की ओर।

– **अशोक वाधवाणी**

सुबह छपा अखबार में...

बस्ती-बस्ती में मैं घूमा,
सुबह छपा अखबार में।
कहीं प्रशंसा, तो मिली
कहीं पर गालियां,
कहीं चना तो मिली
कहीं पर रोटियां,
जैसे-तैसे राह गुजारी
नहीं गया दरबार में
भारत माता की पूजा ही,
है मेरे आधार में
बस्ती-बस्ती में मैं घूमा,
सुबह छपा अखबार में।।1।।
नींद बेंचकर स्वप्न खरीदा,
स्वप्न बेंचकर राहें
सौदा कोई काम न आया,
भरते अपनी बाहें
बिना थके ही रोज उठा
अपने ही मसान में,
अर्थी कोई नहीं उठाया,
मैं ठहरा श्मशान में
बस्ती-बस्ती में मैं घूमा,
सुबह छपा अखबार में।।2।।
कोई मिला तो प्रेम दिया,
कोई ने तो घाव दिया
जिसके जीवन में जो था,
उसने वैसा भाव दिया
डगर-डगर में मैं गाया,
जीवन के सोपान में
अपना कोई नहीं मिला,
छला गया बाजार में
बस्ती-बस्ती में मैं घूमा,
सुबह छपा अखबार में।।3।।
जिनको मैं अपना समझा,
वो तो वीराने निकले
जिनको केवल कभी दिखा
वो ही अपने निकले
प्रत्यक्ष की तो बाते छोड़ो,
नहीं मिले दूरभाष में
कैसे-कैसे लोग बसे हैं,
इस रंगीले संसार में
बस्ती-बस्ती में मैं घूमा,
सुबह छपा अखबार में।।4।।

– **अनाम**

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजेय समझे जाने ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम की धमाकेदार जीत का डंका क्रिकेटप्रेमी दुनिया में बज रहा है। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली। लेकिन इस जीत में सबसे काबिले गौर रहा युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। वो खिलाड़ी जिनके जीवन संघर्ष का फल उन्हें एक मैच से ही मिल गया। ये युवा खिलाड़ी जिस बैकग्राउंड से संघर्ष करते हुए आज देश के हीरो बने हैं, उनकी कहानी जानना प्रेरणादायक होगा।

'गाबा के गब्बर'

आधुनिक भारत क्या कर सकता है, इसकी एक बानगी ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में देखने को मिली जब भारतीय क्रिकेट टीम ने तीन विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही जमीन पर 2-1 से हरा दिया और भारत ने सारीज जीत ली। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह इस वक्त क्रिकेट में बेताज बादशाह है। यह मैच कई मायनों में भारतीय क्रिकेट में याद किया जाएगा। इस मैच में भारत के 6 बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। कप्तान विराट कोहली टीम में नहीं थे। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की। इसके अलावा टीम के पांचों बड़े गेंदबाज चोट की वजह से टीम से बाहर थे। दुनिया के दो सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मुहम्मद शमी अहमद टीम में नहीं थे। भारत के सबसे बेहतरीन दो स्पिन गेंदबाज अश्विन और जडेजा भी चोट की वजह से ये मैच नहीं खेल पाए। साथ ही गेंदबाज उमेश यादव भी चोट खा बाहर बैठे थे। यानी गेंदबाजी उनके हाथों में थी जिन्होंने कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में दस से अधिक विकेट नहीं लिए थे। फिर भी शिराज, सुंदर, शार्दूल और सैनी ने जान लगा दी, भारत को निराश नहीं किया और यह महसूस नहीं होने दिया कि भारत की पहली पसंद के पांच बड़े गेंदबाज टीम में नहीं हैं। यह सबूत है कि भारतीय टीम आज किस मुकाम पर है और नए खिलाड़ी जल्द हार मानने को तैयार नहीं हैं।

इस मैच में ऋषभ पंत की शानदार 89 रन की बल्लेबाजी हमेशा याद की जाएगी। साथ ही अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे शुभमन गिल के 91 रन भी लंबे समय तक याद किए जाएंगे। पंत के टैलेंट के बारे में कभी भी किसी को शक नहीं था पर उनके टेंपरामेंट पर गहरे सवाल खड़े होते रहे। एक विकेटकीपर के तौर पर उनका प्रदर्शन हमेशा कमजोर रहा, पर लगातार दो मैचों में शानदार पारी खेल उन्होंने साबित कर दिया कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी वह टीम में जगह बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंत और गिल ने कोहली की अनुपस्थिति में जिम्मेदारी ली और दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं।

इस मैच की दूसरी पारी में शिराज ने पांच विकेट लिए और बुमराह और शमी की कमी कभी भी नहीं खलने दी। तीसरे मैच में अश्विन और विहारी ने जिस तरह से मैच बचाया वह काबिले तारीफ था। इसी तरह से ब्रिस्बेन की पहली पारी में सुंदर और शार्दूल ने गेंदबाज होते हुए जो शानदार बल्लेबाजी की वह गजब थी। पुजारा हमेशा की तरह चट्टान की तरह अड़े रहे। पर एक आदमी की तारीफ के बगैर यह कहानी अधूरी रहेगी। वह है कप्तान अजिंक्य रहाणे। पहले टेस्ट में भारत की टीम 36 रन पर आउट हो गई थी। जो भारत के इतिहास का सबसे कम और टीम का शर्मनाक स्कोर था। फिर कप्तान कोहली भारत वापस आ गए और किसी ने यह नहीं सोचा था कि अब भारत बेहद शर्मनाक हार का सामना नहीं कर वापस लौटेगा। पर दूसरा टेस्ट भारत जीता और तीसरा टेस्ट हारते-हारते भारत ने जोरदार ड्रॉ किया और चौथे में भारत की युवा टीम ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। इस मैदान पर 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया हारा है। वह भी चौथी पारी में 300 से अधिक रन बनने के कारण। इस दौरान रहाणे ने टीम को कप्तान कोहली और 36 रन के शर्म के बाद बिखरने नहीं दिया। टीम को जोड़कर रखा और नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और दिखा दिया कि कप्तानी शोमैनशिप नहीं है, वह शांत रहते हुए आक्रामक तरीके से की जा सकती है।

सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पर पटकनी देना। भारत के बारे में यह बार-बार कहा जाता है कि वह अपनी पिचों पर शेर रहता है और विदेशी पिचों पर ढेर हो जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में भारत सीरीज अगर बराबर भी कर लेता तो एक उपलब्धि होती। सीरीज जीतना एक कमाल है। एक जमाना था जब भारत के बारे में कहा जाता था कि वह हार बचाने के लिए खेलता था। सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भारत को जीतना सिखाया। सचिन और सौरव ने कहा कि भारत को हराना मुश्किल है लेकिन धोनी ने सही मायने में भारत को विश्व विजेता बनाया। कोहली ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन यह तब होता था जब भारत के सभी दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे।

यह पहली बार है जब आधे से अधिक दिग्गज टीम में नहीं थे और जिन्हें नौसिखिया कहा जाता था, जो नेट बॉलर के तौर पर टीम में थे, उन्होंने दिग्गजों की कमी खलने नहीं दी और भारत का गौरव बढ़ाया। यह अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। यह जीत युवा भारत की है। नए आत्मविश्वासी भारत की जीत है।

● आशीष नेमा

पेरेंट्स की शादी से पहले हो गया था श्रुति हासन का जन्म

पिता की गर्लफ्रेंड से दोस्ती करने पर मां ने बंद कर दी थी बातचीत

साउथ और बॉलीवुड अभिनेत्री श्रुति हासन 35 साल की हो गई हैं। 28 जनवरी, 1986 को उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। श्रुति ने 1999 में अपना कैरियर शुरू किया था। वह साउथ इंडियन सिनेमा की लीडिंग अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। श्रुति ने डी-डे, रमैय्या वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक, रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों में काम किया है। वह शॉर्ट फिल्म देवी में भी नजर आई थीं।

स्कूल में रखा था फेक नाम

खबरों के मुताबिक, श्रुति जब स्कूल में थीं तो उन्होंने अपना असली नाम छुपाकर एक फेक नाम से स्कूल में पढ़ाई की थी ताकि किसी को ये ना मालूम चले कि वो कमल हासन और सारिका की बेटी हैं। उन्होंने अपना नाम पूजा रामचंद्रन रखा था ताकि किसी को ना पता चले कि वो फिल्मी फैमिली से हैं। श्रुति की प्रारंभिक स्कूलिंग लेडी अंदल स्कूल, चेन्नई से हुई है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट एंड्रू कॉलेज से साइकोलाजी में डिग्री हासिल की। संगीत में रूचि के चलते श्रुति ने अमेरिका के कैलिफोर्निया का रुख किया और वहां के म्यूजिशियंस इंस्टिट्यूट से म्यूजिक की पढ़ाई की और फिर चेन्नई लौट आईं।

पेरेंट्स की शादी से पहले हुआ था जन्म

श्रुति कमल हासन और सारिका जैसे दिग्गज एक्टर्स की बेटी हैं। उनका जन्म उनके माता-पिता की शादी से पहले ही हो गया था। दरअसल, शादी से पहले कमल हासन और सारिका लिव इन में रहते थे। इसी दौरान सारिका प्रेग्नेंट हो गईं और 1986 में श्रुति को जन्म देने के दो साल बाद उन्होंने 1988 में कमल हासन से शादी कर ली। कमल हासन और सारिका की शादी नहीं टिकी और 2004 में दोनों का तलाक हो गया।

बाजीगर में सीन के दौरान काजोल नहीं दे पा रही थीं सही एक्सप्रेशन

शाहरुख खान और काजोल बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन ऑन-स्क्रीन कपल के तौर पर मशहूर हैं। उनकी जोड़ी 1993 में आई अब्बास-मस्तान की फिल्म बाजीगर से मशहूर हुई थी। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शाहरुख ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में सुनाया था जिसका वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख बता रहे हैं की एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के समय क्या-क्या हुआ था?

शाहरुख ने किया था काजोल को पिंच

शाहरुख वीडियो में बताते हैं, फिल्म के टाइटल सॉन्ग बाजीगर ओ बाजीगर की कुछ लाइन्स थीं-मेरा दिल था अकेले तूने खेल ऐसा खेला। इन लाइनों पर काजोल को कुछ सेंशुअस एक्सप्रेशन देने थे जो उनसे नहीं हो पा रहा था। फिर कोरियोग्राफर ने मुझसे कहा, तुम उसको ऐसा कुछ पिंच-विंच कर दो। फिर मैंने वैसा ही किया और शॉट ओके हो गया।

फ्लॉप कैरियर और फिल्में ना मिलने से शराबी बन गए थे बॉबी देओल

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने साल 1995 में आई फिल्म बरसात से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देशभर में पहचान और फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड मिला। शुरुआती कैरियर में बेहतरीन फिल्मों में नजर आए एक्टर को कुछ ही समय बाद साइड रोल मिलने लगे। अच्छे ऑफर ना मिलने से बॉबी काफी परेशान रहने लगे और शराब की गिरफ्त में पड़ गए।

काम ना मिलने पर लिया नशे का सहारा

बॉबी देओल को बॉलीवुड फिल्मों के अच्छे ऑफर मिलने बंद हो गए थे। इस बात से एक्टर परेशान रहने लगे और नशे में डूबने लगे। एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझमें क्या कमी है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। उसके बाद मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को सबसे दूर कर लिया था।

कुछ साहसी बापों में इतना साहस होता है कि वे खुलकर दहेज की मांग करते हैं। वे न किसी कानून से और न कानून के बाप से डरते हैं। कुछ दब्बू और डरपोक टाइप के आदर्श बाप अपनी सहधर्मिणी को आगे बढ़ा देते हैं कि जो भी कहना, मांगना है, तू ही मांगना, कहना।

मैं दहेज़ हूँ!

आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते-पहचानते हैं। प्राय: लोग मुझे 'दहेज' के नाम से जानते हैं। दहेज एक ऐसी संपत्ति है, जिसे विवाह के समय, पहले अथवा बाद में लड़की वाले द्वारा लड़के वाले को दिया जाता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, कि लड़के वाले द्वारा लड़की वाले से उसकी इच्छा या अनिच्छापूर्वक धन अथवा सामग्री अथवा दोनों रूपों में ले लिया जाता है।

वैसे तो मेरा जन्म सादी (शादी) के अवसर के लिए हुआ है। नाम तो सादी है, पर ये केवल कोरे आदर्श और दिखावे की बात ही है। शादी के साथ बर्बादी और आबादी का बहुत करीब का रिश्ता है। मानव समाज में आदर्श और व्यवहार में मीलों का अंतर है। यहां दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, पास में आने पर वे कानों में चुभते हुए शोर बन जाते हैं। यहां कभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। बड़े-बड़े आदर्शों की बातें कही जाती हैं, पर उन पर चलता कोई भी नहीं है। ढोल में पोल की तरह सब जगह पोल ही पोल है। इस मामले में धरती गोल है। आदमी की बातों में जितना झोल है, उतना कहीं भी नहीं।

कुछ साहसी बापों में इतना साहस होता है कि वे खुलकर दहेज की मांग करते हैं। वे न किसी कानून से और न कानून के बाप से डरते हैं। कुछ दब्बू और डरपोक टाइप के आदर्श बाप अपनी सहधर्मिणी को आगे बढ़ा देते हैं कि जो भी कहना, मांगना है, तू ही मांगना, कहना। इससे मेरी नाक भी बच जाएगी और बगुले जैसी गर्दन उठाकर भरी सभा में कह सकूंगा कि देखिए मैंने तो कोई दहेज की मांग नहीं की। सहधर्मिणी चूंकि अर्धांगिनी भी है, इसलिए पति का आधा अंग होने के कारण पूरा जिम्मा ले लेती है, आप कुछ मत कहना, मैं सब निपट लूंगी। और वे निपट भी लेती हैं। इसीलिए तो 'नारी आरी नारि की' कहा गया है। पतिदेव पर्दे में बैठे पुजते रहते हैं। ससुरजी तो बहुत अच्छे हैं, सास बड़ी खंट है। दहेज एक भिक्षा है, जिसे प्राप्त करने के लिए और भी उपाय किए जाते हैं। इस कार्य के लिए बिचौलियों या मध्यस्थों को भी नियुक्त किया जाता है, कि भई! तुम्हीं दहेज की बात करना, हम तो मौन ही रहेंगे। इससे हमारी नाक भी तनी, बनी, घनी रहेगी और हम खुलकर कह सकेंगे कि लड़की वालों ने स्वयं ही अपनी इच्छा से दिया है, हमने तो एक पैसे की भी मांग नहीं की थी।

बिना कमाया, मुफ्त में आया धन किसे अच्छा नहीं लगता? इसलिए चोर के द्वारा चुराया हुआ गुड़ खरीदे हुए गुड़ से अधिक मीठा होता है। फिर मैं दहेज नाम धारी मुफ्त का धन भला किसे मीठा नहीं लगूंगा। अनिच्छा पूर्वक लिया हुआ, दवाब बनाकर हथिया लिया गया दहेज किसे और कैसे प्रिय नहीं होगा। लोग कहते हैं कि दहेज से बहू की सुंदरता, महत्व और गुणवत्ता में चार नहीं चौदह चांद लग जाते हैं। सास के द्वारा बहू की सांस बंद न कर दी जाए, उसके लिए सेफ्टी वाल्व का काम मैं ही तो करता हूं। ग्रहस्थी रूपी प्रेशर कुकर का शानदार, जानदार सुरक्षा वाल्व!

जिनके घर में पुत्रों ने जन्म लिया है, वे सौभाग्यशाली हैं। पर पुत्री जन्मदाताओं ने मानों कोई अपराध किया हो। एक ओर जिस समाज में 'लड़का-लड़की एक समान' के खोखले नारे लगाए जाते हैं, इससे बड़ा झूठ और अत्याचार हो ही नहीं सकता, जिसके विरोध में हजार कानून बनाए जाएं, वहां उसका एक प्रतिशत भी अनुपालन नहीं हो, इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है? यह मेरे प्रति भी अन्याय की पराकाष्ठा है। इस अन्याय में पूत के पिता-माता की अन्य आय जो कबड्डी खेल रही है।

इसे भला कौन ठुकरा सकता है! मजे की बात ये है कि सब मुझे बुरा कहते हैं, परंतु हृदय से अपनाते हैं। ये एक सोची-समझी साजिश और विषम विडम्बना का मजबूत उदाहरण है। मानव के खोखलेपन के ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलेंगे। लड़की के पिता की कन्या को ब्याहने की मजबूरी का लाभ लेने वाला दूल्हे के बाप की खुशी का मीटर कितना ऊपर चढ़ जाता है, इसे कोई दहेज पिशाच ही समझ सकता है। मेरी कोई जमीन हो या न हो, पर मेरा आकाश अछोर है, जिसकी कोई सांझ हो, पर नहीं इसका कहीं भोर है। आदमी ने मुझे पैदा किया, उसमें मेरा क्या दोष! बताए देता हूं मुझ पर नहीं दिखाए कोई रोष! दुरुस्त कर ले पहले अपने होश! लड़के वालों का बना दिया मुझे अक्षय कोश, लड़की की सासु मां का मन का तोष, भले सूख जाए पुत्री के पिता का गोश्त। मेरा नहीं कहीं भी कोई दोस्त।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

आइये, इस गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों की सहभागिता की सुदृढ़ बुनियाद पर हम
ऐसे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लें, जो देश में समानता, सद्भाव और सबसे तेज प्रगति की मिसाल बने।

देश के लिए बलिदान होने वाले वीर सपूतों को शत्-शत् नमन।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

आत्मनिर्भर हों जन-जन
नवचेतना नवऊर्जा का
गणतंत्र

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

खुशहाल जीवन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम...

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जारी। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य। नीति आयोग ने की इस पहल की प्रशंसा।
- मनरेगा योजना में अब तक 86 लाख 37 हजार मजदूरों को रोज़गार, इनमें 36 लाख 87 हजार महिलाएं। प्रतिदिन लगभग 20 लाख श्रमिकों का नियोजन। देशभर में सर्वाधिक।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम।
- कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का "मोस्ट इम्प्रूव्ड" राज्य।
- सुशासन को मूर्तरूप देने के लिए एकल नागरिक डेटाबेस।
- कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू।
- मिलावटखोरी अब संज्ञेय अपराध।
- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना शुरू, 21 राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों पर राशन उपलब्ध।
- 781 करोड़ की अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना का क्रियान्वयन।
- प्रदेश के इतिहास में 2789.55 लाख यूनिट बिजली सप्लाई का नया रिकार्ड।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कैबिनेट का गठन।
- ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य (Historical Urban Landscape) की ग्लोबल रिकमेन्डेशन योजना के तहत चयनित।
- शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में स्मारक निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर।
- धार्मिक स्वातंत्र्य अब बना कानून।

HEIDELBERGCEMENT

148 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 148 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

तकनीकी एवं व्यावसायिक जानकारी के लिए संपर्क करें

भोपाल: 9425602721, 9719344555, मुज़फ्फरपुर: 8417000136,
लखनऊ: 9560512211, 9559136323, आगरा: 7705903227, 9425007436

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.org.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in